राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 189

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 17 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जामिया पर ट्वीट को लेकर घिरे अक्षय, देनी पड़ी सफाई

>> 5

हिंसा रुकने पर होगी सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

तीखे तेवर ▶ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया विवि छात्रों के हिंसक आंदोलन पर तल्ख टिप्पणी

सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं, आज सुनवाई को हुआ राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को गंभीरता से लिया है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग पर सख्त लहजे में कहा कि पहले हिंसा रुकनी चाहिए। अगर हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जारी रहा तो सुनवाई नहीं की जाएगी। बाद में मंगलवार को मामले पर सुनवाई को राजी होते हुए कोर्ट ने कहा कि हम अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, लेकिन इस माहौल में सुनवाई नहीं हो सकती।

ये सख्त टिप्पणियां सोमवार सुबह प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने उस वक्त कीं जब वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह और कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट से जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में पुलिस अत्याचार पर स्वतः संज्ञान लेने और छात्रों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की। जयसिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का भी मामला उठाया। इन वकीलों ने जस्टिस बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के बैठते ही मामले का जिक्र करते हुए तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर दखल देने की मांग की। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह यह सब करेंगे। लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, लेकिन पहले हिंसा रुकनी चाहिए। ऐसे माहौल में सुनवाई नहीं हो सकती। जब हिंसा हो रही है तो पुलिस को क्या करना चाहिए, इस पर जयसिंह ने कहा कि हिंसा छात्रों ने नहीं की है। यह पुलिस की गढ़ी कहानी है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप क्या कह रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बसों को आग लगाई जा रही है। हम यह नहीं कह रहे कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन यह रुकना चाहिए। इसके रुकने के बाद ही ठंडे दिमाग से मामले पर विचार हो सकता है। कोर्ट देखेगा कि क्या किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है।

जब कोर्ट यह कह रहा था कि तभी कई वकीलों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। कुछ वकील कोर्ट को घटना का वीडियो दिखाना चाहते थे। कुछ तत्काल पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप कोर्ट पर इस तरह दबाव नहीं बना सकते। सिर्फ आपकी बातों को सुनकर आदेश नहीं दिया जा सकता। जो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहते हैं करें, लेकिन कोर्ट इस तरह सुनवाई नहीं कर सकता।

इंद्रा जयसिंह ने कहा कि वकीलों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, इसी तरह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस ने विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर लाइब्रेरी में छात्रों पर अत्याचार किया है। गोंसाल्विस ने कहा कि पुलिस हमले में छात्रों को चोटें आई हैं, उन्हें उचित चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोर्ट को एएमयू के वीसी और जामिया मिल्लिया के प्राक्टर के बयान पर ध्यान देना चाहिए। गोंसाल्विस ने कहा कि कोर्ट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक कमेटी बना दे जो एएमयू जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है। पीठ ने वकीलों से कहा कि वे याचिका दाखिल करें। मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। मालूम हो कि रविवार को जामिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसमे हिंसा हुई थी। पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

संबंधित खबरें पेज>>2-3-5

दिल्ली हाई कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, जासं : जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका सोमवार को ही सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष पेश की गई। पीठ ने इसे सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस पर आपात सुनवाई की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता तारिक खान और अपूर्व सिंघल के माध्यम से अधिवक्ता रिजवान ने यह याचिका दायर की है। जामिया निवासी रिजवान ने दावा किया है कि 15 दिसंबर को जब छात्र और शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर घुस आई और आंसू गैसे के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग की और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया।

नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर उपद्रव जारी, उप्र में भी बढ़ीं घटनाएं

नई दिल्ली : देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर दिल्ली सहित कई स्थानों पर रविवार को हुई हिंसा के बाद सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने लगातार चौथे दिन प्रदर्शन किया। वहीं, उप्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएएमयू) में रविवार को हुई हिंसा के बाद इसकी चिंगारी राजधानी लखनऊ स्थित नदवा कॉलेज होते हुए मऊ तक जा पहुंची। नदवा कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया जबकि मऊ में रोडवेज की बसों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई जिसमें कई यात्री घायल हो गए। मऊ शहर के दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बंगाल में भी हिंसक विरोध-प्रदर्शन जारी है।

सरोकार

आसान शिकार के चक्कर में आलसी हो चले बाघ!

लखीमपुर : जंगल में भरपूर शिकार उपलब्ध होने के बावजूद आबादी का रुख क्यों कर रहे हैं बाघ? व्यवहार में आए बदलाव पर हुआ अध्ययन। जंगली पशुओं का कठिन शिकार करने की जगह आबादी में मिल जाता है आसान शिकार। (पेज-10)

जागरण विशेष

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाएं लोग...

नई दिल्ली : गौतमबुद्ध नगर में खनन माफिया को धूल चटाने वाली आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बन रही है। दुर्गा शक्ति कहती हैं कि इससे आम व्यक्ति को लड़ने की हिम्मत मिले तो खुशी होगी। (पेज-11)

विश्वास.News

घायल बच्ची की तस्वीर का सीएए से कोई लेना-देना नहीं ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 11

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चार माह के भीतर अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर : शाह

गोड्डा : 'अयोध्या में चार माह के भीतर भगवान राम का भव्य गगनचुंबी मंदिर बनेगा। यह दुनिया के सुंदर मंदिरों में एक होगा।' यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहीं। वह सोमवार को झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पाक ने पुंछ से गुरेज तक की भारी गोलाबारी, जवान शहीद

जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को पुंछ से लेकर गुरेज सेक्टर तकभारत के सैन्य व नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक अग्रिम मोर्चा तबाह हो गया और एक अधिकारी व तीन जवान जख्मी हो गए। तीन अन्य लोगों के मारे जाने की भी सूचना है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

'बढ़ते कॉल ड्रॉप के लिए गैरकानूनी बूस्टर्स जिम्मेदार'

नई दिल्ली : कॉल ड्रॉप की परेशानी का हल खोजने में विफल टेलीकॉम कंपनियों ने गैरकानूनी बूस्टर्स और रिपीटर्स को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनियों ने कहा है कि इसी वजह से मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

नाइजीरिया के नजदीकी समुद्र से 20 भारतीय फिर अगवा

नई दिल्ली : एक व्यापारिक जहाज पर सवार 20 भारतीयों का अफ्रीका महाद्वीप में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया है। वाकया नाइजीरिया के नजदीक के समुद्री इलाके में रविवार को घटित हुआ। नाइजीरिया तट के नजदीक से ही दस दिन पहले हांगकांग के जहाज से 18 भारतीयों का अपहरण हुआ था।

नाबालिग से दुष्कर्म में विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव कांड

- तीस हजारी अदालत ने सुनाया फैसला तो रोने लगा सेंगर
- सह आरोपित महिला शशि सिंह संदेह के लाभ में बरी

दुष्कर्म के दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की फाइल फोटो। एएनआइ

पीड़िता का बयान सत्य और बेदाग पाया। उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। वह खतरे में थी और चिंतित थी। वह एक गांव की लड़की है, न कि किसी महानगर की। सेंगर शक्तिशाली व्यक्ति था और इसलिए पीड़िता ने अपना पक्ष रखने में समय लिया।

-न्यायाधीश धर्मेश शर्मा (फैसला सुनाते वक्त की टिप्पणी)

इस केस को लड़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है। यह सच की जीत है और पीड़िता को इंसाफ मिलने की शुरुआत है।

-धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पीड़िता के वकील

हम फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यह केस यहीं खत्म नहीं हो गया है।

-तनवीर अहमद मीर, दोषी के वकील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म मामले में तीस हजारी अदालत ने उत्तर प्रदेश भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। सह आरोपित शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने सजा पर बहस के लिए 19 दिसंबर का दिन तय किया था, लेकिन दोषी के वकील ने मंगलवार को ही बहस करने की अपील की। अदालत ने इसे मान लिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान शशि सिंह रोने लगी और बेहोश हो गई। दोषी करार दिए जाने पर कुलदीप सेंगर भी कोर्ट रूम में रोने लगा।

तीस हजारी अदालत ने जांच में कई पहलुओं पर लापरवाही बरतने के लिए सीबीआइ को लताड़ लगाई, लेकिन इस बात के लिए शाबादी भी दी कि उसने साबित किया कि पीड़िता नाबालिग थी और सेंगर पर पॉक्सो एक्ट के तहत सही केस चलाया गया था। पीड़िता द्वारा उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने के बाद उसके परिवार पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए और उनमें सेंगर की भूमिका भी देखी गई।

इन धाराओं के तहत दोषी : अदालत ने कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सी (लोक सेवक द्वारा बच्चे के खिलाफ भयावह यौन उत्पीड़न) और 6 (जो बच्चे के खिलाफ भयावह यौन उत्पीड़न करे उसे कम से 10 साल और अधिकतम उम्रकैद और जुर्माना अदा करने की सजा) के तहत दोषी करार दिया है।

कुलदीप ने आवास पर किया दुष्कर्म : सीबीआइ के आरोपपत्र के मुताबिक नाबालिग के साथ 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर ने अपने आवास पर दुष्कर्म किया था। शशि सिंह पर आरोप था कि वह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर लेकर गई थी।

रोजाना हुई सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित किया गया। गत 5 अगस्त से इस पर रोजाना सुनवाई हुई। कई बार सरकारी छुट्टी के दिन भी केस सुना गया। यहां तक कि पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए तीन दिन तक एम्स में भी अदालत लगी।

कई मामले अभी विचाराधीन : उन्नाव कांड से जुड़ा सामूहिक दुष्कर्म मामला, पीड़िता के पिता की हत्या और पीड़िता को ट्रक से कुचलने की कोशिश के मामले अभी विचाराधीन हैं।

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 133 दिन में सुनाया अपना फैसला पेज>>6

जनवरी के पहले सप्ताह में होंगी सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं एक से सात जनवरी के बीच आयोजित होंगी। 15 फरवरी से स्किल विषयों की सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। बोर्ड जल्द ही इसके लिए समयसारिणी जारी करेगा। परीक्षाएं लगभग एक महीने के भीतर करा ली जाएंगी। मुख्य विषयों की परीक्षाएं फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। परीक्षा खत्म होने के एक महीने बाद परिणाम भी घोषित होंगे।

बोर्ड के अनुसार, रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की भी योजना है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर्स और मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी है। पिछले तीन वर्षों में सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से 50 दिन पहले डेट शीट जारी कर रहा है। 2017 और 2018 में परीक्षाएं दो या तीन मार्च से शुरू हुई थीं।

हिंसा पर राज्यपाल ने ममता को किया तलब

- जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा-निजी तौर पर हालात से अवगत कराएं सीएम
- मुख्य सचिव व डीजीपी से कोई जानकारी नहीं मिलने से नाराज हैं राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन पर राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से कोई जानकारी नहीं मिलने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ नाराज हैं। सोमवार को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद आकर उन्हें निजी तौर पर राज्य की परिस्थिति से अवगत कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि बुलाए जाने के बावजूद राज्य के दो बड़े अधिकारी उन्हें हालात का जायजा देने नहीं पहुंचे। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण व अवांछनीय बताया।

बता दें राज्यपाल ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को विस्तृत जानकारी के साथ बुलाया था, हालांकि दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया-'राज्य में व्याप्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निजी तौर राज्य के हालात से अवगत कराने को कहा है। वह अपनी सुविधानुसार राजभवन आने का समय चुन सकती हैं। मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।' इधर, राज्य के प्रशासनिक सूत्रों की ओर से कहा गया है कि मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक सही समय पर राज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे।

ममता का विरोध असंवैधानिक : सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली को भी राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। सोमवार सुबह राज्यपाल ने ट्वीट किया-' मैं बेहद दुखी हूं कि सीएम और उनके मंत्री सीएए के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से इस असंवैधानिक और भड़काऊ कृत्य को रोकने की अपील की है क्योंकि इससे हालात बिगड़ेंगे।'

हाई कोर्ट भी सख्त, मांगी रिपोर्ट

बंगाल में पिछले चार दिनों से जारी हिंसा के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा रोकने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई और कानून एवं व्यवस्था कायम करने के संबंध में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट तलब की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से कैसे मना कर सकती है? हिंसा में रेलवे और परिवहन विभाग की नष्ट हुई संपत्ति की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? याचिकाकर्ता ने राज्य में व्याप्त हिंसा को रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। अदालत ने हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तारित रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही 18 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

राज्यों की मांग पूरी, जारी किए गए जीएसटी कंपनसेशन के 35000 करोड़ रुपये

- जीएसटी काउंसिल की बैठक से पूर्व राज्यों को मिला बूस्टर डोज
- बुधवार की बैठक में कंपनसेशन का मुद्दा हावी रहने के थे आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीएसटी काउंसिल की बैठक से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। रेवेन्यू की धीमी रफ्तार की वजह से वित्तीय दिक्कतों से जूझ रहे राज्य इसकी पुरजोर मांग कर रहे थे। बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस मुद्दे के हावी होने की आशंका बन गई थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक, 'केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के मद में 35298 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।' विभिन्न राज्य पिछले कुछ दिनों से केंद्र पर कंपनसेशन के भुगतान का निरंतर दबाव बनाए हुए थे। गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत भी कराया था। राज्यों का कहना था कि भुगतान में हो रही देरी के चलते विकास से संबंधित कार्य बाधित हो रहे हैं।

वित्त मंत्री ने भी कई मंचों से राज्यों को आश्वस्त किया था कि सरकार जल्द ही इस राशि का भुगतान करेगी। सोमवार को भी यह राशि जारी होने से पूर्व वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के भुगतान के वादे से केंद्र नहीं मुकरेगा। उनका कहना था कि कलेक्शन में अपेक्षाकृत तेजी नहीं होने के कारण कंपनसेशन की राशि जारी करने में देरी हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, 'निश्चित ही यह उनका अधिकार है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रही हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम इसे नहीं रोक रहे। राज्यों को इसका भुगतान किया जाएगा।' गैर भाजपा शासित राज्यों की तरफ से कंपनसेशन का मुद्दा जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोर शोर से उठाने की तैयारी थी। इससे काउंसिल की बैठक प्रभावित हो सकती थी। माना जा रहा है कि काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेवेन्यू की धीमी रफ्तार को लेकर ही चर्चा होनी है। राज्यों की तरफ से अधिकारियों की समिति की बैठक में रेवेन्यू बढ़ाने के कई उपाय भी सुझाए गए हैं। हालांकि सूत्रों ने बैठक में दरों में वृद्धि जैसे किसी निर्णय की संभावनाओं से इन्कार किया है।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाने होंगे नए भारतीय सेना प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। वे इस समय 13 लाख जवानों वाली सेना के उप प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति को उच्च स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने इस मामले में वरिष्ठता के नियम का पालन किया है। नरवाने वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की संभावना है।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की फाइल फोटो। प्रेट्र

इस साल सितंबर में सेना का उप प्रमुख पद संभालने से पहले नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सेना की यह कमान चीन से लगती 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती है। नरवाने की नियुक्ति ऐसे समय हो रही है, जब आतंकी गतिविधियों के जरिये पाकिस्तान की भड़काऊ कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं।

जानिए नए सेना प्रमुख को

- लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जून 1980 में सातवीं सिख लाइट इन्फैंट्री में कमीशन हुए थे।
- अपनी 37 साल की सेवा में वे कई कमानों में काम कर चुके हैं।
- उनके पास जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकरोधी कार्रवाइयों का लंबा अनुभव है।
- जम्मू-कश्मीर में अपने बटालियन के सफल संचालन के लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
- उन्होंने श्रीलंका में शांति रक्षक बल में काम किया है। वे म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे भी रहे हैं।
- नरवाने की शादी वीणा नरवाने से हुई है, जो शिक्षिका हैं। उनकी दो बेटियां हैं।

धोखाधड़ी

जीसटी में आनलाइन फर्जीवाड़े का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में जो मामला सामने आया है वह केवल इसी राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं

उत्तराखंड में ई-वे बिल में 8500 करोड़ का फर्जीवाड़ा

- कर विभाग ने छापा मारकर 70 बोगस फर्मों पर कसा शिकंजा
- फर्जीवाड़े के दायरे में दिल्ली समेत करीब आधा दर्जन राज्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में कर महकमे (वस्तु एवं सेवा कर) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-वे बिल में करीब 8500 करोड़ का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा पकड़ा है। 70 बोगस फर्मों ने बीते दो महीनों में फर्जी तरीके से राज्य के भीतर और बाहर करीब 8500 करोड़ के ई-वे बिल बनाए। इन 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के बिल बना रही थीं। 26 फर्मों के माध्यम से चप्पल की बिक्री अन्य राज्यों में दिखाई गई।

उत्तराखंड में जीएसटी लागू होने के बाद माल एवं वस्तु कर के तहत ई-वे बिल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का यह अपनी तरह का अलहदा मामला है। इस फर्जीवाड़े की आंच दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान तक पहुंच रही है। वित्त सचिव अमित नेगी के निर्देश पर मंगलवार को कर आयुक्त जीएसटी की 55 टीमों ने कुल 70 फर्मों (ऊधमसिंह नगर में 68 और देहरादून में दो) के कार्यालयों पर छापे मारे। व्यापार स्थल पर किए गए सर्वे में यह फर्जीवाड़े सामने आया। उत्तराखंड की वित्त सचिव एवं कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि मंगलवार को मौके पर न कोई फर्म मिली और न ही कोई पंजीकृत व्यक्ति।

प्रतीकात्मक फोटो

ज्यादातर वाहन पूर्वोत्तर में पंजीकृत : उन्होंने बताया कि राज्य में कुछ लोगों ने जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर ई-वे बिल के करोड़ों रुपये के कारोबार को दिखाया। जांच करने पर पता चला कि 70 में से 34 फर्मों ने दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के 1200 करोड़ मूल्य के ई-वे बिल बनाए। इसके बाद फर्मों ने उक्त सामान की आपस में खरीद-बिक्री के साथ प्रदेश के बाहर की फर्मों को भी खरीद और बिक्री दिखाई, जिससे बिल की धनराशि करीब 8491 करोड़ तक पहुंच गई। फर्जी तरीके से बनाए गए ई-वे बिल में प्रयोग किए गए वाहनों की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि अधिकतर वाहन पूर्वोत्तर राज्यों में पंजीकृत हैं।

21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल : कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि कुल 80 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी का प्रयोग करते हुए दो-दो की साझेदारी में 70 फर्म पंजीकृत कीं। पंजीयन में दर्ज ब्योरे के मुताबिक सभी साझीदार हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति ने अलग-अलग नाम से अलग-अलग फर्मों में साझेदारी की है। किराए पर लिए गए स्थान का किरायानामा और बिजली का बिल लगाया गया है। जांच से पता चला कि मकान मालिक ने इस तरह का करार किसी फर्म से नहीं किया है।

गलत उम्र बताने पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला का निर्वाचन रद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अब्दुल्ला आजम। फाइल

हाई कोर्ट ने कहा, विधानसभा चुनाव लड़ते समय 25 साल के नहीं थे अब्दुल्ला

सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनके रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए उनका निर्वाचन रद कर दिया है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति चुनाव आयोग व विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल नहीं थी, जबकि चुनाव के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल के फार्म में अब्दुल्ला की जन्म की तारीख एक जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि उनकी मां तजीन फात्मा का कहना है कि यह तारीख सही नहीं है। उनके बेटे का जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ था, जो नगर निगम लखनऊ में दर्ज है। 17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाणपत्र की अर्जी दी गई थी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है। अस्पताल में मेल बेबी का जन्म लिखा है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह बच्चा अब्दुल्ला आजम ही था। अब्दुल्ला ने वोटर लिस्ट में दर्ज जन्म की तारीख के आधार पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसे ठोस आधार नहीं माना जा सकता। (पेज-6 भी देखें)

10 लाख रुपये का राजस्व मिला है नोएडा के परिवहन विभाग को 45 फैंसी नंबरों पर लगी बोली से। करीब 200 साधारण नंबर बुक होने से करीब नौ लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 17 दिसंबर 2019

पुलिस पर एफआइआर दर्ज कराएगा जामिया

दावा ▸ कुलपति नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर छात्रों को पीटने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

किसी भी छात्र की नहीं हुई मौत, फैलाई जा रही अफवाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) की कुलपति नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना अनुमति के कैंपस में घुसी और छात्रों के साथ बर्बरता की। पुलिस के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा में किसी भी छात्र की मौत नहीं हुई है बल्कि मौत की अफवाह फैलाई जा रही है। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।

कुलपति नजमा अख्तर ने सोमवार को बाकायदा पत्रकार वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, पुलिस ने रविवार को बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। पुस्तकालय में बैठे छात्रों पर लाठियां भांजी जिससे 200 छात्रों को चोटें आईं। इस कार्रवाई में विश्वविद्यालय की संपत्ति बर्बाद हो गई। छात्रों को भावनात्मक नुकसान हुआ है। आप संपत्ति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं जो छात्रों पर बीती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और उसकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। कुलपति ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि वह मानव संसाधन विकास मंत्री को रिपोर्ट भेजेंगी।

केंद्रीय विवि शिक्षक संघ ने की न्यायिक जांच की मांग : केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (एफईडीसीयूटीए) ने जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआइआर वापस ली जाए और विश्वविद्यालय परिसर के माहौल को सामान्य बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

हॉस्टल खाली करने के निर्देश : सभी छात्र-छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के लिए कह दिया गया है। इसके बाद छात्रों ने घर जाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्राएं भी प्रदर्शन के दौरान सामान लेकर जाती दिखाई दीं। परिजन भी मीडिया में आई खबरों के बाद छात्रों से घर वापस लौटने के लिए कह रहे हैं।

इग्नू ने बदला परीक्षा केंद्र : जामिया प्रकरण के कारण तनाव के बाद इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी (इग्नू) ने परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर दिया है। दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया परीक्षा केंद्र की जगह गुरु नानक गरीब नवाज एजुकेशन सोसायटी (07191) को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 17 दिसंबर को होनी है।

आप नेताओं के खिलाफ भाजपा ने की पुलिस से शिकायत : भाजपा ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक अमानतुल्लाह खान सहित आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेताओं ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त से करके हिंसा फैलाने वाले आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

छह मेट्रो स्टेशन रहे बंद : सोमवार को छह मेट्रो स्टेशन बंद रहे। दिल्ली पुलिस के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन से दोपहर में यात्रियों का आवागमन रोक दिया। इसके बाद शाम को पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग व जनपथ मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया।

विवि के छात्रों के लिए चिंतित इरफान पठान

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज रह चुके इरफान पठान ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर चिंता जताई है। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी पठान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, 'देश भर के शिक्षण संस्थानों से बेहद परेशान करने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं।' 35 वर्षीय इरफान ने सोमवार को ट्वीट किया, 'राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मैं और हमारा देश जामिया के छात्रों के लिए चिंतित हैं।' वहीं, भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने एक ट्वीट करके कहा, 'छात्र आंखों में आंसू लिए थे। वह भी हम में से ही एक हैं। यह बच्चे देश का भविष्य हैं। लोगों की आवाज बलपूर्वक दबाकर हम भारत को महान नहीं बनाते हैं। इस तरह आप केवल उन्हें भारत के खिलाफ करेंगे।' जामिया मिल्लिया के छात्र नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ रविवार शाम को हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। सीएए के खिलाफ हिंसक उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया। सराय जुलेनिया मथुरा रोड पर स्थित इस परिसर में जब हालात ज्यादा गंभीर हो गए तो पुलिस ने परिसर में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डीटीसी बस को जला दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

समर्थन में आया बॉलीवुड

मुंबई, प्रेट्र : जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई की बॉलीवुड के कई कलाकारों और निर्माता-निर्देशकों ने आलोचना की है। हॉलीवुड स्टार जॉन कुसैक, निर्देशक अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा और अभिनेत्री तापसी पन्नू व और कोंकणा सेन शर्मा समेत कई लोगों ने विवि परिसर में हिंसा पर नाराजगी जताई है। कुसैक ने ट्वीट किया, 'दिल्ली से खबरें हैं कि यह पिछली रात युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गई थी। फासिज्म मजाक नहीं है। हम समझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।' अनुराग ने ट्वीट किया, 'अब और चुप नहीं रह सकता। यह सरकार फासिस्ट है। यह देखकर मुझे और नाराजगी हो रही है कि जिन आवाजों से सही में फर्क पैदा हो सकता है, वे चुप हैं।'

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में उतरे विपक्षी दल

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा (सामने जैकेट में)। साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी (बाएं से दूसरे, टोपी में) और हरीश रावत (एंटनी के पीछे, टोपी में)। संजय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों पर पुलिस की 'बर्बरतापूर्ण' कार्रवाई के विरोध में सोमवार को कांग्रेस की अगुआई में कई विपक्षी दलों ने आगे आकर पूरी घटना की निंदा की। साथ ही सरकार से मामले की सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुआई में न्यायिक जांच कराने की मांग की। विपक्ष का आरोप था कि नागरिकता कानून का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना कैंपस में दाखिल होकर पीटा, जो निंदनीय है। इस पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दोपहर बाद मोर्चा संभाला और इंडिया गेट पहुंचकर धरना दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की अगुआई में जिन प्रमुख विपक्षी दलों के नेता इसे मसले पर सामने आए, उनमें समाजवादी पार्टी के दानिश अली, भाकपा के ए. राजा, माकपा के सीताराम येचुरी और राजद के मनोज झा शामिल थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देशभर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मौजूदा हालात के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि यह आग उसी की लगाई हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया था। माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि नागरिकता कानून कोई हिंदु-मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह संविधान से छेड़छाड़ का मुद्दा है। इसमें धार्मिक आधार पर नागरिकता तय की गई है। भाकपा के डी. राजा ने कहा कि जामिया की घटना में इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह कार्रवाई किसके आदेश पर की गई। उन्होंने देश के मौजूदा हालात को सिविल वार जैसा बताया जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सपा सांसद दानिश अली ने भी घटना की निंदा की और कहा कि छात्रों की जिस नागरिकता कानून को लेकर पिटाई की गई है, सरकार को तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसे वापस लेना चाहिए।

पाकिस्तान मरा हुआ शेर, कब तक उसके नाम से डराएगी सरकार : आजाद : कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से चर्चा में पाकिस्तान को 'मरा हुआ शेर' बताया और कहा कि यह ठीक वैसा है जिसे घास-फूस भरकर सिर्फ खड़ा किया गया है। ऐसे में सरकार कब तक उसके नाम को लेकर हमें डराएगी। उन्होंने कहा कि वैसे भी भाजपा अंग्रेजों से सीखकर 'बांटो और राज करो' की नीति पर काम रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जामिया मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। वह विश्वविद्यालय के विजिटर हैं। जैसे ही समय मिलेगा, वह पूरी बात उनके सामने रखेंगे।

जामिया के समर्थन में उतरे जादवपुर व प्रेसिडेंसी के छात्र

कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) का विरोध कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर रविवार रात को हुए पुलिसिया हमले के विरोध में सोमवार को कोलकाता के जादवपुर और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जादवपुर परिसर से निकली इस रैली में सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए थे। दूसरी ओर प्रेसिडेंसी विवि के छात्रों ने कॉलेज स्ट्रीट में मानव बंधन के जरिए सड़क अवरोध कर विरोध जताया। इस दौरान दोनों विवि के छात्रों ने सीएए व एनआरसी के खिलाफ पोस्टर व बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

न्यूज गैलरी

नहीं हो सका मुफ्त वाई-फाई योजना का शुभारंभ

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रविवार को जामिया नगर में हुई हिंसा के चलते दिल्ली सरकार ने सोमवार को मुफ्त वाई-फाई योजना का शुभारंभ टाल दिया। इस आयोजन के लिए भविष्य में तारीख निर्धारित की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आइटीओ बस स्टैंड पर इस योजना का शुभारंभ करना था। सोमवार को 100 हॉट स्पॉट की शुरुआत की जानी थी। पहले फेज में दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। सोमवार को सराय काले खां बस स्टैंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी बस स्टैंड, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट आइएसबीटी, आइटीओ बस स्टैंड, मंडी हाउस बस स्टैंड, दिल्ली सचिवालय बस स्टैंड और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन समेत सात विधानसभा क्षेत्रों में 100 हॉट स्पॉट की शुरुआत होनी थी। (जासं)

काम करने का दिखावा कर रहे केजरीवाल : डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि साढ़े चार वर्षों तक दिल्ली के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली सरकार चुनाव नजदीक देखकर काम करने का दिखावा कर रही है। दिल्ली की जनता यह तय करेगी कि उन्हें चुनाव के समय सक्रिय होने वाला सीएम चाहिए या पूरे पांच वर्षों तक काम करने वाला। केंद्रीय मंत्री ने बयान जारी कर दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन माह से आप सरकार सक्रिय दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। आप सरकार ने अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों की अनदेखी की है। चुनाव के समय इन कॉलोनियों व झुग्गी-झोपड़ी में काम करने का दिखावा किया जा रहा है। (जासं)

सोने की तस्करी में गिरफ्तार किए गए दो भारतीय

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी में दो भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने की 27 रॉड बरामद की गई हैं। तस्कर मार्कर की रिफिल में रॉड छिपाकर दिल्ली आए थे। कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना 16 दिसंबर की है। एक उड़ान जेद्दा से आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई थी। इससे उतरे दो संदिग्ध शख्स एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जुगत में लगे थे। तभी कस्टम अधिकारियों ने दोनों को दबोच उनकी तलाशी ली। तलाशी में उनके पास से सोना बरामद हुआ। कस्टम अधिकारी यह छानबीन कर रहे हैं कि क्या वे पहले भी तस्करी की घटना में लिप्त रहे हैं। (जासं)

'11 वर्षों से रुके कार्य को कुछ हफ्तों में पूरा कर दिखाएंगे'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

रोहिणी में अनाधिकृत कालोनियों को पक्का करने के लिए बनाए गए पोर्टल की बुकलेट को लांच करते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (मध्य में)। साथ में (दाएं से) डीडीए उपाध्यक्ष तरुण कपूर, उपराज्यपाल अनिल बैजल और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता (बाएं)। जागरण

रोहिणी के सेक्टर-10 में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र सहित छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विकास कार्यों का नया आयाम प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से रोहिणी ही नहीं बल्कि नरेला, द्वारका समेत दिल्ली के कई इलाकों में तेजी से कार्य हो रहे हैं। हमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य करना है। इस दौरान उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बनाए गए डीडीए के पोर्टल को भी लांच किया।

उन्होंने कहा कि 2008 से जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तब से अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात चल रही है। उस समय बनाए गए एक पोर्टल में 1731 कॉलोनी की सूची डाली गई थी। उसके बाद से हम इस इंतजार में थे कि इन कॉलोनियों के नक्शे बनें और इन्हें मालिकाना हक देने का काम शुरू हो। 2017 में दिल्ली सरकार से जब इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि इसमें दो वर्ष लगेंगे। 2019 में उनकी ओर से यही जबाव आया। तब हमने यह निर्णय लिया कि दिल्ली सरकार यह काम नहीं करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे डीडीए के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया, जबकि दिल्ली सरकार यह कहती रही कि वह इस कार्य को कराना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही।

मंत्री ने कहा कि संसद में बिल पास होने के बाद 1550 कॉलोनियों के नक्शे बन चुके हैं। 1060 कॉलोनियों के नक्शे पोर्टल पर अपडेट हो चुके हैं और 8268 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगले कुछ हफ्तों में इसे पूरा करके दिखाएंगे। ऐसे में 11 वर्षों से जो कार्य रुका था, आज उसके पूरा होने का अवसर आ गया है। इसके तहत डीडीए के 50-75 हेल्प डेस्क भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में कार्य शुरू कर दिए जाएंगे और इसकी स्कीम 'जहां झुग्गी वहीं मकान' की योजना पर जल्द काम पूरा किया जाएगा।

इस मौके पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत से रोहिणी में लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मॉडर्न सिटी के निर्माण से प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रोहिणी को सुंदर बनाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इन परियोजनाओं की शुरुआत होने से आने वाले वक्त में यहां का नजारा अलग ही होगा। इस दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर, उत्तरी पश्चिम जिलाध्यक्ष नीलदमन खत्री भी मौजूद थे।

पहले ही दिन डीडीए पोर्टल पर हुए 10 हजार से अधिक पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पोर्टल पर सोमवार से पंजीकरण शुरू हो गया। पहले ही दिन इन कॉलोनियों के 10 हजार से ज्यादा निवासियों ने पंजीकरण कराया। दूसरी तरफ डीडीए की ओर से 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की चहारदीवारी तय कर ली गई है और 1243 कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। डीडीए का कहना है कि आने वाले दिनों में तेजी से लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की इन अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। इन सभी को संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाना है। डीडीए द्वारा भी इन कॉलोनियों में रहने वालों की मदद के लिए अधिक से अधिक सहायता केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा समय में 25 सहायता केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिन पर लोग जाकर दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं। दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने में समस्या आने पर सहायता केंद्रों से मदद ली जा सकती है।

निर्भया के गुनहगारों से अंगदान की अपील करेगी संस्था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सामाजिक सेवा से जुड़ी एक संस्था ने तिहाड़ जेल प्रशासन को पत्र लिखकर निर्भया के दोषियों से मिलने की इच्छा जताई है। पत्र में कहा गया है कि मिलने का उद्देश्य दोषियों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। संस्था का मानना है कि दोषियों की ओर से किए गए कृत्य की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ अच्छा करने का अंतिम मौका है। दोषी अंगदान कर कई जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं।

निर्भया के दोषियों से मिलने को लेकर रोड एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन संस्था ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से इन लोगों ने चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश से मिलकर उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित करने की इच्छा जताई है। संस्था के प्रमुख राहुल शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने संस्था के लोगों से विचार-विमर्श कर यह पहल की है। अभी तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। अगर तिहाड़ प्रशासन की ओर से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो वह न्यायालय से गुहार लगाएंगे। इस बाबत जेल अधिकारियों का कहना है कि तिहाड़ में जो भी पत्र आते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तिहाड़ में मौत की सजा पाए दोषियों से किसी भी संस्था को ऐसे नहीं मिलने दे सकते हैं। इसके लिए अदालत की इजाजत जरूरी है।

निर्भया मामले के दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। अक्षय ने अपने मृत्युदंड के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। अक्षय ने याचिका में कहा है कि वायु और जल प्रदूषण के चलते दिल्ली में लोगों की उम्र वैसे ही कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्म पीड़िता की मां का पक्ष भी सुनेगा, जिन्होंने अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पिछले वर्ष नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं आयोजित कराएगा जेएनयू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 12 दिसंबर से शुरू हुई सेमेस्टर परीक्षाओं का वामपंथी छात्र संगठनों ने बहिष्कार किया है। इस वजह से बहुत से छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इस समस्या के हल के लिए जेएनयू प्रशासन ने वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है। इसके अलावा शुरुआत में परीक्षाओं की अवधि 12 से 20 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दिया गया है।

जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने 16 दिसंबर को इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से बार-बार अपील के बाद भी छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। इस वजह से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (एसएसएस), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लेंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के कई छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी हैं। फिलहाल जेएनयू प्रशासन ने अन्य वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है। वैकल्पिक माध्यमों में ओपन बुक परीक्षा, घर पर बैठकर परीक्षा या असाइनमेंट जैसे विकल्प शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आम्रपाली को स्ट्रेस फंड देने पर कब फैसला लेगा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली समूह की ठप परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्ट्रेस फंड का लाभ दिए जाने के मुद्दे पर केंद्र से सवाल पूछा है। उसने पूछा है कि योजना का लाभ देने संबंधी आवेदन पर विचार करने के लिए केंद्र और कितना समय लेगा। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को परेशानी से उबारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के स्ट्रेस फंड की घोषणा की है। कोर्ट ने केंद्र को मंगलवार को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

जस्टिस अरुण मिश्रा व यूयू ललित की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को मंगलवार सुबह तक यह बताने का निर्देश दिया कि आवेदन पर कार्रवाई के लिए और कितना वक्त लगेगा। बनर्जी ने बताया कि 25 हजार करोड़ रुपये का स्ट्रेस फंड वास्तव में एक वैकल्पिक निवेश कोष है, जिसमें केंद्र को 10 हजार करोड़ रुपये देना है। बाकी 15 हजार करोड़ रुपये दूसरे वित्तीय संस्थानों को देना है। इस राशि से रियल एस्टेट की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक फंड मैनेजर के तौर पर काम करेगा और वह रियल एस्टेट के आवेदनों पर नियत प्रक्रिया के तहत राशि जारी करेगा। पीठ ने पूछा कि फंड मैनेजर को दिए गए आवेदन पर विचार की कोई समयसीमा तय है? बनर्जी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आम्रपाली को फंड की जरूरत है तो उसे आवेदन करना होगा। अदालत ने कहा कि वह कोर्ट रिसीवर को आवेदन के लिए कह सकता है, लेकिन यह पता होना चाहिए कि इस पर विचार में कितना समय लगेगा।

सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को परेशानी से उबारने के लिए 25 हजार करोड़ के स्ट्रेस फंड की घोषणा की है

पीठ ने सुनवाई के दौरान आम्रपाली समूह की संपत्तियों की नीलामी के लिए नियुक्त सरकारी संस्था मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी) की कार्य प्रणाली पर भी नाराजगी जताई। उसने कहा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीटीआर) से आम्रपाली की संपत्तियां वापस लेनी हैं। डीटीआर को आम्रपाली समूह की संपत्तियों की नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन गुटबाजी के कारण वह समूह की प्राइम प्रॉपर्टी की भी अच्छी कीमत नहीं हासिल कर सका। अगर ऐसी ही स्थिति फिर पैदा होती है तो उसे एमएसटीसी से भी आम्रपाली की संपत्तियां वापस लेनी होंगी। शीर्ष अदालत ने एनबीसीसी को आम्रपाली की ए श्रेणी की परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें बेचा जा सके और प्राप्त राशि को दूसरी परियोजनाओं में लगाया जा सके।

धौनी की फीस संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई : आइएएनएस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को दी गई फीस की वापसी संबंधी निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आम्रपाली समूह ने धौनी को प्रचार के लिए फीस के तौर पर 42.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जनवरी में सुनवाई करेगी।

योजना

कपड़ों-खिलौनों में बसेंगी चिड़ियाघर की यादें

चिड़ियाघर में खुलेगा स्टोर, यहां आने वाले पर्यटक वन्यजीवों से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सेकेंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विदेशी चिड़ियाघरों की तर्ज पर राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी अपना एक स्टोर खोलने जा रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक वन्यजीवों से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए निविदा जल्द ही जारी की जाएगी। निविदा मंजूर होते ही चिड़ियाघर के बाहर स्टोर खुल सकेगा। फिलहाल निजी कर्मचारी ही इसका संचालन करेंगे।

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशों में अमूमन चिड़ियाघरों में अपना एक स्टोर होता है। इसमें टी-शर्ट, खिलौने, किताबें, टोपी व कपड़े आदि उपलब्ध होते हैं। पर्यटक चिड़ियाघर में भ्रमण करने के बाद अक्सर स्टोर से खरीदारी कर चिड़ियाघर से जुड़ी अपने यादों को सहेजते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चिड़ियाघर में भी स्टोर खोलने की कोशिश हो रही है। चीजों को खरीदने में पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए चीजों के दाम बाजार के दाम पर ही रहेंगे।

चिड़ियाघर की फाइल फोटो।

हालांकि, चिड़ियाघर के बाहर स्टोर कहां खुल सकता है, अभी इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन जमीन देख रहा है। इसके लिए ऐसा स्थान देखा जा रहा है जिससे यहां आने जाने वाले पर्यटक स्टोर तक आसानी से पहुंच सके।

दो रुपये में मिल सकेगा पीने का पानी : आने वाले समय में चिड़ियाघर के अंदर वाटर एटीएम लगाए जाने का भी प्रस्ताव है। एक अधिकारी ने बताया कि कई बार लोग यहां लगे नलों से पानी पीने में कतराते हैं। ऐसे में वाटर एटीएम का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही यहां पर दो रुपये में पर्यटक पानी पी सकेंगे।

प्लास्टिक की बोतल पर पूरी तरह से प्रतिबंध

चिड़ियाघर में प्लास्टिक की बोतल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में यदि कोई चिड़ियाघर के अंदर प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि चिड़ियाघर में प्लास्टिक पहले से ही प्रतिबंधित है। ऐसे में इसके प्रयोग को लेकर अब चिड़ियाघर ने और भी सख्त रवैया अपना लिया है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए भी बायोडिग्रेडेबल गिलास उपलब्ध रहेंगे। चिड़ियाघर में हाल में ही प्लास्टिक खाने से एक अफ्रीकी भैंसे की मौत हो गई थी। इसने चिड़ियाघर प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था।

ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी को सौंपा कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड

जासं, ग्रेटर नोएडा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जेवर एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के सीईओ डैनियल बर्चर को लखनऊ में कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड सौंपा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कंपनी को हर संभव सहयोग देगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 29 नवंबर को फाइनेंशियल बिड खोली गई थी। अडानी समूह को पीछे छोड़ते हुए स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने एयरपोर्ट की बिड जीती थी। सोमवार को लखनऊ में विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट को कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया। कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड सुरक्षा जांच के बाद जारी किया जाएगा। सुरक्षा जांच के लिए विकासकर्ता कंपनी को पहले नियाल में आवेदन करना होगा।

अगले सप्ताह से अवकाश पर आधे डॉक्टर, मरीजों की बढ़ेंगी मुश्किलें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स व मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) में अगले सप्ताह से सर्दी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस वजह से एम्स व एमएएमसी से संबंधित अस्पतालों में शैक्षणिक कैडर के 50 फीसद डॉक्टर नौ दिन से लेकर 16 दिन तक अवकाश पर रहेंगे। इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एम्स में 23 दिसंबर से आगामी 10 जनवरी तक डॉक्टरों की छुट्टी रहेगी। इस दौरान डॉक्टरों को दो चरणों में छुट्टी मिलेगी। पहले चरण में 23 से 31 दिसंबर तक आधे डॉक्टरों को अवकाश दिया जाएगा। बचे हुए डॉक्टरों को 2 से 10 जनवरी तक अवकाश दिया जाएगा। एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 13 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें से करीब 40 फीसद मरीज दूसरे राज्यों से इलाज के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड के मरीज अधिक पहुंचते हैं। ऐसे में 50 फीसद डॉक्टरों के अवकाश पर होने से मरीजों का इलाज प्रभावित होना लाजमी है। हालांकि, एम्स प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अवकाश के दौरान 50 फीसद फैकल्टी (शैक्षणिक कैडर के वरिष्ठ डॉक्टर) की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर भी मरीजों के इलाज का दारोमदार रेजिडेंट डॉक्टरों व अनुबंध पर नियुक्त डॉक्टरों पर ही होगा। ऐसे में 23 दिसंबर के बाद एम्स की ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने से पहले यह जांच लेना बेहतर होगा कि मरीज जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, वह उपलब्ध हैं या नहीं।

एमएएमसी में 24 दिसंबर से छुट्टी शुरू हो रही है। इस मेडिकल कॉलेज से लोकनायक, जीबी पंत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व गुरु नानक नेत्र केंद्र जुड़े हुए हैं।

2018 में भारत और अमेरिका के बीच कॉमकासा (कम्यूनिकेशंस एंड इंफॉमेशन आन सिक्यूरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) हुआ था। यह किसी भी दूसरे देश के साथ अमेरिका की तरफ से किया गया सबसे अहम समझौता है।

प्रणब ने दिया लोकसभा सदस्य संख्या 1,000 करने का सुझाव

रखी राय ▶ इसी अनुपात में बढ़े राज्यसभा सदस्यों की भी संख्या

वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर में पूर्व राष्ट्रपति ने सांसदों को याद दिलाई उनकी जिम्मेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने मौजूदा वोटर संख्या के लिहाज से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या एक हजार तक करने और इसी अनुपात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाने का सुझाव दिया। संसद में सदस्यों के हंगामे को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रणब ने कहा कि सांसद यह कतई न भूलें कि उन्हें लाखों लोगों ने बड़ी उम्मीद से कुछ करने के लिए भेजा है, उन्हें उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना चाहिए।

पूर्व राष्ट्रपति सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित दूसरे मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। 'भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता और चुनौतियां' विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने में बुनियादी ढांचे की भी फिलहाल कोई कमी आड़े नहीं आने वाली है। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल हॉल को लोकसभा, लोकसभा को राज्यसभा और राज्यसभा को लॉबी या सेंट्रल हाल में तब्दील करने का सुझाव दिया।

प्रणब ने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या भारत से काफी कम है और इसके बावजूद वहां की संसद में सदस्यों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि ब्रिटिश संसद में 650 सदस्य हैं, कनाडा की संसद में 443 सदस्य हैं और अमेरिका की संसद (कांग्रेस) में 535 सदस्य हैं। ऐसे में हम क्यों पीछे हैं। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया और कहा कि 2109 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, देश में मौजूदा समय में कुल 90 करोड़ वोटर हैं। ऐसे में लोकसभा की 543 सीटों के लिहाज से देखें तो एक सीट पर औसतन 16 से 20 लाख वोटर आते हैं। ऐसे में एक सदस्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ पाना मुश्किल होता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति ने यह सुझाव ऐसे समय दिया है, जब सरकार मौजूदा संसद में जगह की कमी का हवाला देते हुए नई संसद बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रणब ने बहुमत की सरकारों को सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की और कहा कि वह भारत के एक महान पुत्र थे, जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत बनाने के लिए उदाहरण पेश किया था। उन्हें साहसिक फैसले लेने के लिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भी संबोधित किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार भी मौजूद रहा।

आरटीआइ में निहित स्वार्थ से ब्लैकमेल होने का खतरा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को तीन महीने के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर लेने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत है। अदालत ने निहित स्वार्थ से आरटीआइ का इस्तेमाल होने और ब्लैकमेलिंग एवं फिरौती की आशंका जताई है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया। शीर्ष कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार ने सीआइसी और एसआइसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की। इस पीठ में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। पीठ ने कहा, 'हम केंद्र और राज्य को नियुक्ति पूरी करने का निर्देश देते हैं।' पीठ ने अधिकारियों से दो सप्ताह में वेबसाइट पर सर्च कमेटी के सदस्यों के नाम जारी करने को कहा है। यह सर्च कमेटी केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित की गई है। सुनवाई के दौरान पीठ ने ऐसे लोगों द्वारा जिनका मांगी गई सूचना से कोई संबंध नहीं है, आरटीआइ का दुरुपयोग होने की आशंका जताई।

स्माग टावर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मिला तीन माह का समय

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कनाट प्लेस में किए जाएंगे स्थापित

नई दिल्ली, प्रेट्र : वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कनाट प्लेस में स्माग टावर स्थापित करने के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने का समय दिया है। कोर्ट ने इस काम के लिए दोनों की नौ माह का समय देने का अनुरोध ठुकरा दिया।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, 'आप इतना समय नहीं ले सकते। हम और एक साल खराब नहीं करना चाहते।' केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस संबंध में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इस पर पीठ ने पूछा, 'पायलट प्रोजेक्ट लागू करने के लिए आपको कितना समय चाहिए?' नादकर्णी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्माग टावर स्थापित करने के लिए अधिकतम पांच से छह महीने की जरूरत होगी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कनाट प्लेस में स्माग टावर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आठ से नौ महीने की जरूरत होगी। पीठ ने उच्चस्तरीय समिति से संबद्ध आइआइटी के प्रोफेसर से भी पूछताछ की। यह समिति वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्माग टावर और स्माग गन जैसी तकनीक के इस्तेमाल की संभावना पर

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

काम कर रही है। जब आइआइटी के विशेषज्ञ ने कहा कि कनाट प्लेस में स्माग टावर पर पायलट प्रोजेक्ट अगले साल अगस्त या सितंबर में पूरा हो जाएगा, पीठ ने कहा, 'क्या दो या तीन महीने में पूरा नहीं हो सकता?'

पीठ ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नादकर्णी से स्माग गन जैसी तकनीक के इस्तेमाल के बारे में भी पूछा। पीठ ने कहा, 'कितने स्माग गन की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए कोष कौन मुहैया कराएगा? स्माग गन पर कितना खर्च आएगा? कल तक आप इस बारे में हमें सूचित करेंगे। हम आदेश जारी करेंगे।'

अपने यहां सक्रिय दूसरे देश के आतंकियों को पकड़ने में मदद करेगा नेपाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीमा पार से आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के भारतीय प्रयासों को बड़ा समर्थन मिला है। नेपाली राष्ट्रीय अर्धसैनिक बल ने अपनी जमीन पर सक्रिय तीसरे देश के आतंकियों को पकड़ने में सहयोग का आश्वासन दिया है। इस संबंध में भारतीय सीमा रक्षक बल एसएसबी और उसके नेपाली समकक्ष एपीएफ के बीच नेपाल के पोखरा में 20-22 नवंबर को हुई समन्वय बैठक में हस्ताक्षर किए गए। एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र और सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के महानिरीक्षक शैलेंद्र खनल के नेतृत्व में दोनों देशों की टीमों ने बैठक में भाग लिया।

दोनों देशों के सीमा रक्षक बल के बीच सालाना बैठक होती है। इस बैठक में हथियारों की तस्करी, जाली नोट, मादक पदार्थ, अन्य आपराधिक गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी एवं आतंकी गतिविधियों संबंधी आपसी चिंता के मुद्दों से निपटने पर चर्चा की जाती है। एक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं करते हुए कहा, 'यह पहला मौका है जब दानों पक्षों ने चर्चा के जिस संयुक्त रिकार्ड पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें तीसरे देश के संचालक का विशेष उल्लेख किया गया है। नेपाल ने अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वाले किसी तीसरे देश के नागरिक के खिलाफ सहयोग की पेशकश की है। भारत ने भी यही आश्वासन दिया है।'

रक्षा सौदों को लेकर अहम घोषणा की उम्मीद

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- बुधवार को होगी भारत व अमेरिका के विदेश व रक्षा मंत्रियों की अगुआई में टू प्लस टू वार्ता
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका रवाना

न्यूयॉर्क में राजनाथ सिंह (मध्य में) की अगवानी अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन (बाएं) और महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती ने की। प्रेट्र

बातचीत का एजेंडा

- ऐतिहासिक रक्षा सौदे कॉमकासा के तहत तय लक्ष्यों की होगी समीक्षा
- साथ मिल कर बनाए जाने वाले रक्षा उपकरणों के एसओपी को मिलेगी मंजूरी
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को आगे बढ़ाने की भावी रणनीति
- चीन के बीआरआइ से ज्यादा विश्वसनीय विकल्प पर होगी बात
- रूस -ईरान के साथ रिश्तों पर भी चर्चा होगी
- अमेरिकी कांग्रेस में कश्मीर व सीएबी पर उठे सवाल भी होंगे शामिल

भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 'टू प्लस टू' वार्ता की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार देर रात को नई दिल्ली से भारत व अमेरिका के कूटनीतिक व रणनीतिक रिश्तों की दिशा तय करने वाली इस अहम बैठक में देश का नेतृत्व करने के लिए रवाना हो जाएंगे। दोनों तरफ से अभी तक इस बैठक को लेकर जो संदेश दिया गया है उससे आगामी बैठक में पिछले वर्ष किए गए एतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते कॉमकासा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। इसके तहत साझा तौर पर विकसित होने वाले या निर्माण किए जाने वाले रक्षा उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (एसओपी) को अंतिम मंजूरी मिलने के आसार हैं।

जानकारों के मुताबिक, इस बार भी टू प्लस टू वार्ता तीन स्तरीय होगी। यानी पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर के साथ बैठक करेंगे। जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री पोंपिओ मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें दोनों तरफ के विदेश व रक्षा मंत्री अगुआई करेंगे। बैठक में दोनों पक्षों के तकरीबन एक-एक दर्जन अधिकारी होंगे। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान में बैठक के महत्व को रेखांकित किया था। यह पहला मौका है जब अमेरिकी पक्ष ने बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि भारत के साथ वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, आगामी बैठक रणनीतिक व रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के विचार को समझने के लिए होगी। भारत और अमेरिका के बीच सितंबर, 2018 में कॉमकासा यानी कम्यूनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन आन सिक्यूरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। यह किसी भी दूसरे देश के साथ अमेरिका की तरफ से किया गया सबसे अहम समझौता है। इस तरह का समझौता अमेरिका ने अपने विशेष रणनीतिक सहयोगी नाटो समेत बेहद कम देशों के साथ किया है। इससे अमेरिका की अत्याधुनिक रक्षा तकनीक भारत को देने का रास्ता साफ हो गया है। अक्टूबर, 2019 में भारत व अमेरिका के बीच भावी रक्षा सौदों को लेकर अहम बात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को होने वाली बैठक में इस संदर्भ में अहम घोषणा हो सकती है। बैठक में भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध अभ्यासों पर भी चर्चा होगी। टू प्लस टू वार्ता में कुछ चुभने वाले मुद्दे भी उठने के पूरे संकेत हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने या नागरिकता बिल पर विपरीत टिप्पणियां की हैं उसे भारत उठा सकता है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इन पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं आई है लेकिन दूसरी सरकारी एजेंसियों की टिप्पणियों को सहज तौर पर नहीं लिया जा सकता।

नागरिकता कानून के खिलाफ अर्जियों पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- याचिकाएं दायर करने वालों में ज्यादातर सांसद या पूर्व सांसद

नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और त्रिपुरा राजपरिवार से संबंध रखने वाले प्रद्योत किशोर देव बर्मन की शीघ्र सुनवाई करने की मांग पर कहा कि इन दोनों के साथ अन्य याचिकाओं पर भी बुधवार को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करने वालों में ज्यादातर राजनेता हैं जो सांसद या पूर्व सांसद हैं। इनमें जयराम रमेश और बर्मन के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, एआइएमआइएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) आदि शामिल हैं।

सोमवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जयराम और बर्मन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे, उसी दिन एक और याचिका आइयूएमएल की भी सुनवाई पर लगी है उसी के साथ इन पर भी सुनवाई की जाएगी।

नागरिकता संशोधन कानून में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ज्यादातर याचिकाओं में कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताते हुए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

जयराम रमेश की याचिका में नागरिकता संशोधन कानून-2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला और 1985 के असम समझौते के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सरबानंद सोनोवाल मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन करता है इसलिए इसे रद किया जाए। याचिका में कहा है कि कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून संविधान में प्राप्त बराबरी (अनुच्छेद 14) और जीवन (अनुच्छेद 21) के अधिकारों का सीधा उल्लंघन करता है। इस कानून को तैयार करने में संयुक्त संसदीय समिति की सात जनवरी, 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार, एएएसयू और एएजीएसपी के बीच 15 अगस्त, 1985 को हुए असम समझौते में फॉरेन नेशनल इश्यू के मुद्दे का उल्लंघन करता है। इस कानून के जरिये मूल कानून में संशोधन करके अवैध रूप से देश में घुसे लोगों (घुसपैठिए) की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए देश में निवास करने की अवधि घटा दी गई है। यह कानून भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मनमाने तरीके से सिर्फ तीन देशों के छह धर्मावलंबियों को शामिल किया गया है और विशेष तौर पर एक धर्म और भाग को छोड़ दिया गया है।

भाजपा का आरोप, राहुल को रीलांच करने को रची गई हिंसा की साजिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संबित पात्रा ने कहा, शनिवार की रैली के अगले दिन हिंसा महज संयोग नहीं
- राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों की आड़ लेने को बताया निंदनीय

भाजपा ने नागरिकता कानून में संशोधनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर छात्रों की आड़ लेकर देश में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। पात्रा के अनुसार, रामलीला मैदान की रैली के अगले दिन ही देश के कई भागों में हुई हिंसा महज संयोग नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाया कि क्या कारण है कि शनिवार को राहुल गांधी को रीलांच करने के लिए कांग्रेस की रैली होती है और रविवार से ही आगजनी और तोड़-फोड़ की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा को हवा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के साथ ही भाजपा ने असद्दुदीन ओवैसी, आप के अमानतुल्लाह खान और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा।

पात्रा ने ओवैसी पर देश को तोड़ने वाले जिन्ना की तरह देश को बांटने की साजिश रचने और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर जिन्ना पदचिह्नों पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और एक समुदाय के वोट के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा की वकालत करने वाली ममता बनर्जी ने सोमवार को हिंदी में भाषण देकर असल में पूरे देश में उन्माद भड़काने की कोशिश की है।

भाजपा ने विपक्षी दलों पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए छात्रों को मोहरा बनाने की निंदा की। संबित पात्रा ने कहा कि दरअसल विपक्षी दलों को हर विषय पर सांप्रदायिक रंग देकर अराजकता फैलाने का साजिश रचने की आदत पड़ गई है। चाहे वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मामला हो, तीन तलाक का विषय हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो। सभी में विपक्ष को हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखने की आदत पड़ गई है। जबकि हकीकत यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का हिंदुस्तान के मुसलमान से न तो कोई लेना-देना है और न ही उनके अधिकारों पर कोई आंच ही आने वाली है।

किरण बेदी ने विवादित ढांचा विध्वंस नाटक का वीडियो अपलोड किया

बेंगलुरु, आइएएनएस : पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दक्षिण कन्नड़ जिले के एक स्कूल में बच्चों द्वारा विवादित ढांचा विध्वंस की नाटकीय प्रस्तुति का वीडियो साझा किया है। वायरल वीडियो में बच्चे भारत के नक्शे की तरह बैठ गए। बीच में कई बच्चे विवादित ढांचे के पोस्टर की तरफ बढ़े और उसे ध्वस्त किया। भगवा और सफेद कपड़ों में छात्रों ने पोस्टर ढहाने के बाद भगवा ध्वज लहराया और जय बजरंगबली, बोलो भारत माता की जय और जय हनुमान के नारे लगाए। कन्नड़ में एक कमेंट्री में राम जन्मभूमि और अन्य मुद्दों के बारे में बताया जा रहा है।

इसके साथ ही उपराज्यपाल ने एक और वीडियो साझा किया है जिसमें स्कूली छात्र अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार कर रहे हैं। मंगलुरु के समीप काल्लाडका गांव में स्थित श्रीराम विद्या केंद्र के वार्षिकोत्सव में रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के 3800 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। यह जानकारी किरण बेदी ने ट्वीट कर दी है।

स्कूल के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और किरण बेदी भी मौजूद थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काल्लाडका नेता प्रभाकर भट्ट इस स्कूल का संचालन करते हैं।

एचडीआइएल के प्रमोटर्स के विरुद्ध सात हजार पन्नों का आरोप पत्र

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सात हजार पन्नों का आरोपपत्र विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया है। ईडी ने इस मामले में एचडीआइएल के मालिक राकेश वधावन और उसके बेटे सारंग वधावन को मुख्य तौर पर दोषी माना है।

ईडी पहले ही पीएमएलए कानून के कई प्रविधानों के तहत वधावन बाप-बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने आगे की जांच के लिए अक्टूबर में इन दोनों को गिरफ्तार किया था। कंपनी ने बैंक से करीब 6700 करोड़ रुपये का लोन ले रखा है। सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों पर पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी। बैंक के पास करीब 16 लाख खाताधारक हैं। बैंक का कुल नौ हजार करोड़ रुपये का लोन है, जबकि 11,610 करोड़ रुपये जमा हैं। इस मामले में अभी तक बारह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीएमसी बैंक के कर्मचारी भी हैं।

इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि

पीएमसी बैंक घोटाला

- बैंक रिकॉर्ड से 10.5 करोड़ गायब, 50-55 लाख रुपये का हिसाब नहीं
- चेक जमा किए बिना दिए पैसे,कुल कर्ज का दो-तिहाई एचडीआइएल को

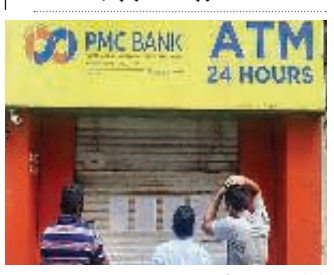

प्रतीकात्मक फोटो

बैंक की आंतरिक जांच टीम ने कहा है कि पीएमसी बैंक के रिकॉर्ड से कुल 10.5 करोड़ रुपये नकद गायब हैं।

टीम को घोटाले में आरोपित रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियों की ओर से जारी किए गए कई चेक मिले हैं। हैरानी की बात ये है कि कंपनी की ओर से जारी किए गए ये चेक बैंक में जमा ही नहीं किए गए। तब भी उन्हें नकद दे दिया गया है।

बैंक की आंतरिक जांच टीम के अनुसार उन्हें जो चेक मिले हैं, वे 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं। बाकी के 50-55 लाख रुपये का कोई हिसाब नहीं है। पिछले दो साल में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस को एचडीआइएल और ग्रुप की कंपनियों ने चेक भेजे थे, जो जमा नहीं किए गए लेकिन कंपनी को पैसे दे दिए गए थे। आशंका है कि थॉमस ने 50-55 लाख रुपये अपने पास रख लिए होंगे।

मामले में एक सूत्र ने बताया कि बैंक की तरफ से बांटे गए कुल कर्ज का दो-तिहाई हिस्सा सिर्फ एक ही कंपनी को दिया गया। उसने कहा कि हो सकता है कि बैंक साल 2008 से ही फर्जीवाड़ा कर रहा है। पिछले 10 सालों से हाउसिंग कंपनी एचडीआईएल को पैसे दिलाने के लिए बैंक ने कई डमी खाते खोले थे। बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह एचडीआइएल के बोर्ड में शामिल थे। बैंक की ओर से एचडीआइएल को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के तौर पर कितना कर्ज दिया गया, इसको उजागर नहीं किया गया था, जो नियम विरुद्ध है।

दुष्कर्म मामलों के त्वरित ट्रायल के लिए दो जजों की कमेटी गठित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं और अदालत में वर्षों लंबित न्याय पर देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे ने संज्ञान लिया है। उन्होंने देशभर में दुष्कर्म के लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण और चुस्त निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की कमेटी गठित की है। इस कमेटी में जस्टिस एमआर शाह और सुभाष रेड्डी शामिल हैं।

सूत्र बताते हैं कि जस्टिस बोबडे ने प्रशासनिक स्तर पर लिए गए निर्णय में दो न्यायाधीशों की निगरानी कमेटी गठित की है। यह कमेटी संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ समन्वय करके यह प्रयास करेगी कि दुष्कर्म के मुकदमे का ट्रायल एक वर्ष में निपटा दिया जाए। जिला अदालतें हाई कोर्ट के अधीन होती हैं। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या कर शव जलाने वाले चार आरोपितों के हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि न्याय और बदले में अंतर है। न्याय तत्काल नहीं हो सकता, लेकिन, मुख्य न्यायाधीश ने उसके बाद ही ऐसे मुकदमों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

हकीकत

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब की हालत खराब, हर ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति रोजाना 55 लीटर जलापूर्ति का लक्ष्य

नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में पेयजल संकट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

2.6 लाख गांव हैं उप्र में। ज्यादातर में रोजाना प्रति व्यक्ति 40 लीटर जलापूर्ति हो रही है

35 हजार से अधिक गांव बिहार में ऐसे हैं जहां लोगों को पानी की यह मात्रा भी नसीब नहीं हो पा रही है

3.5 हजार गांव पंजाब के ऐसे हैं जहां लोगों को जहरीले तत्वों से युक्त पानी पीना पड़ता है

प्रतीकात्मक फोटो

नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में ही शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई जरूरत से भी कम हो पाती है। ज्यादातर क्षेत्रों में प्रदूषित जलापूर्ति होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल से रोजाना 55 लीटर पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाती है और न ही शुद्ध जलापूर्ति हो रही है। जबकि इन राज्यों में नदियों का जाल है। पेयजल प्रबंधन में इन राज्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संसद में पूछे लिखित सवालों के जवाब में मंत्रालय ने विस्तार से ब्योरा दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े कुल 2.60 लाख गांवों में से ज्यादातर में प्रति व्यक्ति रोजाना 40 लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। दो हजार गांवों में तो इतना भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि एक हजार से अधिक गांवों के लोग अति प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। फिलहाल ज्यादातर गांवों में नल से पानी की आपूर्ति का बंदोबस्त नहीं है।

मानसून सीजन में नदियों के पानी लबालब रहने वाले बिहार में पेयजल की हालत ठीक नहीं है। कुल 1.10 लाख छोटे गांवों में से 70 हजार गांवों में प्रति व्यक्ति को रोजाना 40 लीटर पानी पहुंचाने का दावा किया गया है। 35 हजार से अधिक गांवों को पानी की यह मात्रा भी नसीब नहीं हो पा रही है। लगभग चार हजार गांवों के लोग प्रदूषित व घातक रसायन मिश्रित पानी पीने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल की हालत इन राज्यों से भी खराब है। यहां 1.07 लाख गांव हैं, जिनमें से 61 हजार गांवों को रोजाना प्रति व्यक्ति 40 लीटर जलापूर्ति का दावा है। 32 गांवों को यह भी मयस्सर नहीं है। 13 हजार से अधिक गांव में लोग खतरनाक रसायनयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उत्तरी राज्यों में पंजाब एक ऐसा राज्य है, जहां नदियों की संख्या अधिक है। लेकिन यहां भी पेयजल की सप्लाई कमोबेश वैसी ही है। यहां के 15 हजार गांवों में से 10 हजार में 40 लीटर प्रति व्यक्ति रोज पानी मिलता है। साढ़े तीन हजार गांवों की हालत बहुत दयनीय है, जहां के लोगों को जहरीले तत्वों से युक्त पानी पीना पड़ता है। इन राज्यों से होकर छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन जल प्रबंधन न होने की वजह से हालत खराब हो चुकी है।

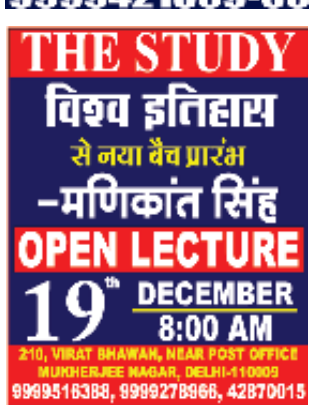

92.43 फीसद दिव्यांगों ने झारखंड के चौथे चरण में मतदान कर मिसाल पेश की है। चौथे चरण में 22 महिला, एक थर्ड जेंडर सहित 221 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 17 दिसंबर 2019

चार माह के भीतर अयोध्या में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण : शाह

किया वादा ▶ कहा, कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के मामले को लटकाया, आंतकियों पर नरम रही

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

केंद्रीय गृह मंत्री ने की पाकुड़ और गोड्डा में की चुनावी सभा

जागरण संवाददाता, गोड्डा

'अयोध्या में भगवान राम का भव्य गगनचुंबी मंदिर बनेगा। चार माह के भीतर इसके निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।' यह बातें केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहीं। वह सोमवार को झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इस मुद्दे को लटकाती रही है, जबकि दुनिया भर के रामभक्त सैकड़ों साल से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की मांग करते रहे हैं। कपिल सिब्बल का नाम लेते हुए शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप से भी सिब्बल यह अपील कर चुके हैं कि राम जन्मभूमि पर सुनवाई टाली जाए। झारखंड के संदर्भ ने शाह ने कहा कि मीर जाफर जैसे गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने इस इलाके में पांव जमाया। उन्हें खदेड़ने के लिए सिदो-कान्हू को शहादत देनी पड़ी। आज फिर मीर जाफर जैसा कोई आपका जनप्रतिनिधि न बन जाए, इसलिए इनको पहचानें और सोच-समझकर मतदान करें।

आदिवासियों की जिंदगी सुरक्षित की

गृहमंत्री ने कहा कि साहिबगंज से एशिया-यूरोप तक व्यापार होता था। कांग्रेस व झामुमो ने इसे समाप्त कर दिया। मोदी ने फिर इसे वैश्विक पहचान दिलाई। झारखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाकर आदिवासियों की जिंदगी सुरक्षित की। कहा कि चुनाव के बाद आदिवासियों व दलितों के आरक्षण में कटौती किए बिना पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा।

झारखंड के साहिबगंज में भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

आलिया, मालिया, जमालिया ले जाते थे सैनिकों के सिर : सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के शासनकाल में पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा हुआ है। आतंकियों को हमने घर में घुसकर मारा है। पूर्व में आलिया, मालिया व जमालिया देश में घुसकर सैनिकों का सिर ले जाते थे। मोदी के हुक्म पर सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा। प्रश्न किया कि क्या राहुल बाबा व हेमंत सोरेन की सरकार में देश सुरक्षित रहेगा? पांच वर्ष में मोदी और रघुवर सरकार ने झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। यह कारवां अब रुकेगा नहीं। झारखंड में बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। भीड़ से संवाद करते हुए संताल परगना की सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करवाने का संकल्प दिलाया।

हमने नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया : अमित शाह ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने, सर्जिकल स्ट्राइक, सीएबी, एनआरसी, राम मंदिर को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया। गोड्डा में 37 मिनट के भाषण में उन्होंने राहुल को निशाने पर रखा। कहा, नक्सलवाद के कारण यहां विकास राह से भटक गया था। डबल इंजन की सरकार ने उसे उखाड़कर फेंका।

हेमंत पर भी साधा निशाना : शाह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस की गोद में बैठकर सीएम बनना चाहते हैं। जब झारखंड के युवक अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन पर गोलियां चलाई गईं। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। अगर हेमंत सोरेन को यह याद नहीं हो, तो वे अपने पिताजी से पूछ लें। कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, तब झारखंड बना। झारखंड को अटल जी ने बनाया और मोदी ने संवारा।

कई सीटों का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं ओवैसी

राज्य ब्यूरो, रांची

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद कुछ अन्य राज्यों में भी सफलता का स्वाद चख रहे एआइएमआइएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन) की नजर अब हिंदी पट्टी के राज्यों पर है। बिहार के हालिया विधानसभा उपचुनाव में सीमांचल की एक सीट हासिल करने वाले एआइएमआइएम प्रमुख असदुदीन ओवैसी की महत्वाकांक्षा बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐन पहले राज्य का दौरा कर संभावनाओं पर गौर किया और 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए।

आरंभ में ओवैसी को नजरंदाज करने की कोशिश की गई, लेकिन एक के बाद एक चार चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक गलियारे में अब यह महसूस किया जाने लगा है कि वे कई सीटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि सीधी लड़ाई भाजपा और विपक्षी गठबंधन के बीच है। अल्पसंख्यकों का भरोसा विपक्षी गठबंधन पर है, ऐसे में एआइएमआइएम महज वोटकटवा बनकर रह जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव भी अपनी सभाओं में ओवैसी पर निशाना साधते हैं और उन्हें भाजपा का एजेंट बताते हैं। लेकिन ओवैसी इन तमाम राजनीतिक आरोपों को दरकिनार करते हुए अपनी मुहिम में जुटे हैं। उनकी नजर अल्पसंख्यकों मतों पर है, जो कई सीटों पर हार-जीत के लिए खासा मायने रखती है। ओवैसी अपनी सभाओं में भाजपा और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हैं। अपनी सभाओं में ओवैसी तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं- अब डर से नहीं, नई उम्मीद और अपनी बराबरी के हक के लिए वोट करना है। मैं आपकी आवाज को मजबूत बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे इत्तेहाद को मजबूत बनाने आया हूं। दिलों को जोड़ने आया हूं। मैं आपको लीडर बनाने आया हूं।

14 सीटों पर खड़े किए हैं एआइएमआइएम ने प्रत्याशी

इन सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी

विश्रामपुर, गढ़वा, जमशेदपुर पश्चिम, धनवार, मांडू, हजारीबाग, बरकट्ठा, गांडेय, मधुपुर, महगामा, राजमहल, सारठ, बोकारो और डुमरी।

ओवैसी की सभाओं में मुस्लिमों खासकर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो एक तरफ विपक्षी गठबंधन, जिसकी नजर अल्पसंख्यक वोट पर है, को असहज कर रही है। वहीं, भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए पर्याप्त है। जिन 14 सीटों पर ओवैसी ने प्रत्याशी दिए हैं, वहां वे चुनावी गणित को बिगाड़ने का माद्दा रखते हैं।

गठबंधन की सरकार बनी तो हर घर एक नौकरी : आरपीएन

जागरण संवाददाता, जामताड़ा : प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि भाजपा की पांच साल की सरकार में नौकरी मिलनी तो दूर की बात, लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। भाजपा का दावा था कि उनकी सरकार बनी, तो झारखंड का विकास होगा। लेकिन, विगत पांच साल में भूख से मौत, किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ही बढ़ी है। अगर हमारी सरकार बनी, तो हर घर में एक नौकरी जरूर देंगे। आरपीएन सिंह सोमवार को गोलपहाड़ी मैदान में महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही।

उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश नौकरी नहीं दे पाए, तो उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले पांच सालों में राज्य के गरीबों की जमीन लूटने का काम किया है। पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका पर लाठीचार्ज को याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी है। लाठियों के बल पर आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि रघुवर दास ने 11 लाख राशन कार्ड को रद कर दिया। स्थिति यह है कि राज्य में भूख से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। जामताड़ा विस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि महागठबंधन से भाजपा घबराई हुई है।

न्यूज गैलरी

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी आज बरहेट में करेंगे जनसभा

रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संताल परगना के बरहेट में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। पीएम की जनसभा सिदो-कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में दोपहर 12 बजे होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह उनकी आखिरी जनसभा होगी। संताल परगना प्रमंडल की 16 सीटों के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान नौ जनसभा की हैं। (राब्यू)

प्रियंका गांधी 18 को आएंगी पाकुड़ में

रांची : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 18 दिसंबर को पाकुड़ में पार्टी प्रत्याशी आलमगीर आलम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने यह जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी ने झारखंड का रुख किया है। हालांकि, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य में पांच जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने तैयारी आरंभ कर दी है। (राब्यू)

सिर्फ भाजपा दे सकती है रामराज : योगी

जासं, जामताड़ा

रामराज शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है, जिसे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को झारखंड के जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को आधार बनाकर जनभावनाओं से जुड़ने की कोशिश की।

वहीं, नागरिकता कानून की चर्चा करते हुए राष्ट्रवाद को उभारा। देश में आतंकवाद, अलगाववाद, अराजकता, बदहाली और भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही। इस दौरान सभा उपस्थित लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या अनुच्छेद 370 हटाए जाने को आप ठीक मानते हैं, मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान की छाती पर मूंग दलने को बेहतर समझते हैं, अगर हां, तो आप भाजपा को वोट करें।

उन्होंने स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि इरफान आपको राम मंदिर निर्माण में सहयोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन, अगर जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल विधायक बनते हैं, तो हमें उम्मीद है कि मंदिर निर्माण के लिए एक शिला लेकर वे अयोध्या अवश्य पहुंचेंगे।

अराजकता फैला रही कांग्रेस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने संशोधित नागरिकता कानून पर कहा कि यह भारत की उदार नीति का प्रमाण है, जो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। दूसरी ओर, कांग्रेस व उसके सहयोगी दल इसे राजनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं।

साहिबगंज में भाजपा की चुनावी सभा को संबोधित करते उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

संताल में हेमंत की घेराबंदी में जुटी भाजपा

राज्य ब्यूरो, रांची

पीएम मोदी मंगलवार को संताल परगना प्रमंडल के भोगनाडीह में जनसभा करेंगे। भोगनाडीह संताल के अमर शहीद सिदो-कान्हू की जन्मस्थली है। विधानसभा क्षेत्र बरहेट है, जहां से भाजपा के परंपरागत प्रतिद्वंद्वी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 15 दिसंबर को उन्होंने दुमका में रैली की थी। हेमंत दुमका से भी चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री की दुमका के बाद बरहेट में जनसभा के मायने स्पष्ट है। भाजपा ने हेमंत को दुमका या बरहेट के रास्ते रांची पहुंचने से रोकना चाहती है और इसके लिए मजबूत घेराबंदी की जा रही है। संताल परगना झामुमो का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से भाजपा यहां सेंध लगाने में काफी हद तक सफल रही है।

2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को संताल की 18 में से सात सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि झामुमो को छह पर। हेमंत सोरेन वर्ष 2014 के विस चुनाव में दुमका व बरहेट से चुनाव लड़े थे। दुमका में उन्हें भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी ने पांच हजार से अधिक वोटों से मात दी थी, जबकि बरहेट में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को हराया था।

राहुल के भाषण पर चुनाव आयोग को उपायुक्त ने भेजी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के गोड्डा और साहिबगंज की जनसभाओं में दिए गए वक्तव्य पर गोड्डा उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। उपायुक्त ने राहुल गांधी के भाषण की रिकार्डिंग के आधार पर उनके भाषण की प्रिंटेड कॉपी आयोग को भेजी है। कुल तीन पन्ने में भेजी गई रिपोर्ट में राहुल गांधी के भाषण की ही बाते हैं। उपायुक्त ने इसमें अपना कोई मंतव्य नहीं दिया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से 12 दिसंबर को राहुल गांधी के गोड्डा में दिए भाषण को अपमानजनक और शर्मसार बताते हुए शिकायत की थी।

राहुल गांधी। फाइल

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमारचौबे से मुलाकात कर राहुल गांधी की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से इसपर उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

झारखंड में चौथे चरण के लिए 62 .54 फीसद मतदान हुआ

चौथे चरण के चुनाव में सोमवार को बोकारो विधानसभा के उच्च विद्यालय हैसाबातू स्थित बूथ में मतदान करने के लिए पंक्ति में खड़ी मुस्लिम महिलाएं। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में चौथे चरण के लिए 15 विस सीटों के लिए सोमवार को 62.54 फीसद मतदान हुआ। इस चरण में धनबाद जिले की 6, बोकारो जिले की 2, गिरिडीह की 5 और देवघर जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। यहां मतदान संपन्न होने के साथ ही दो मंत्री, सात पूर्व मंत्री तथा 14 वर्तमान विधायकों सहित कुल 221 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इनमें 198 पुरुष तथा 22 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। पहली बार एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे। इन इलाकों में 2014 की तुलना में इस बार 2.12 फीसद कम वोट पड़े। पिछले चुनाव में 64.66 फीसद वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चंदन कियारी में सर्वाधिक 74.50 प्रतिशत मतदान हुआ। बोकारो, झरिया और धनबाद मतदान में सबसे पीछे रहे।

उत्तराखंड में किसानों को नए साल में मिलेगा फसलों का ज्यादा समर्थन मूल्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून : किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार नए वर्ष में उन्हें सौगात देने जा रही है। इसके तहत छह पारंपरिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने के मद्देनजर खाका तैयार कर लिया गया है। इससे किसानों को सरकार से बेहतर दाम पर उपज की बिक्री की गारंटी मिलेगी। वहीं, फसलोत्पादन बढ़ाने को भी वे प्रेरित होंगे। कृषि उत्पादों की खरीद के मद्देनजर सरकार ने मंडी परिषद में रिवॉल्विंग फंड के गठन का निर्णय लिया है। यह विधेयक विस में पारित हो चुका है, जिसे राजभवन की मंजूरी का इंतजार है। रिवॉल्विंग फंड का उपयोग मंडी समितियों द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले कृषि उत्पादों के भुगतान करने में किया जाएगा। अब इसकी अगली कड़ी में राज्य में होने वाली परंपरागत फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कवायद लगभग पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक जिन परंपरागत फसलों के समर्थन मूल्य प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें छह फसलें मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, कालाभट, और राजमा शामिल हैं।

'मैं भी सावरकर' लिखी टोपी पहन पहुंचे भाजपा विधायक

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▶ नागपुर में सोमवार से राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई

▶ नेता प्रतिपक्ष फड़नवीस व पार्टी विधायकों ने किया प्रदर्शन

महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को नागपुर में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (बाएं से तीसरे) की अगुआई में भाजपा विधायकों ने 'मैं भी सावरकर' लिखी टोपी पहनकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर संबंधी बयान पर विरोध जताया। एएनआइ

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सावरकर संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में आक्रामक दिखी। सभी भाजपा विधायक 'मैं भी सावरकर' लिखी भगवा टोपी लगाकर आए और राहुल से माफी मांगने की मांग उठाते दिखे।

महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में सोमवार से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। भाजपा के तीखे तेवर पहले ही दिन दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस सहित सभी विधायक मैं भी सावरकर लिखी भगवा टोपी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा एवं विधान परिषद के दरवाजे पर बैठकर प्रदर्शन किया। वे राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने सदन में कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग करते रहेंगे। बता दें कि दो दिनों पूर्व दिल्ली में भारत बचाओ रैली के दौरान राहुल ने मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, कहकर स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी की थी। हालांकि, शिवसेना सांसद संजय राऊत ने इस टिप्पणी से किनारा करते हुए सावरकर का अपमान न करने की सलाह कांग्रेस को दी थी। लेकिन, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना पर निशाना साधने का मौका तो अब भाजपा को मिल ही गया है। इसका लाभ लेती हुई भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ शिवसेना अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरुद्ध भी नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए शाम को एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं आज भी हिंदू हूं। भाजपा से गठबंधन तोड़कर मैंने धर्मांतरण नहीं कर लिया है। लेकिन, हिंदुत्व के नाम पर देश में हंगामा खड़ा करनेवालों को हिंदू जनता माफ नहीं करेगी।' बता दें कि कांग्रेस-राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने से पहले शिवसेना भी सावरकर पर की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर आक्रामक भूमिका निभाती रही है।

सावरकर पर चर्चा को कार्यवाही से बाहर करने पर भड़के भाजपाई

मुंबई, मिड डे : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सावरकर पर चर्चा के कुछ अंश को कार्यवाही से बाहर करने का फैसला किया। इससे भाजपा विधायक भड़क गए। वे प्रदर्शन करते हुए वेल में पहुंच गए और वहां बैनर लहराया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी भाजपा विधायक प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अभूतपूर्व अन्याय है। विपक्ष ने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया।

सवर्ण कार्ड के साथ आगे बढ़ रही लोजपा

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ नए पदाधिकारियों की सूची में आधे से अधिक सवर्ण

चिराग पासवान। फाइल

राजनीतिक दलों के बीच खत्म हो रहे वोट बैंक केंद्रित मिथक के साथ लोजपा भी पूरी गति के साथ तालमेल बिठाने का जतन कर रही है। पहली बार राजद ने अगड़ी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। भाजपा में अति पिछड़े की बात तेजी से चल रही। ऐसे में अपने वोट बैंक से परे लोजपा ने पूरी रणनीति के साथ सवर्ण कार्ड को आगे बढ़ाना आरंभ किया है। बिहार में सवर्णों का वोट बैंक सत्रह से बीस प्रतिशत का है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख लोजपा ने हाल ही में दस पदाधिकारियों की सूची जारी की है जिसमें आधे से अधिक सवर्ण हैं। इसके साथ ही लोजपा प्रायः अपने सभी कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र कर रही है कि आर्थिक दृष्टि से सवर्णों के लिए आरक्षण की जो वैधानिक व्यवस्था की गई है उसे सबसे पहले उनके दल ने ही आगे किया। लोजपा के पदाधिकारियों की नयी सूची जारी होने के दो दिन बाद लोजपा सप्रीमो व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का यह बयान आया कि अगड़ी जाति के नेताओं ने पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगड़े वर्ग के नेताओं की भूमिका आरंभ से अहम रही है। यह वक्तव्य अनायास ही नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार चिराग पासवान ने पिछले हफ्ते दस उपाध्यक्ष बनाए। इनमें सात उपाध्यक्ष अगड़ी जाति के हैं। इनमें सुनील पांडेय, राजू तिवारी, नूतन सिंह, हुलास पांडेय, विनोद कुमार सिंह, विरेश्वर सिंह और उषा शर्मा शामिल हैं। पासवान जाति के लोगों को अपना वोट बैंक समझने वाली लोजपा ने इस सूची में केवल दो पासवान क्रमशः रामविनोद पासवान और संजय पासवान को ही शामिल किया। एक उपाध्यक्ष राजकुमार साह पिछड़ी जाति के हैं। सवर्ण जाति के धुरंधरों के बूते लोजपा सदस्यता अभियान चलाएगी। इसी बहाने वह अपनी जमीन की तलाश भी करेगी। इन्हें प्रमंडल के हिसाब से कमान सौंपी गई है। जवाबदेही यह दी गई है कि यह परखें कि कौन-कौन सी सीट के लिए लोजपा अपनी दावेदारी कर सकती है।

आंख मूंद कर थोड़े ही समर्थन कर देंगे एनआरसी का : चिराग

राज्य ब्यूरो, पटना : लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के समर्थन से जुड़े एक प्रश्न पर कहा कि आंख मूंद कर थोड़े ही समर्थन कर देंगे एनआरसी का। अभी यह आया कहां है सो इसे इतना तूल दिया जा रहा है। एनआरसी के संबंध में बिल आने पर लोजपा उसका अध्ययन करेगी और राष्ट्र व राज्य हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चिराग ने कहा कि लोजपा ने एनआरसी पर आरंभ से ही अपने स्टैंड को सार्वजनिक रखा है। यह कहां और कैसे लागू होगा इस तरह का कोई डाक्यूमेंट ही नहीं है अभी। वैसे इस पर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। वहीं नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर चिराग ने कहा कि कानून में शरणार्थियों की बात है। कानून में संबंधित देश में रह रहे अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। मेरी राय है कि अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त वहां रह रहे बहुसंख्यकों का भी ख्याल रखने पर सोचना चाहिए।

बढ़ा विवाद

सचिवालय थाने में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया आवेदन, पुलिस से घर पर हुए विवाद की जांच की मांग की

राबड़ी ने ऐश्वर्या पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना

ऐश्वर्या का आरोप-दहेज में कार के लिए रोज ताना मारती थीं राबड़ी

जागरण संवाददाता, पटना : ऐश्वर्या राय ने सास, पति और ननद पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में ऐश्वर्या ने कहा कि दहेज में पति को कार नहीं देने के कारण शादी के बाद से ही मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा था। राबड़ी देवी रोज ताना मारती थी और पति के कहने पर ननद मीसा भारती भी प्रताड़ना देती थी। ऐश्वर्या की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। ऐश्वर्या की लिखित शिकायत पर महिला थाने में प्रताड़ना, मारपीट, और दहेज मांगने का मामला दर्ज किया गया है।

बहू ऐश्वर्या के खिलाफ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सचिवालय थाने में लिखित तहरीर दी है। रविवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को लेकर जो कुछ हुआ था, उस मामले की उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की मांग पुलिस से की है। अपने आवेदन में राबड़ी ने लिखा है कि 15 दिसंबर की शाम अपने आवास में बैठी थीं। उसी दौरान बहू ऐश्वर्या कमरे से निकली और अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जान बचाने के लिए घर पर तैनात सुरक्षा बलों को आवाज दी। वे पहुंचे और बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। इस दौरान बहू असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रही थी। पूर्व में भी वह उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रही है। जबकि कोर्ट में लिखकर दिया था कि कोई गलती नहीं करेगी।

चश्मदीद गवाह हैं राजद विधायक : राबड़ी देवी ने घटना के चश्मदीद गवाह राजद विधायक शक्ति सिंह यादव को बनाया है। कहा गया है कि उस वक्त वह वहीं थे। तहरीर में इस बात का जिक्र किया है कि अक्टूबर में भी ऐश्वर्या ने उनके कमरे के दरवाजे पर शाम को लात से धक्का मारा था। दरवाजे पर ही कूड़ा फेंक दिया था। यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उन्होंने इसकी फुटेज पहले ही सचिवालय थाने को सिपुर्द कर दी थी। थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

शक्ति ने कहा, ऐश्वर्या ने राबड़ी पर डंडे से हमला किया : शक्ति के मुताबिक राबड़ी ने उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी लेने के लिए रविवार को अपने आवास पर बुलाया था। शाम का वक्त था। परिसर में जलते अलाव के पास बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। इसी दौरान ऐश्वर्या आईं और चिल्लाने लगीं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, किंतु कोई असर नहीं हुआ। राबड़ी के सामने आग में जलती हुई लकड़ी को खींचकर ऐश्वर्या ने पटक किया। कुछ चिंगारी राबड़ी देवी पर भी पड़ीं। राबड़ी ने ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान महिला सुरक्षाकर्मी ने मामले को शांत कराना चाहा तो ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर लात चलाने की कोशिश की। वह आपे से बाहर थी। सुरक्षा कर्मी ने उसे जैसे-तैसे संभाला।

सुशील मोदी से मिल बताएंगे उपेंद्र, बिहार के लिए क्या-क्या किया

राज्य ब्यूरो, पटना : रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ होकर दिल्ली से पटना वापस आ गया हूं। आप मुझे मिलने का समय बताएं ताकि मैं आपको इस संबंध में पूरी जानकारी दे सकूं कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए मैंने बिहार के लिए क्या क्या किया है। शिक्षा में सुधार और केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन की मांग को लेकर पिछले महीने उपेंद्र ने आमरण अनशन किया था। महागठबंधन के नेताओं के आग्रह पर आमरण अनशन उन्होंने समाप्त किया लेकिन इस बीच तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। फिर दिल्ली एम्स इलाज के लिए रेफर किया गया था। मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री रहते हुए बिहार के लिए कुछ नहीं किया।

हिंसा रोकने को गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने राज्यों से शांति-व्यवस्था बनाए रखने और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश के कई इलाकों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की सूचना मिली है। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और आम लोगों के जान-माल का नुकसान रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग भी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों और हिंसा की फर्जी खबरें रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रवासियों को स्वत : नहीं मिलेगी नागरिकता

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि नागरिकता संशोधन कानून में वर्णित किसी भी प्रवासी को स्वत : भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। हर प्रवासी को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना होगा। साथ ही यह कानून किसी भी सूरत में भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए अन्य सभी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसके लिए नागरिकता नियमों को जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा।

मोदी सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ छेड़ा युद्ध : सोनिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिंसक और विभाजक हो गई है। उसने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ध्रुवीकरण की पटकथा लिखी है। भाजपा सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। उसने राजनीतिक लाभ के लिए अस्थिरता और धार्मिक तनाव की स्थिति पैदा की है। उन्होंने कहा, 'लेकिन जब युवा शक्ति जागती है तो परिवर्तन की नई तरंग पैदा करती है। छात्रों पर पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई यह संकेत देती है कि मोदी सरकार जाने वाली है।' सोनिया ने कहा, 'शांति और सद्भाव कायम रखना, सुशासन और संविधान की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा सरकार ने अपनों के ही खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।

बंगाल में एआइएमआइएम के दो नेता गिरफ्तार

जासं, कोलकाता : सीएए के विरोध के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम के दो शीर्ष नेताओं जमीरुल हसन और अनवर पाशा को क्रमश : कोलकाता और पूर्व मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। उन पर गैरकानूनी रूप से भीड़ एकत्र करने, मार्ग अवरुद्ध करने, षड्यंत्र रचने, सरकारी कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। गौरतलब है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आला अफसरों के साथ नवान्न में बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एआइएमआइएम जैसे किसी भी कट्टरपंथी संगठन को राज्य में बैठक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने एआइएमआइएम का नाम लिए बगैर कहा था कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। उधर, एआइएमआइएम की ओर से 18 दिसंबर को सीएए का विरोध करने के लिए धर्मतला में सभा आयोजित की गई है।

हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : बिस्वसर्मा

संजय मिश्र, गुवाहाटी

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम में हुए आंदोलन के दौरान भारी हिंसा को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद असम की भाजपा सरकार ने भी पूर्वोत्तर की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वसर्मा ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक विशेष राजनीतिक दल ने अराजक तत्वों के जरिये विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा कराई।

राज्य सरकार नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में हिंसा करने वाले 190 अराजक तत्वों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सख्ती के चलते हिंसा थम गई है, लेकिन उपद्रवियों को मौका नहीं देने के लिए गुवाहाटी समेत कई जिलों में रात का कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी अभी जारी है। सूबे में विरोध प्रदर्शन भी जारी है और सोमवार को सत्याग्रह आंदोलन के तहत लोगों ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। विरोध प्रदर्शन का हिंसक दौर थमने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रही राज्य सरकार ने सोमवार को इस आंदोलन को समर्थन दे रहे राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा करने

गुवाहाटी में सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वसर्मा। एएनआइ

का प्रयास किया। सोनोवाल सरकार में नंबर दो हेमंत बिस्वसर्मा ने नागरिकता कानून में संशोधनों के बाद गुवाहाटी में पहली प्रेसवार्ता में कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें कई लोग एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हैं। उन्होंने उस पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर उनका साफ इशारा कांग्रेस की ओर था। हिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले तत्वों के खिलाफ 136 मुकदमे दर्ज करने की बात भी उन्होंने कही। हेमंत बिस्वसर्मा ने गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस से जुड़े लोगों का भले ही सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य रिपुल बोरा ने माना कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुवाहाटी और अपर असम के जिलों डिब्रूगढ़, जोरहाट और गोलाहाट आदि में यह गिरफ्तारियां हुई हैं। रिपुल बोरा ने युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआइ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को भाजपा और आरएसएस की साजिश करार दिया।

नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने के बहाने हिंसा करने वाले अराजक तत्वों में अधिकतर एक समुदाय विशेष के बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। नए कानून के तहत जाहिर तौर पर ऐसे लोगों की नागरिकता की राह बंद हो गई है। हेमंत बिस्वसर्मा ने अपनी प्रेसवार्ता के दौरान गिरफ्तार कुछ आरोपितों के नाम का जिक्र कर कुछ ऐसा ही संकेत दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून से अधिकतम 5.42 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ लोगों द्वारा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इससे एक करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और बांग्लादेश से असम में घुसपैठ की बाढ़ आ जाएगी। आंकड़े का स्रोत पूछने पर उन्होंने कहा कि एनआरसी की अंतिम सूची में जिनका नाम शामिल नहीं हुआ उनके आकलन से यह उभरकर सामने आया। इस बीच, असम भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास का कहना है कि नागरिकता कानून के खिलाफ माहौल का सियासी फायदा उठाने के लिए बांग्लादेशी अल्पसंख्यक घुसपैठियों के जरिये हिंसा कराई गई है। दास के मुताबिक इस हिंसा में कांग्रेस और वामपंथी दलों से जुड़े संगठनों का हाथ है। उनका मकसद हालात का राजनीतिक फायदा उठाना है।

एजीपी भाजपा से समर्थन वापस ले सकती है : महंत

गुवाहाटी, एएनआइ : असम में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) के विधायक और पूर्व सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में नागरिकता बिल का समर्थन करके गलती की है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी असम सरकार से समर्थन वापस ले लेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार में असम गण परिषद के तीन मंत्री हैं। सहयोगी दल के कुल 12 विधायक हैं। एजीपी नेता प्रफुल्ल कुमार महंत ने सोमवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी असम सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि सीएए असम की जनता के विरुद्ध है। वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उन लोगों का समर्थन करेंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दायर की है। हम सीएए का समर्थन नहीं करेंगे यह असम समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बिल का संसद के दोनों सदनों में समर्थन किया था। जबकि पार्टी इसका विरोध वर्ष 2015 से ही कर रही है। महंत ने आगे कहा कि सरकार को मौजूदा हालात सुधारने चाहिए। सरकार गोलीबारी करके असमिया लोगों की आवाज नहीं दबा सकती है।

एक-दो दिन में लौट आएंगी असम में तैनात टुकड़ियां : सेना

जागरण संवाददाता, कोलकाता

सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि तेजी से सुधर रहे हालात के मद्देनजर असम में तैनात सेना की टुकड़ियों को एक-दो दिनों में बैरकों में वापस बुला लिया जाएगा। सीएए को लेकर हिंसक विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बने असम में पिछले चार दिनों से सेना की टुकड़ियां तैनात हैं। चौहान ने कहा कि यह राज्य प्रशासन का अधिकार है कि अगर वह किसी स्थिति को संभालने में विफल रहती है तो सेना से मदद मांग सकती है। पिछले चार दिनों में सेना की टुकड़ियों की न सिर्फ असम बल्कि त्रिपुरा में भी तैनाती की गई है। कुछ को मेघालय में भी तैयार रहने को कहा गया है, हालांकि उन्हें फिलहाल तैनात नहीं किया गया है।

चौहान विजय दिवस के मौके पर फोर्ट विलियम मुख्यालय में विजय स्मारक पर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों के निशाने पर शाह समेत कई मंत्रियों के आवास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय इलाके में रविवार को उपद्रव के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा केंद्रीय मंत्रियों के आवासों को निशाना बनाने की आशंका जाहिर की है। इसके बाद पुलिस ने उन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। मंत्रियों के निवास और कार्यालय पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, खुफिया विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर हंगामा कर सकते हैं। विजय चौक, इंडिया गेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नए और पुराने पुलिस मुख्यालय के समीप भी उत्पात मचा सकते हैं।

इसके बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष वैन के साथ-साथ नई दिल्ली जिला त्वरित प्रतिक्रिया दल को सतर्क कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशनों के आसपास सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए हैं। वहीं, पुलिस की अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है। महिला पुलिस कर्मियों और यातायात पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया है।

सीएए के नाम पर उपद्रव जारी, उप्र में भी बढ़ीं घटनाएं

बढ़ा तनाव ▶ दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि में विरोध प्रदर्शन में चेहरा ढक कर शामिल हो रहे लोग

उप्र के मऊ और नदवा कॉलेज में उग्र प्रदर्शन, बरेली और देवबंद में सुरक्षा कड़ी, सहारनपुर में इंटरनेट सेवा बंद

जेएनएन, नई दिल्ली

- बंगाल में कई स्थानों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन, कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की छुट्टी रद
- मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में भी छात्र उतरे विरोध में, आइआइटी चेन्नई के छात्रों ने किया विरोध का आह्वान

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नाम पर दिल्ली सहित कई स्थानों पर सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), लखनऊ के नदवा कॉलेज और इंटीग्रल विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए, जबकि मऊ में उग्र प्रदर्शन हुआ। बंगाल में रेल और सड़क यातायात को ठप कर तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद में मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और आइआइटी चेन्नई के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली के जामिया विवि को पांच जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही छात्राओं को हॉस्टल छोड़ने के लिए भी कहा गया है। यहां प्रदर्शनकारियों ने कवरेज करने पहुंचे मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में दो मीडियाकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। एक महिला रिपोर्टर से बदसुलूकी की गई और उनका कैमरा व मोबाइल फोन लूटने का प्रयास किया गया। सुबह आठ बजे से ही विश्वविद्यालय के गेट नंबर सात पर शुरू में तो करीब 200-300 प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने मानव श्रृंखला बना रखी थी, लेकिन जैसे-जैसे दोपहर होती गई, यहां पर छात्रों और जामिया नगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आने वालों लोगों की भीड़ बढ़ती गई। वहीं छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने सोमवार को जामिया विवि का टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ भी उतर आया। आरोप लगाया कि रविवार को पुलिस ने कैंपस की लाइब्रेरी व शौचालय में घुसकर छात्रों की पिटाई की। आंदोलनकारियों के समर्थन में विवि स्टाफ ने मार्च भी किया। सोमवार को भी प्रदर्शन में छात्रों से इतर आए लोग बड़ी संख्या में चेहरा ढक कर शामिल हुए। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मऊ में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और पथराव शुरू कर दिया, जिससे गुरिल्ला युद्ध के हालात पैदा हो गए। बवालियों ने दो बसों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस व मीडियाकर्मियों की गाड़ियों में आग लगा दी। दक्षिण टोला थाने में घुसकर दीवार गिराने के साथ गाड़ियों को भी जलाने का प्रयास किया। हालात पर काबू पाने के लिए धारा-144 के साथ ही पूरे जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल द्वारा पैदल मार्च की घोषणा के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। सहारनपुर में सोमवार को इंटरनेट सेवा बंद रही। देवबंद में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दारुल उलूम कैंपस के छात्रों ने नारेबाजी की। अलीगढ़ में छात्रों के समर्थन में भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला बोलने के बाद एएमयू को खाली करा लिया गया है। एहतियातन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छुट्टी कर दी गई।

बंगाल : टायर जलाकर रेल और सड़क यातायात किया ठप

बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर रेल और सड़क यातायात को ठप कर दिया। कई रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। एहतियातन सोमवार को भी कई ट्रेनों को रद कर दिया गया। अफवाहें फैलने से रोकने के लिए हावड़ा सहित छह जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रही। हिंसा से निपटने के लिए राज्य पुलिस ने टोल फ्री नंबर शुरू किया है। हावड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोलकाता के राजारहाट, न्यूटाउन और कॉलेज स्ट्रीट में सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सोमवार को लखनऊ में नदवा कॉलेज के छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के अंदर से छात्रों द्वारा किए जा रहे पथराव से बचने की कोशिश करते पुलिसकर्मी। रंगनाथ तिवारी

नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर संघ की निगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संघ के अनुसार अलग-थलग पड़ते जा रहे संशोधनों का विरोध करने वाले
- केरल और बंगाल में भी विरोध को नहीं मिल रहा है जनसमर्थन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गहरी नजर रखे हुए है। संघ के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इसका विरोध करने वालों को जनता स्वीकार नहीं करेगी और वे खुद ही अलग-थलग पड़ जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंगाल और केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार विरोध प्रदर्शन का आयोजन जरूर कर रही है, लेकिन जनता का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है।

संघ (आरएसएस) ने आधिकारिक रूप से नागरिकता कानून में संशोधनों का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन वह इस पर हो रहे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों के बीच फंसने से बच रहा है। यही कारण है कि हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ संघ के किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश की जनता भली भांति समझ रही है कि इन संशोधनों से यहां के नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसका विरोध करने वाले कहीं न कहीं से जेहादी मानसिकता का समर्थन कर रहे हैं। केरल और बंगाल में विरोध प्रदर्शनों को जनता का साथ नहीं मिलने का उदाहरण देते हुए संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद विरोध रैली की अगुआई की, लेकिन इस रैली में पांच हजार से भी कम लोग मौजूद थे और उनमें भी अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इसी तरह केरल में सत्तारूढ़ माकपा, विपक्ष में बैठी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नागरिकता कानून में संशोधनों के खिलाफ मंगलवार को बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद के खिलाफ बनते हुए जनमानस को देखकर पहले माकपा और बाद में कांग्रेस व मुस्लिम लीग को भी बंद के आह्वान को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा।

सीएए पर हिंसा में सिमी और पीएफआइ का हाथ

नई दिल्ली, आइएएनएस : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में देशभर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय के साथ साझा की गई ताजा खुफिया रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों के साथ ही प्रतिबंधित कट्टरपंथी और आतंकवादी इस्लामी संगठनों सिमी और पीएफआइ पर संदेह जाहिर किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते मंत्रालय के साथ साझा की गई रिपोर्ट में कहा गया कि यह उन लोगों की करतूत है, जो सरकार के कदम के खिलाफ हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, 'कुछ राजनीतिक दलों ने विभिन्न स्थानों पर हिंसा को भड़काया, जिससे चरमपंथी और उग्रवादी इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) और इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के स्लीपर सेल को मौका मिला।'

उन्होंने कहा, 'इनका उद्देश्य देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बाधित करना है।' चूंकि यह अधिनियम इसी तरह के राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ जाएगा, इसलिए वह देश में शांति को बाधित करना चाहते हैं।

- खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से साझा की अपनी रिपोर्ट
- सिमी कुछ राजनीतिक दलों की शह पर स्लीपर सेल सक्रिय करने में जुटा

उल्फा भी कर रहा प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल

नई दिल्ली, आइएनएस : प्रतिबंधित उल्फा संगठन (युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम) के नेताओं ने नागरिकता कानून, 2019 के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल अपना हित साधने में किया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार सीएए और एनआरसी के खिलाफ उल्फा नेता अरुणोदय दहोतिया ने अपने गुर्गों से कहा है कि वह असमिया लोगों को इस बात के लिए सतर्क करें कि गैर असमिया लोग अल्पसंख्यकों के इलाकों के पास कोई कामकाज न करें। लिहाजा, देश की केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। प्रतिबंधित संगठन ने असम सरकार को भी धमकी दी है कि अगर सरकार ने लोगों के प्रदर्शनों के खिलाफ बल प्रयोग किया तो वह उसका कड़ा जवाब देंगे। उल्फा प्रमुख परेश बरुआ ने कहा कि अगर ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह हिंसा दूसरे राज्यों तक फैल सकती है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआइ, जो खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने व लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करता है, उसके पास राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सहित विभिन्न विंग हैं, जो स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह से सिमी जो देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन से संकट के क्षणों में अपने स्लीपर सेल को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सिमी को सरकार ने फरवरी में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर सिमी और पीएफआइ की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखेंगे। यह संगठन देश विरोधी प्रचार करके राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है।

सूत्रों ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फर्जी व अफवाह से भरे समाचारों के प्रसार पर रोक लगाने के साथ ही हिंसा को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तमाम अफवाहों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनमें से राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ ही आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विरोध जारी

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर जताया विरोध

'मेरे जीते जी बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी सीएए और एनआरसी'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सोमवार को खुद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ सड़क पर उतरीं और जुलूस की अगुआई की। जुलूस में हजारों की संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर अख्तियार करते हुए ममता ने सीएए लागू नहीं करने देने का संकल्प दोहराते हुए कहा, 'मेरे जीते जी बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने दूंगी।' कहा, 'जब तक मैं जिंदा हूं, एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने दूंगी। केंद्र को अपनी सरकार बर्खास्त करने की चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप मेरी सरकार बर्खास्त कर दें अथवा मुझे सलाखों के पीछे डाल दें लेकिन मैं यह काला कानून कभी लागू नहीं होने दूंगी। जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक संवैधानिक तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा।' ममता ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की भी निंदा की।

नागरिकता संशोधन कानून पर बंगाल में भारी हिंसा के बाद इस कानून और प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसी के विरोध में सोमवार को कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आईं और विशाल मार्च निकाला। असीम पॉल

ममता ने कहा कि राज्य में हिंसा भड़काने के लिए भाजपा ने कुछ लोगों को रुपये दिए हैं। राज्य में बाहर की कुछ ताकतें मुस्लिम समुदाय का मित्र होने का दिखावा कर रही हैं और वे तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल हैं।

लोकतांत्रिक हो विरोध का तरीका : ममता ने कहा, 'राज्य में सीएए के खिलाफ विरोध का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए क्योंकि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोस्ट आफिस, ट्रेन-बस में आग लगाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। रास्ता रोककर और ट्रेन रोककर भी लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे वे लोग हलकान हो रहे हैं, जो आपके साथ हैं। यह पूरे देशवासियों की लड़ाई है।'

पहले अकेले थी अब नहीं : ममता

ममता ने सीएए के विरोध को जायज ठहराते हुए कहा, 'पहले मैं अकेली इसके खिलाफ थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी इसे इजाजत नहीं देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एनआरसी को अनुमति नहीं देंगे। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सीएए को भी इजाजत न दें। मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भी यही कहा है। सभी को यही कहना चाहिए।'

जामिया से जुड़े ट्वीट के लाइक पर फंसे अक्षय, कहा-गलती से हो गया

मुंबई, एजेंसियां : दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े एक ट्वीट को लाइक करने के मुद्दे पर अक्षय कुमार ने सोमवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि पेज को बढ़ाने के क्रम में वह गलती से ट्वीट को लाइक कर बैठे थे।

दरअसल, नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर जामिया में चल रहे बवाल से जुड़े वीडियो को साझा करते हुए एक यूजर ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। उसने लिखा था, 'बधाई हो... जामिया में आजादी मिली है।' इस वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस से भागते नजर आ रहे हैं।

अक्षय ने ट्विटर पर सफाई दी, 'जामिया के छात्र के ट्वीट को लाइक किए जाने के बारे में कहना है कि वह गलती से हो गया था। मैं पेज को स्क्रॉल (आगे या पीछे बढ़ाना) कर रहा था, तभी वह गलती से लाइक हो गया होगा। जब मैंने इस गलती को महसूस किया तभी तत्काल इसे अनलाइक किया। मैं इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन कतई नहीं करता।'

हालांकि, इसके बाद भी ट्विटर पर लोगों ने हैशटैग आइ सपोर्ट अक्षय कुमार व बायकाट कनाडियन कुमार के जरिये उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, 'विश्वविद्यालयों में पढ़ाई को छोड़कर सबकुछ हो रहा है। यह भारत है। जामिया, एएमयू, जेएनयू। आइ सपोर्ट अक्षय कुमार।' दूसरे ने विरोध करते हुए लिखा, 'उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा, इसलिए उन्हें बाद में माफी मांगने व निंदा करने की जरूरत पड़ी... ये लोग काफी दबाव में हैं... हम लोगों को समझना चाहिए... अक्षय कुमार खुलकर बात करें... मैं उनके साथ हूं।' एक अन्य ने लिखा, 'एक्सिडेंटल नेशनलिस्ट।'

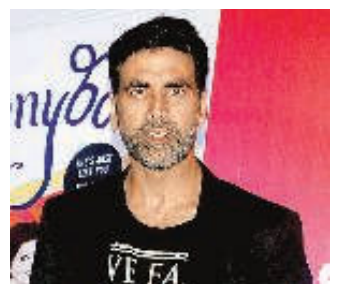

अक्षय कुमार फाइल

सीमा पर पाक के तीन बैट कमांडो ढेर

करार जवाब ▶ भारतीय सेना ने हमला किया नाकाम, अन्य सदस्य जान बचाकर भागे

पाकिस्तान सेना ने कवर फायर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर सोमवार को भारतीय चौकी पर हमला करने आए पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते के तीन कमांडो को भारतीय सेना ने मारा गिराया। बैट कमांडो दस्ते के अन्य सदस्य अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद और एक अन्य घायल हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने के साथ मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी की गई। देर रात तक दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी होती रही। इस दुस्साहस के बाद पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद यहां सीमा पर भारी हलचल भी रही।

राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के अंतर्गत केरी बट्टल इलाके में एलओसी पर स्थित ललयाली चौकी पर दोपहर बाद पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते ने हमला किया। गोलाबारी को देखते हुए भारतीय जवान समझ गए कि घुसपैठ हो रही है या फिर पाकिस्तानी सेना किसी बड़े बैट हमले की कार्रवाई कर रही है। सेना ने उसी समय सभी नाका पार्टियों और अग्रिम चौकियों को सचेत कर दिया। पाकिस्तानी गोलाबारी के थोड़ा धीमा पड़ते ही पाकिस्तानी सेना का बैट दस्ता एलओसी पार कर ललियाली चौकी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां मौजूद जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए बैट दस्ते के तीन कमांडोज को मार गिराया। इसके बाद उनके बचे हुए साथी वापस अपने साथियों के शव किसी तरह अपने इलाके में ले गए। इनके शव एलओसी के अगले हिस्से में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से बैट दस्ते को कवर फायर देने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम), मोर्टार और तोपखाने से भी गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी में एक जवान शहीद और एक अन्य जख्मी हो गया। गोलाबारी के बीच ही घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी की। इसमें एक जवान शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान अग्रिम इलाके में नाका पार्टी ने कुछ संदिग्ध तत्वों को भारतीय इलाके में घुसते देखा। जवानों द्वारा ललकारे जाने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और वापस भागने लगे। जवानों ने भी जवाबी फायर किया और उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया।

पुंछ से गुरेज तक सीमा पार से गोलाबारी, हवलदार शहीद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को नियंत्रण रेखा पर जम्मू के पुंछ से उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर तक संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारत के सैन्य व नागरिक ठिकानों पर भारी गोलाबारी की। इसमें एक जवान शहीद हो गया। इसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का भी एक अग्रिम मोर्चा तबाह हो गया। वहीं, पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी व तीन जवानों के जख्मी होने के अलावा तीन अन्य लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। शहीद भारतीय जवान की पहचान सेना की छह मराठा लाइट इंफेंट्री के हवलदार चौगले ज्योतिबा गणपति निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह जिला बांडीपोरा के अंतर्गत गुरेज सेक्टर के बगतूर इलाके में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गोले दागे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बगतूर (गुरेज) में पंथा पोस्टर और उसके साथ सटे इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी की चपेट में आकर एक जवान जख्मी हो गया। उन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बगतूर के सामने एलओसी के पार लीपा घाटी में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक अग्रिम मोर्चा तबाह हुआ है। उसका एक जवान जख्मी व एक अन्य व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है।

शहीद हवलदार चौगले ज्योतिबा गणपति की फाइल फोटो। पीआरओ डिफेंस

दोषी करार होते ही कोर्ट रूम में रोया सेंगर, बाहर बिलखा परिवार

उन्नाव कांड

सुशील गंभीर, नई दिल्ली

नाबालिग से दुष्कर्म के लिए जब सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया तो वह कोर्ट रूम में ही रोने लगा। इसके बाद जब न्यायाधीश ने शशि सिंह के लिए फैसला सुनाना शुरू किया तो वह रोने लगी और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। हालांकि न्यायाधीश ने शशि को बरी करने का आदेश दिया। पुलिसकर्मियों ने शशि सिंह को समझाया कि वह बरी हो गई है, लेकिन वह बेसुध पड़ी रही। इसके बाद कोर्ट रूम में ही डॉक्टर को बुलाया गया और प्राथमिक इलाज के बाद उसे होश में लाया गया।

फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट रूम के बाहर मौजूद सेंगर के परिजनों में कुछ अंदर आ गए और रोने लगे। बाहर भी उनके परिवार के कई सदस्य बिलख पड़े। कुलदीप सेंगर की बेटियां जोर-जोर से अदालत परिसर में रोने लगीं। सेंगर की बहन ने रोते हुए उसकी बेटियों को बोला कि उनके पिता ने कुछ नहीं किया है और यह लड़ाई जारी रहेगी। दोषी दिए जाने के बाद जब सेंगर को पुलिसकर्मी कोर्ट रूम से हवालात लेकर जाने लगे तो सेंगर के पीछे उसके समर्थकों की भीड़ चलने लगी। हालांकि सेंगर के वकीलों ने भीड़ को रोक दिया और पीछे जाने से मना किया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया।

दिल्ली की अदालत से 133 दिन में आया फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उन्नाव कांड से जुड़े दुष्कर्म के मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 133 दिन में फैसला सुनाया है। 5 अगस्त को पहली बार यह केस दिल्ली में सुना गया और अब 16 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत ने हर दिन मामले की सुनवाई की।

तीस हजारी के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने जिस तरह इस केस की हर दिन सुनवाई कर मामले को फैसले तक पहुंचाया वह एक उदाहरण स्थापित करता है। इसी साल 5 अगस्त को पहली बार तीस हजारी अदालत में यह केस सुना गया था, जब कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को उत्तर प्रदेश से दिल्ली प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग हर दिन इस मामले की सुनवाई हुई। प्रतिदिन देर शाम तक सुनवाई होती थी, जबकि कई बार सरकारी छुट्टी के दिन भी केस सुना गया। यहां तक कि पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए तीन दिन तक एम्स में भी अदालत लगी। ऐसा अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही होता है कि अदालत खुद पीड़ित को सुनने के लिए उसके पास जाए।

हड़ताल की वजह से अटक गई थी सुनवाई : तीस हजारी अदालत में विगत 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल के बाद सभी अदालतों के वकील हड़ताल पर चले गए थे। 12 दिन तक चली हड़ताल के कारण इस मामले की सुनवाई भी अटक गई थी, जो करीब दो सप्ताह के बाद फिर से शुरू हो सकी। उन्नाव कांड से जुड़े सभी केस बंद कमरे में सुने जा रहे हैं और इस केस को भी इसी प्रक्रिया के तहत सुना गया।

15 साल से फरार आरोपित टिक-टॉक के शौक में पकड़ा गया

संवाद सूत्र, उदयपुर: पचास लाख रुपये की ठगी के मामले में उदयपुर पुलिस जिसे करीब 15 साल से तलाश रही थी, वह टिक-टॉक पर वीडियो अपलोड करने के शौक में पकड़ा गया। कोर्ट ने आरोपित को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है।

मामला राजस्थान के उदयपुर शहर के गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र से जुड़ा है। कुछ दिन पहले ठगी के आरोपित दिनेश नाथ ने टिक-टॉक पर वीडियो अपलोड किया। इसमें उसने बताया कि वह पुताई का काम कर रहा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पता लगाया कि वीडियो पुणे से अपलोड किया गया है। उसे पकड़ने के लिए टीम गठित कर पुणे भेजी। टीम ने पुणे में संबंधित क्षेत्र में 50 से अधिक ऐसी बहुमंजिला इमारतों को खंगाला, जहां रंग-रोगन का काम चल रहा था। इसी दौरान दिनेश पुणे के पींपरी चिंचवड़ के बाणेर क्षेत्र की एक बिल्डिंग में काम करता मिल गया। उसे गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया। यहां सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक, दिनेश पर उदयपुर के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास तथा मारपीट के चार मामले दर्ज हैं। इनमें गोवर्धनविलास थाने में 15 साल पहले दर्ज कराया गया 50 लाख रुपये की ठगी का मामला भी शामिल है।

बर्फ पर फुटबाल

कश्मीर में फुटबाल का खुमार चरम पर है। आइ-लीग फुटबाल प्रतियोगिता का जोश खिलाड़ियों में गर्माहट का काम कर रहा है। बर्फ में ढक चुके श्रीनगर के टीआरसी मैदान में कड़ा अभ्यास करते रियल कश्मीर फुटबाल टीम के खिलाड़ी। रोजाना इन खिलाड़ियों को सुबह इसी तरह कड़ाके की ठंड में पसीना बहाते देखा जा सकता है। रियल कश्मीर और चेन्नई सिटी फुटबाल टीम के बीच 26 दिसंबर को मुकाबला होना है। हालांकि मौसम खराब होने के कारण 12 और 15 दिसंबर को होने वाले मैच रद हो चुके हैं। सौजन्य : रियल कश्मीर फुटबाल क्लब

अदालत ने समझा गांव में रहने वाली पीड़िता का दर्द

सुशील गंभीर, नई दिल्ली

- यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण लड़कियां दबंगों के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं
- सेंगर को दोषी करार देते समय की कोर्ट ने की टिप्पणी

यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण लड़कियां दबंगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से डरती हैं। यह मामला उन प्रतिबंधों और धारणाओं को दर्शाता है, जिनके साथ ग्रामीण लड़कियों को पालकर बड़ा किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के मन में भय के स्तर को प्रकट करता है कि किस तरह वे दबंगों द्वारा यौन हिंसा का शिकार होने के बाद भी उसके विरोध में आवाज उठाने से डरती हैं। यह टिप्पणी तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने उन्नाव पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार देते समय की।

न्यायाधीश ने फैसला सुनाते समय कहा कि पीड़िता ने अपने साथ हुए अपराध के कुछ तथ्य उन्नाव में मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज कराते समय उजागर नहीं किए, क्योंकि सेंगर ने उसे डरा रखा था कि अगर वह सच बोलेगी तो तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पीड़िता के साथ 4 जून को दुष्कर्म हुआ, लेकिन अगस्त में केस दर्ज हुआ था। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अपने साथ हुए अपराध की तुरंत शिकायत नहीं की और न ही पहली बार दिए बयान में मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म की बात कही। यह मामला दर्शाता है कि ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी लड़कियों के मन में किस हद तक डर है। चूंकि पीड़िता ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है और कुलदीप सेंगर दबंग व्यक्ति था, इसलिए पीड़िता ने इतना समय लिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला यह भी दर्शाता है कि पॉक्सो एक्ट के जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं होने के पीछे रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रमुख कारण है।

'एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने की कोशिश'

जासं, नई दिल्ली : विधायक कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म के लिए दोषी करार देने के साथ ही अदालत ने उसके वकील को भी आड़े हाथों लिया। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि सेंगर के वकील ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से दो पक्षियों (मामलों) को एक पत्थर से मारने की कोशिश की और पीड़िता के चरित्र को ध्वस्त करने का प्रयास किया। बचाव पक्ष सेंगर से जुड़े दुष्कर्म के मामले के साथ पीड़िता से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को जोड़ रहा था और उस पर सवाल उठा रहा था।

सामूहिक दुष्कर्म का मामला दुष्कर्म के मामले से अलग है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई अभी ट्रायल कोर्ट में शुरू होनी है। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष ने दुष्कर्म के मामले को भी प्रभावित करने की कोशिश की, यह साबित करने की कोशिश की कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक दिखाव था। अदालत ने यह भी कहा कि दुष्कर्म की शिकार पीड़िता के परिवार में तीन अन्य लड़कियों को भी शर्म, घृणा और समाज में अपमान के अधीन किया जा रहा था। बचाव पक्ष बुरी तरह से यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता के चाचा ने सेंगर के खिलाफ पुराने मसले को निपटाने के लिए यह सब झूठ किया था।

विस चुनाव के लिए अब्दुल्ला ने की थी जालसाजी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

2017 के विस चुनाव में 24 साल थी अब्दुल्ला की उम्र

25 साल आयु दिखाने के लिए बनवाया था दूसरा पैन कार्ड

मार्कशीट बनी आधार

अब्दुल्ला की मार्कशीट को आधार बनाते हुए उम्र छिपाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में दो पैन कार्ड बनवाए जाने की जानकारी भी रखी गई थी। पैन कार्ड मामले में आकाश ने पिता-पुत्र दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। आकाश ने आजम के खिलाफ सेना के खिलाफ अपशब्द कहने और भावनाएं आहत करने का मामला भी दर्ज कराया था। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर भी आकाश आवाज उठाते रहे हैं।

शीतकालीन सत्र में शामिल न हो सकेंगे :

हाई कोर्ट द्वारा अब्दुल्ला आजम की विधायकी निरस्त कर देने से वह मंगलवार से आरंभ शीतकालीन सत्र में भी भाग नहीं ले सकेंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे का कहना है कि अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट द्वारा विधायक पद से अयोग्य घोषित किया गया है इसलिए उन्हें सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

विधायक बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, लेकिन सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खां के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की उम्र 2017 के विधानसभा चुनाव के लिहाज के 24 साल ही बैठ रही थी। यह उम्र उसके पैन कार्ड में दर्ज थी। इसलिए अब्दुल्ला का एक और पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें उम्र 26 साल हो गई। भाजपा सरकार में दो बार मंत्री और चार बार विधायक रहे शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र आकाश सक्सेना ने यही शिकायत निर्वाचन आयोग व आयकर विभाग में दर्ज कराई थी।

आकाश ने अगस्त, 2017 में यह मामला लखनऊ में उठाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि आजम खां ने अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए उसकी उम्र छिपाई, जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए उसके दो पैन कार्ड बनवाए और विधानसभा चुनाव के नामांकन में झूठा शपथ पत्र दिया। आकाश ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बाबत दिए शिकायती पत्र के साथ अब्दुल्ला के नामांकन के शपथ पत्र, बैंक पासबुक, दोनों पैन कार्ड के ई-टैक्स चालान, दोनों पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी के अलावा लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी गलत जन्म प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी भी लगाई थी।

यह था मामला : अब्दुल्ला का पहला पैन कार्ड (डीएफओपीके6164के) 30 अगस्त 2013 को बना था, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 दर्ज कराई गई थी। अब्दुल्ला की हाई स्कूल की सीबीएसई की मार्कशीट (रोल नंबर-5260139) में भी यही जन्मतिथि दर्ज है। इस लिहाज से अब्दुल्ला 25 साल की उम्र एक जनवरी 2018 को पूरी होनी थी, जबकि आजम ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया था। इस चुनाव के समय वास्तव में अब्दुल्ला की उम्र 24 साल थी, जो कि चुनाव लड़ने के लिए कम थी। इसीलिए 24 मार्च 2015 को अब्दुल्ला का एक और पैन कार्ड (डीडब्ल्यूएपीके7513आर) बनवाया गया और इसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज करा दी गई। इस जन्मतिथि को तर्कसंगत बनाने के लिए 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से एक जाली जन्म प्रमाणपत्र बनवाया गया। नई जन्म तिथि के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते समय अब्दुल्ला की उम्र 26 साल हो गई।

हाथ से चढ़ाई थी सूचना : बैंक पासबुक हो या नामांकन का शपथपत्र, दोनों में बाकी सारी जानकारी टाइप की हुई है, जबकि 26 साल उम्र बताने वाले पैन कार्ड की सूचना हाथ से दर्ज की गई थी। शपथ पत्र में जिस बैंक खाते को नए पैन कार्ड से लिंक बताया गया, वह वास्तव में पुराने पैन कार्ड से लिंक था। इसी तरह जो आयकर रिटर्न नए पैन कार्ड पर भरे गए दिखाए गए, वह असल में पुराने पैन कार्ड पर दाखिल किए गए थे।

छह साल की मासूम से 10 साल के दो बच्चों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, गढ़वा : झारखंड के गढ़वा स्थित एक गांव में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दो बच्चों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों आरोपितों का उम्र लगभग 10-10 वर्ष है। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म दो दिनों तक क्रमशः 12 और 13 दिसंबर को रेलवे लाइन के समीप किया गया। 13 दिसंबर को जब दोनों आरोपित रेलवे लाइन के समीप फिर से बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगे तो बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर वहां पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को डांट-फटकार कर भगा दिया। इसके बाद बच्ची ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।

पीड़िता के परिजनों ने जब दोनों आरोपितों के घर जाकर इसकी शिकायत की तो आरोपितों के परिजनों ने पीड़िता के परिजन के साथ मारपीट की।

छह वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। इसके साथ ही कोर्ट में 164 का बयान हुआ है। आरोपित बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

-बहामन टूटी, एसडीपीओ, गढ़वा

उन्नाव में पीड़िता ने एसपी आफिस में खुद को लगाई आग

जागरण संवाददाता, उन्नाव

- 85 फीसद झुलसी, कानपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती
- रिपोर्ट दर्जकर दो माह खामोश रही पुलिस, आरोपित ले आया अग्रिम जमानत

उन्नाव एसपी कार्यालय में सोमवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना घटी। पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध एक दुष्कर्म पीड़िता ने कार्यालय गेट पर खुद को आग लगा ली और भीतर की ओर दौड़ पड़ी। यह देख पुलिसकर्मियों ने उसे किसी तरह रोक बॉडी प्रोटेक्टर और शॉल के सहारे आग बुझाई। तब तक वह गंभीर रूप से जल चुकी थी। उसे कानपुर के एलएलआर अस्पताल भेजा गया। युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले गांव के युवक अवधेश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपित पर कार्रवाई के बजाय करीब दो माह बैठी रही। इस बीच आरोपित कोर्ट से अग्रिम जमानत ले आया और आराम से घूम रहा है। अब पुलिस आरोपित अवधेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सुबह करीब 11 बजे एसपी कार्यालय में फरियादियों की भीड़ लगी थी। एसपी विक्रांत वीर समस्याएं सुन रहे थे। अचानक केरोसिन से भीगी एक युवती कार्यालय गेट पर पहुंची और खुद को आग लगा ली। आग का गोला बन चुकी युवती चीखते हुए कार्यालय के भीतर भागी। महिला पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए आग बुझाई। महिला फरियादियों ने सिपाहियों को अपने शॉल दिए। पुलिसवालों ने पीड़िता को शॉल से लपेटा और तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए। एसपी विक्रांत वीर, एएसपी विनोद कुमार पांडेय व सीओ यादवेंद्र यादव भी अस्पताल पहुंचे। युवती की हालत गंभीर देख उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। एसपी ने बताया कि युवती ने मुख्य आरोपित अवधेश सिंह समेत चार के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट कराई थी। आरोपित को अग्रिम जमानत मिलने से वह नाराज थी, इसलिए यह कदम उठाया। मुख्य आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

उधर, कानपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती पीड़िता का इलाज कर रहे सर्जरी विभाग के डॉ. जीडी यादव ने बताया कि युवती 85 फीसद जली हुई है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह पूरी तरह होश में नहीं है।

सहयोग

पुलिस संगठन के आधुनिकीकरण के लिए पिछले दो साल में मिले 83 करोड़, तकनीकों से लैस हथियारों की खरीद से लेकर ढांचागत सुविधाएं भी जुटाई गईं

जम्मू-कश्मीर पुलिस को हर पल केंद्र का साथ

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पुलिस के सामने अधिक चुनौतियां

देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित पुलिस संगठनों के विपरीत जम्मू-कश्मीर पुलिस अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रही है। यहां भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हर क्षेत्र में पुलिस के सामने अलग-अलग जरूरतें और चुनौतियां हैं। उसके सामने एक ओर आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद से भी जूझना पड़ रहा है।

जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध का मुकाबला कर रही जम्मू-कश्मीर पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार हर पल तैयार है। इसके तहत केंद्र ने पिछले दो वर्ष में ही 83 करोड़ रुपये राज्य पुलिस संगठन को दिए हैं। इस राशि का इस्तेमाल अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने से लेकर पुलिस के मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के पुलिस संगठनों को क्रमशः 769 और 811 करोड़ दिए हैं। पूरे देश में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए सर्वाधिक 83 करोड़ रुपये मिले हैं। महाराष्ट्र को 131 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 98 करोड़ दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में डीआइजी रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र से मिली राशि के आधार पर ही पूरे राज्य में करीब 200 पुलिस थानों व चौकियों में मौलिक सुविधाएं जुटाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की आवासीय सुविधा, थाना परिसरों के भीतर मूलभूत आवासीय सुविधाओं का निर्माण, पुलिस थानों की चारदीवारी को ऊंचा करना, प्रवेश द्वार को अभेद्य बनाने का काम किया गया है। सभी पुलिस थानों के आसपास और जम्मू और श्रीनगर शहरों के अलावा अन्य प्रमुख कस्बों में सीसीटीवी लगाए गए हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि के आधार पर ही पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदे गए हैं। उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट की नई खेप लाई गई है। आतंकवाद से प्रभावित सभी इलाकों में पुलिस थानों के लिए बुलेट प्रूफ वाहनों का बेड़ा तैयार किया गया है। मौजूदा रक्षक वाहनों में आवश्यक सुधार के अलावा अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस नए बुलेट प्रूफ वाहन, आइईडी डिटेक्टर और जैमर भी खरीदे गए हैं। इस राशि से ही साइबर सेल में व्यापक सुधार कर महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस को बदलते परिवेश व बढ़ती चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह समर्थ बनाने की प्रक्रिया जारी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की ढांचागत सुविधाओं की गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा कर रहा है। इसके तहत समय-समय पर पुलिस की जरूरतों का आकलन कर उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

बरेली में सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, 35 पर यौन उत्पीड़न का आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली

- महिला के पति की गैरमौजूदगी में अक्सर जबरन घर में घुस आते थे आरोपित
- एक दिन पति की मौजूदगी में भी पहुंचे तो सामने आई पूरी घटना
- पीड़िता से एक साल में 50 हजार रुपये ऐंठ चुके हैं आरोपित

पति मजदूरी पर गया तो गांव के चार दबंग महिला के घर में घुस आए और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद धमकी देकर सालभर तक शोषण करते रहे। वे चारों आए दिन युवकों को लेकर महिला के घर लेकर पहुंचते और दुष्कर्म कराते। एक दिन महिला के पति की मौजूदगी में भी ऐसा दुस्साहस किया गया तो पीड़िता ने पूरी घटना बयां की। जिसके बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी क्राइम से कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना कैंट क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि सालभर पहले गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के चार लोग घर में घुस आए थे। उस वक्त पति मजदूरी करने गए थे। चारों ने दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर पति की गैरमौजूदगी में अक्सर लोगों को घर लाते और दुष्कर्म कराते। इसकी जानकारी पति को शनिवार को उस समय हुई जब वह घर पर था, तभी चारों आरोपित दो युवकों को लेकर घर आ गए। दूसरे कमरे में मौजूद महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह मदद के लिए चीख पड़ी। यह सुनकर पति पहुंचा तो आरोपित वहां से भाग गए। इसके बाद महिला ने पति को शोषण की पूरी कहानी बताई। कहा कि एक साल में 35 लोग दुष्कर्म कर चुके हैं। कार्रवाई के लिए वे थाने पहुंचे मगर पुलिस ने अनसुना किया तो सोमवार को दंपती एसएसपी कार्यालय पहुंचा।

थाना कैंट पुलिस को मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर घटना सही होगी तो मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।

-रमेश कुमार भारतीय, एसपी क्राइम

पीड़िता से रुपये ऐंठते रहे आरोपित : महिला के पति ने मजदूरी कर कुछ रुपये जोड़कर रखे थे। आरोपितों को इसकी भनक लगी तो वे घर अक्सर उससे रुपये ऐंठते। महिला का कहना है कि एक साल में वे करीब 50 हजार रुपये ऐंठ चुके थे।

विजय दिवस : 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि, हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश

जागरण संवाददाता, कोलकाता

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत की याद में 48वें विजय दिवस के मौके पर सोमवार को कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम में स्थित विजय स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सहित अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने विजय स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। इनके अलावा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष अरुप राहा, पूर्वी वायुसेना कमान के प्रमुख एयर मार्शल आरडी माथुर सहित अन्य हस्तियों और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले जांबाजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस समारोह में भाग लेने बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं व सैन्य अधिकारियों समेत 71 सदस्यीय प्रतिनिधिदल की अगुआई कर रहे वहां के सांसद शाहजहां खान ने भी पुष्प चक्र अर्पित किया। इस मौके पर सेना के तीन हेलीकॉप्टरों से विजय स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने वीर योद्धाओं को सलामी देने के साथ उनके योगदानों को याद किया। उन्होंने घोषणा की कि अब विजय स्मारक प्रत्येक रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन आम जनता के लिए खुला रहेगा ताकि वे हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें।

विजय दिवस के अवसर पर सोमवार को कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी (दाएं), लेफ्टिनेंट जनरल जेएस शर्मा (मध्य में) और वायुसेना के पूर्व प्रमुख अरुप राहा (बाएं) ने विजय स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर 1971 के शहीदों को याद किया। प्रेट्र

इसलिए मनाते हैं विजय दिवस : हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी, जब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था।

विजय दिवस समारोह संपन्न : विजय स्मारक पर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ पूर्वी कमान की ओर से आयोजित चार दिवसीय विजय दिवस समारोह संपन्न हो गया। हर साल सेना की ओर से कोलकाता में यह समारोह धूमधाम से आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान सेना के जांबाजों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन कर अपनी शौर्य व ताकत का परिचय दिया। आरसीटीसी ग्राउंड में आयोजित मिलिट्री टैटू में लगातार दो दिन 14 व 15 दिसंबर को हेलीकॉप्टर शो, घोड़ा दौड़, डॉग शो, मार्च पास्ट, मोटरसाइकिल करतब आदि का हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया, 'विजय दिवस पर मैं शहीदों के साहस व वीरता को श्रद्धांजलि देता हूं। आज के दिन बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास रचा था, वह इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा।' रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को याद किया। भारतीय सैनिकों ने वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया था। इस जीत ने बांग्लादेश के गठन का रास्ता तैयार किया था। उन्होंने ट्वीट किया, 'इस अवसर पर राष्ट्र भारतीय सेनाओं के अदम्य साहस व वीरता को सलाम करता है। हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमारी रक्षा की है। हम उनकी सेवा व बलिदान को नहीं भुला सकते।' केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी लिखा, 'पूरा देश शहीदों को सलाम करा रहा है और मैं इसमें शामिल हूं। मैं 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन करती हूं।'

नरेंद्र मोदी। फाइल

बांग्लादेश में 'सारे जहां से अच्छा' की धुन सुनकर खड़े हो गए लोग

ढाका, प्रेट्र : पाकिस्तान से आजादी के उपलक्ष्य में बांग्लादेश ने सोमवार को अपना 49वां विजय दिवस मनाया। परेड के दौरान बांग्लादेश की सेना ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पहली बार इस परेड में भारतीय सेना के बैंड ने भी हिस्सा लिया। 'सारे जहां से अच्छा' की धुन पर जब भारतीय बैंड कदमताल कर रहा था तो दर्शक दीर्घा का उत्साह देखते ही बन रहा था। परेड के दौरान 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत की भूमिका के बारे में भी बताया जा रहा था। दर्शक दीर्घा में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा के साथ 20 एनसीसी कैडेटों का दल भी मौजूद था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद ने परेड की सलामी ली और परेड कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अकबर हुसैन के साथ खुली जीप में सवार होकर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक भी मौजूद थे। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास भी मेहमानों में शामिल थीं। वर्ष 1971 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पाक से युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ शस्त्र संशोधन बिल बना कानून

नई दिल्ली, आइएएनएस : नए शस्त्र (संशोधन) अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है। छह दशक पुराने कानून के संशोधन बिल को इसी सप्ताह संसद में पारित किया गया था। नया कानून देश में अवैध हथियारों और गोली-बारूद की रोकथाम में सरकार के लिए मददगार साबित होगा चूंकि अब इसमें अधिकतम सजा उम्रकैद होगी।

छह दशक पुराने शस्त्र कानून, 1959 को अवैध हथियारों की तस्करी रोकने में प्रभावी बनाने के लिए इसमें अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल, हस्तांतरण, बदलाव, हथियारों की बिना लाइसेंस टेस्टिंग या प्रूफिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। नए कानून में सजा भी कड़ी कर दी गई है। अब सजा जुर्माने समेत सात साल कैद से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। जबकि पहले यह सजा जुर्माने के साथ तीन साल से सात साल तक कैद की ही हो सकती थी। राष्ट्रपति कोविंद ने विगत शनिवार को उस अधिनियम पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत शस्त्र लाइसेंस की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रानिक फार्म के जरिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने का प्रविधान किया गया है। इसकी प्रक्रिया में बदलाव का कारण अपराधों में इस्तेमाल हो रहे अवैध हथियारों का संजाल खत्म करना है।

पहाड़ों से चली हवाओं ने मैदान को ठिठुराया

मौसम के तेवर ▶ जम्मू-कश्मीर में निकली धूप लेकिन राहत नहीं, शीतलहर की चपेट में दिल्ली, टूटा 16 साल का रिकॉर्ड

लद्दाख के द्रास में माइनस 27 .2 रहा न्यूनतम तापमान

जेएनएन, नई दिल्ली

कई दिनों की बर्फबारी के बाद निकली धूप भी पहाड़ों को कोई राहत नहीं दे सकी, बल्कि वहां से चली बर्फीली हवाओं ने मैदान को ठिठुरा दिया है। राजधानी दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। सोमवार को यहां पहली बार पाला पड़ने के साथ ही दिसंबर में सर्दी का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तापमान में यह गिरावट अभी जारी रहेगी।

सोमवार सुबह करीब 11 बजे तक फुहारें पड़ने का अहसास होता रहा। दिल्ली का अधिकतम तापमान महज 12.9 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। यह सामान्य से दस डिग्री कम है। इससे पहले 25 दिसंबर 2003 को अधिकतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। ऑलटाइम रिकॉर्ड 28 दिसंबर 1973 का है, जबकि अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद 28 दिसंबर 1997 को अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। आलम यह रहा कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर महज 2.7 डिग्री सेल्सियस का रह गया। हवा में नमी का स्तर 88 से 100 फीसद दर्ज किया गया। दिनभर धूप के दीदार नहीं हुए।

स्काईमेट वेदर के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकल जाने के बाद अब उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही हैं। वहीं दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में घने कोहरे की शुरुआत भी हो चुकी है। सोमवार को भी दिल्ली और एनसीआर में मध्यम कोहरा छाया रहा। इस साल ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जब पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों और दिल्ली सहित उत्तर भारत के सभी मैदानी इलाकों में धुंध बनी हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के इस प्रकोप से अगले दो दिनों तक राजधानी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 21 और 22 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार हैं।

जम्मू-कश्मीर, लेह और उत्तराखंड में कई दिनों की बर्फबारी के कारण बंद पड़े कुछ मार्गों को खोला गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुसीबत कम नहीं हो रही। हिमपात के कारण करीब 260 सड़कें बंद हैं। तीन दिन बाद सोमवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल किया गया। श्रीनगर-लेह राजमार्ग और पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड अभी भी बंद है। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के साथ बैटरी कार सेवा और पैसेंजर केबल कारसेवा सुचारु रही। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के कारण सड़कों को खोलने के काम में तेजी आई है। सोमवार को 17 और सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया, लेकिन अब भी बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पिथौरागढ़ में थल-मुनस्यारी समेत 18 संपर्क मार्गों पर आवाजाही ठप है। प्रदेश के पांच शहरों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस से कम रहा।

रेल व हवाई यातायात पर असर : कोहरे की वजह से रेल व हवाई यातायात पर असर पड़ने लगा है। सोमवार को चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल्लू को जाने वाली फ्लाइट खराब मौसम के कारण रद कर दी गई हैं। दिल्ली में राजधानी सहित कई ट्रेनें देरी से पहुंची। कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा। मध्य फरवरी तक 23 जोड़ी ट्रेनें पहले ही निरस्त कर दी गई हैं।

विभिन्न शहरों में तापमान

शहर	न्यूनतम तापमान
द्रास	-27.2
श्रीनगर	-1.8
मसूरी	02.8
मुक्तेश्वर	0.8
हिसार	9.1
कोलकाता	18

नोट- तापमान डिग्री सेल्सियस में हैं।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को माल रोड पर जमी बर्फ पर फिसलन से बचने के लिए संभलकर चलते पर्यटक। जागरण

मप्र में 'ऑपरेशन क्लीन', घर ऑफिस बंद कर भागे माफिया

नईदुनिया, इंदौर

▶ इंदौर से फरार अश्विन मेहता, चिराग शाह व महिपाल का लुक आउट सर्कुलर जारी

मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के माफिया के खिलाफ शुरू किए गए 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत इंदौर पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी और अड़ीबाजी में शामिल माफिया की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। देश छोड़ने की आशंका को देखते हुए फरार कॉलोनाइजर अश्विन चंद्रसिंह मेहता, चिराग उर्फ चीकू शाह और केबल माफिया महिपाल रावत के विरद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इनके घर व ऑफिसों पर ताला लगा है, उन्हें फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया जा रहा है।

एसपी (इंदौर पूर्व) मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के मुताबिक 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत गत दिनों 11 मामले दर्ज किए गए। इनमें जमीन की धोखाधड़ी, अड़ीबाजी, अवैध कब्जे जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। भूमाफिया बब्बू उर्फ सुल्तान, हेमंत यादव और शिवनारायण अग्रवाल को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन कुख्यात चिराग शाह, अश्विन मेहता, चंपू अजमेरा, छब्बू उर्फ साबिर, गैंगस्टर सतीश भाऊ और केबल माफिया महिपाल रावत फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित विदेश भाग सकते हैं, इसलिए उनके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया। यह सर्कुलर जारी होने पर किसी भी आरोपित के लिए देश छोड़ना आसान नहीं होता। कई माफिया तो घर और ऑफिस बंद कर परिवार सहित गायब हो गए। कई राजनेताओं से संपर्क कर बचने की कोशिश में जुटे हैं।

'संतोषी माता' घोटाले में अश्विन, चिराग पर केस : इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस ने भूमाफिया अश्विन और चिराग के खिलाफ कैलोद हाला स्थित संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था जमीन घोटाले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, संस्था के पदाधिकारी आनंदीलाल जैन, योगेश रत्नावत, राजेंद्र सोनी ने कॉलोनी लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, विकास अनुमति भी नहीं ली और भूमि उपयोग परिवर्तन भी नहीं कराया। धारा 10 (4) के तहत कलेक्टर से अनुमति नहीं ली। आरोपितों ने अवैध निर्माण किया। महंगे दामों पर भूखंड बेच अवैध लाभ अर्जित किया। आरोपितों द्वारा हेराफेरी के आशय से फर्जी अनुबंध किए गए।

एक हाथ में एके-47 और दूसरे में दवाओं का थैला

रीतेश पांडेय, जगदलपुर

दंतेवाड़ा एसपी व जगदलपुर एसडीओपी हैं डॉक्टर, नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों का करते हैं इलाज

छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात दो युवा अधिकारी एक हाथ में एके-47 और दूसरे में दवाओं के थैला लेकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। दरअसल, नक्सल फ्रंट पर काम कर रहे दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव और बस्तर के सब डिविजनल पुलिस ऑफीसर(एसडीओपी)डॉ. यूलंडन यार्क अपनी मेडिकल शिक्षा का इस्तेमाल ग्रामीणों की सेहत दुरुस्त में भी कर रहे हैं।

डॉ. पल्लव दंतेवाड़ा में नशामुक्ति अभियान चला रहे हैं। पुलिस जवानों समेत तीन हजार युवाओं को नशा से मुक्ति दिला चुके हैं। इसके साथ ही वह पुलिस के जवानों समेत ग्रामीणों के लिए करीब 100 स्वास्थ्य शिविर लगाकर करीब 10 हजार लोगों का उपचार कर चुके हैं। दूसरी तरफ डॉ. यूलंडन दरभा ब्लॉक के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान दवाओं का थैला साथ लेकर चलते हैं। वह जवानों के साथ ही ग्रामीणों का भी उपचार करते हैं।

सरकारी बंगला बना डिस्पेंसरी : डॉ. अभिषेक पल्लव 2013 बैच के आइपीएस हैं। उन्होंने दिल्ली में एमबीबीएस किया। बाद में मनोरोग में एमडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर आइपीएस बने। उनकी दो साल पूर्व दंतेवाड़ा में नियुक्ति हुई। डॉ. पल्लव ने देखा कि अधिकतर जवान कड़ी ड्यूटी और पारिवारिक तनाव से ग्रस्त होकर शराब के व्यसनी हैं। उन्होंने पुलिस लाइन में जवानों के लिए कैंप शुरू किया। मानसिक रूप से परेशान जवानों की वे नियमित काउंसिलिंग करते हैं। वर्तमान में उनका सरकारी बंगला डिस्पेंसरी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सुदूर गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर वे न केवल मानसिक उपचार करते हैं, बल्कि सामान्य रोगों की दवाएं भी ग्रामीणों को मुहैया करवाते हैं।

पल्लव को पत्नी का भी मिलता है साथ : पल्लव की पत्नी डॉ. यशा पल्लव चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। वे भी उनकी मुहिम में योगदान देती हैं। साथ ही जिला अस्पताल में उपचार करती हैं।

यूलंडन की डॉक्टर साहब के नाम से हो गई पहचान : 2014 बैच के छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा (सीपीएस) के अधिकारी डॉ. यूलंडन यार्क दरभा इलाके में एसडीओपी हैं। ग्रामीणों के बीच डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बिलासपुर से एमबीबीएस की डिग्री ली है। इसके बाद वे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर सीपीएस बने। ढाई साल पहले उनकी नियुक्ति बस्तर में हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरभा में तैनाती के दौरान उन्होंने देखा कि ग्रामीणों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तब उन्होंने ग्रामीणों का इलाज करने की ठानी। वे जवानों के साथ तलाशी अभियान के दौरान एके- 47 के साथ दवाओं का थैला साथ लेकर चलते हैं। दरभा ब्लॉक मलेरिया के चलते संवेदनशील माना जाता है। वह सुदूर गांवों भडरीमऊ, कोलेंग, चांदामेटा, बिसपुर आदि में बुखार व अन्य सामान्य रोगों के मरीजों को आवश्यकतानुसार दवाएं प्रदान करते हैं। वहीं गंभीर मामलों को जिला अस्पताल भेजने की व्यवस्था करते हैं।

ग्राम चोलनार में शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज करते दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव (मध्य में)। नईदुनिया

बस्तर के सब डिविजनल पुलिस ऑफीसर(एसडीओपी) डॉ. यूलंडन यार्क (वर्दी में) शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए। नईदुनिया

गांधी परिवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जेल पहुंचीं पायल रोहतगी

जागरण संवाददाता, जयपुर

▶ फिल्म अभिनेत्री को राजस्थान पुलिस ने किया है गिरफ्तार, 24 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

▶ मोतीलाल से लेकर जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर की थी टिप्पणी

पंडित मोतीलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी को 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान की बूंदी पुलिस ने उनको रविवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था।

रोहतगी को सोमवार सुबह पुलिस बूंदी लेकर पहुंची और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट में पेश किया। वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सक्सेना ने पायल रोहतगी की ओर से कोर्ट में पैरवी की। सक्सेना मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पेश करेंगे।

गौरतलब है कि रोहतगी ने गत 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी-नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। दो अक्टूबर को बूंदी निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने पायल रोहतगी के खिलाफ आइटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505 (2) के तहत बूंदी सदर पुलिस थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने 10 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। उक्त धाराओं में दो साल की सजा या फिर जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

पायल रोहतगी फाइल फोटो

पायल ने नहीं दिया था नोटिस का जवाब : 26 नवंबर को बूंदी पुलिस ने पायल रोहतगी के अहमदाबाद स्थित आवास पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। पुलिस ने ईमेल भी किया था। इसके बाद 11 दिसंबर को पुलिस के नोटिस पर पायल रोहतगी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ट्वीट कर पुलिस में मामला दर्ज कराने वाले चर्मेश शर्मा से बचाने की गुहार लगाई थी। 12 दिसंबर को पायल रोहतगी के वकील ने बूंदी जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 13 दिसंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई और कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) की तारीख दी। इसी बीच शनिवार शाम को बूंदी पुलिस की टीम पायल रोहतगी को हिरासत में लेने के लिए मुंबई गई तो उनके अहमदाबाद होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस की टीम रविवार सुबह अहमदाबाद पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर सोमवार सुबह बूंदी पहुंची।

एसपी ने कहा-आरोप प्रमाणित : बूंदी पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि जांच में पायल रोहतगी के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं। पुलिस ने उन्हें कई बार नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। रविवार को उनको अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।

थोड़ा इंतजार

करपात्री महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में दिया जा रहा आकार, अनूठे देवालय संकुल में द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित विराजेंगे पंचदेव

काशी को मिलने जा रहा भव्य-दिव्य श्रीराम मंदिर

प्रमोद यादव, वाराणसी

अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य-दिव्य मंदिर तो अभी कुछ इंतजार कराएगा, लेकिन देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में इसका स्वरूप जल्द ही निखर कर सामने आएगा। करपात्री महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में यह आकार पा रहा है। धर्म सम्राट के हाथों आठ दशक पहले स्थापित श्रीराम दरबार की झांकी सहेजे मंदिर को देवालय संकुल का रूप दिया जा रहा है। नए साल में 28 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा।

खास यह कि लगभग 43 हजार वर्ग फीट में विस्तारित देवालय बनारसी मिजाज की तरह रामस्य ईश्वरः या रामः यस्य ईश्वरः (रामेश्वर) के अर्थ जाल से दूर खड़ा शैव-वैष्णव एका की नजीर की तरह नजर आएगा। इसमें सियाराम के साथ ही शिव-राम तो शक्ति और पंचदेव का भी दर्शन एक साथ हो जाएगा।

राम दरबार के ठीक सामने विशाल मंडप के मध्य पांच फीट आकार में शिवलिंग तो दोनों ओर 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग की कतार होगी। बगल में शिव परिवार और स्फटिक मणि का द्वादश ज्योतिर्लिंग दरबार तन-मन को शिवमय करेगा। परिक्रमा पथ पर अगले हिस्से में सूर्यदेव व काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव, पिछले हिस्से में एक ओर गणपति देव तो दूसरी तरफ मां दुर्गा अभयदान मुद्रा में कृपा बरसाएंगी। राम दरबार के बगल में ही मां अन्नपूर्णेश्वरी काशीवासियों के भरण-पोषण के लिए बाबा भोले शंकर को भिक्षादान के विधान निभाएंगी।

तंत्र मंत्र का भी जतन : अनूठे देवालय संकुल में दस महाविद्याएं यानी तंत्र साधना की दस देवियां भी पूरी दिव्यता के साथ भय-बाधाओं से मुक्ति का आशीष बरसाएंगी। इनमें भगवती काली, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला का दरबार सजेगा। इस लिहाज से भी यह मंदिर को अनूठा बनाएगा।

वाराणसी के धर्म संघ शिक्षा मंडल परिसर में ऐसा होगा श्रीराम मंदिर का स्वरूप। फोटो : धर्म संघ शिक्षा मंडल

मणि मंदिर

धर्म संघ परिसर में करपात्री महाराज ने 1940 में श्रीराम दरबार की स्थापना की थी। शिलान्यास समारोह में चारों शंकराचार्य के साथ ही तत्कालीन काशीराज महाराज विभूति नारायण सिंह ने भी भागीदारी की थी। धर्म सम्राट के शिष्य व धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी ने तीन साल पहले मंदिर को भव्य-दिव्य स्वरूप देने का संकल्प लेते हुए कार्य शुरू कराया। चुनार व जोधपुर के लाल पत्थरों से इसका निर्माण कराया तो भीतर की दीवारों को श्वेत संगमरमर और फर्श ग्रेनाइट से सजाया जा रहा है। धर्म संघ सचिव जगजीतन पांडेय के अनुसार शिवलिंगों में स्फटिक मणि के प्रयोग के कारण 11 शिखरों से युक्त देवालय संकुल को मणि मंदिर नाम दिया गया है।

भगवान राम से जुड़े 41 स्थलों की नेटवर्किंग से खुलेगा नया द्वार

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से उनकी ससुराल एवं माता जानकी के जन्मस्थान जनकपुर के बीच पड़ने वाले स्थलों की नेटवर्किंग सिर्फ अयोध्या ही नहीं, मार्ग में पड़ने वाले जिलों में पर्यटन का नया द्वार खोल सकती है। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिनी अवध-मिथिला सम्मेलन में भगवान राम की जनकपुर यात्रा पर विवेचन हुआ, जिसमें यह तथ्य रखा गया कि यदि यात्रा में पड़ने वाले स्थानों की नेटवर्किंग की जाए तो यह पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम होगा।

सम्मेलन के पहले दिन अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित व अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. वाइपी सिंह ने इस विषय को रखा। भगवान राम की जनकपुर यात्रा मार्ग पर 41 ऐसे स्थल हैं, जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये स्थल यूपी, बिहार और नेपाल के 16 जिलों में स्थित हैं। इसमें यूपी में अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बिहार में बक्सर, पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल में जनकपुर व धनुषा जिला पड़ता है। इनमें बक्सर में पड़ने वाला रामेश्वरमनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, विश्वामित्र आश्रम, अहिल्या आश्रम, मधुबनी जिले का गिरिजा मंदिर, नेपाल के जनकपुर में रंगभूमि व धनुषा में धनुष मंदिर प्रमुख स्थान हैं। अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. वाईपी सिंह कहते हैं कि मार्ग के बनने से ये स्थल आसानी से पर्यटन स्थल के रूप विकसित हो सकेंगे।

बननी चाहिए ऑल वेदर रोड : प्रो. मनोज दीक्षित ने यह तथ्य साझा किया था कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों में मिथिलांचल के लोगों की संख्या बेहद कम है। इन स्थलों की नेटवर्किंग के लिए ऑल वेदर रोड की जरूरत हैं। यह मार्ग पर्यटन की संभावनाओं से भरा पड़ा है। यदि ऑल वेदर रोड बनी तो पर्यटन का नया द्वार खुलेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 17 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

जीवन को सार्थक बनाना है तो पहले उसका उद्देश्य समझना होगा

खतरनाक राजनीति

यह अच्छा हुआ कि नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा थमने पर ही मामले को सुनने की बात कह कर उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जिन्होंने पहले तो अराजक तत्वों को हिंसा के लिए उकसाया और फिर पुलिस की ज्यादती का रोना रोया। वास्तव में यही काम कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे पुलिस की कथित ज्यादती का तो उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हिंसक तत्वों के खिलाफ एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं। यह तब है जब अराजक तत्वों की हिंसा में करीब तीन दर्जन पुलिस कर्मी घायल हुए। प्रियंका गांधी का धरना हिंसक तत्वों की अराजकता से ध्यान बंटाने की कोशिश का ही हिस्सा अधिक जान पड़ता है। वैसे तो राजनीतिक दल पहले भी लोगों की भावनाओं से खेलकर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं, लेकिन नागरिकता कानून को लेकर उनकी ओर से जैसा दुष्प्रचार किया जा रहा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सरकार की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस कानून का देश के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी कई राजनीतिक दल यही माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में तो इस दुष्प्रचार के साथ-साथ हिंसक तत्वों को शह भी दी जा रही है। यह भारतीय राजनीति का खतरनाक रूप है।

क्या देश के विभिन्न मुस्लिम शिक्षा संस्थानों के छात्रों को बरगलाकर सड़क पर उतारने वाले यही नहीं साबित कर रहे कि उन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुसंख्यकों की चिंता खाए जा रही है? अगर भारत इन देशों के बहुसंख्यकों के बजाय वहां सताए और अपमानित किए जा रहे अल्पसंख्यकों की परवाह कर रहा है तो इसे लेकर आसमान सिर पर उठाने का क्या मतलब? क्या भारत कोई धर्मशाला है कि जो चाहे यहां बस जाए? ध्यान रहे कुछ समय पहले म्यांमार के रोहिंग्याओं को भारत में बसने देने की जिद पकड़ी गई थी? नागरिकता कानून के विरोध में अराजकता फैलाने वाले संविधान की दुहाई तो देने में लगे हुए हैं, लेकिन इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं। क्या संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ऐसा ही भीषण उत्पात मचाते हैं? इस उत्पात को लेकर केंद्र सरकार को केवल सतर्क ही नहीं रहना होगा, बल्कि नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार की काट भी करनी होगी और वह भी मुस्तैदी से।

कैग के सवाल

अगर खर्च कमाई से अधिक हो जाए तो साख पर सवाल उठना लाजिमी है। वही व्यक्ति या संस्थान कामयाब कहलाता है, जो खर्च को कमाई से अधिक न करे। यही बात सरकार जैसी संस्था पर भी लागू होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2017-18 की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि प्रदेश में आय के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है। सदन पटल पर रखी रिपोर्ट में आर्थिक प्रबंधन की कई खामियों की ओर इंगित किया गया है। कैग ने खुलासा किया है कि प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले खर्च तीन फीसद अधिक किया जा रहा है। यहां तक कि प्रदेश का राजस्व घाटा ही एक साल में 922 करोड़ रुपये बढ़ गया है। आय के मुकाबले व्यय अधिक होने की वजह से सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कैग की मानें तो आने वाले दस साल में सरकार को साढ़े 21 हजार करोड़ के कर्ज एवं 9483 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करना है। इसके अलावा कई सरकारी विभागों के कार्यों पर असंतोष जताया गया है और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग एवं योजना विभाग सड़कों के लिए विधायकों को पूछना तक गंवारा नहीं समझते। मनमानी से सड़कों को नाबार्ड में डाला जाता है। आबकारी एवं कराधान विभाग भी ठेकेदारों पर मेहरबान रहा और उन पर कार्रवाई करने से बचा रहा। कई योजनाओं पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया है। कैग ने रिपोर्ट के माध्यम से जो चेतावनी दी है, उस पर सरकार को गंभीर होकर कार्यप्रणाली में सुधार लाने होंगे। पूर्व की खामियों से सबक लेकर खामियों से पार पाने के उपाय करने होंगे। आय के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय किया जाना भी जरूरी है। कर्ज लेकर थोड़े समय के लिए मुसीबत को टाला तो जा सकता है, लेकिन यह स्थाई समाधान नहीं है। इसके लिए जरूरत है कि उन क्षेत्रों की पड़ताल करनी चाहिए, जिनसे राजस्व का सृजन हो सकता है। सत्तापक्ष और विपक्ष को मिलकर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। खर्च में कटौती के उपायों पर भी गंभीर होना होगा। आय के संसाधन बढ़ेंगे तो कर्ज से मुक्ति की तरफ कदम बढ़ेंगे और प्रदेश खुशहाल होगा।

कैग रिपोर्ट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उन पर बात होनी चाहिए। उन खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है

भारतीय हितों की जानबूझकर अनदेखी

शंकर शरण

जो अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम 'उत्पीड़ितों' के लिए आहें भर रहे हैं उन्होंने कभी भी कश्मीरी पंडितों के अपमान, विस्थापन पर एक शब्द नहीं कहा

दुनिया भारत को हिंदू देश जानती है। अनुच्छेद 370 हटाने को सामान्य बताते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा था कि 'वह तो हिंदू देश है', लेकिन यही देश यानी भारत जब पड़ोस के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण दे रहा है तो आपत्ति हो रही है। आपत्ति करने वालों में अग्रणी हिंदू परिवारों में जन्मे नेता और बौद्धिक भी हैं। उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हिंदू धर्म-समाज के सिवा सबकी चिंता है। उन्हें हिंदू समाज के अतिरिक्त कहीं कोई अंधविश्वास, क्रूरता, गंदगी नहीं दिखती। यह विचित्र संवेदनहीनता है। विडंबना यह है कि यह संवेदनहीनता स्वतंत्र भारत में विकसित हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमेपन को 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' कहकर कोसा गया, जबकि कारण नेहरूवादी कम्युनिस्ट नीतियां थीं। हालांकि गत सात सौ साल से भारत हिंदू शासकों द्वारा नहीं, वरन विदेशियों से शासित रहा, फिर भी सारी गड़बड़ी का कारण हिंदू समाज को बताया जाता है। वस्तुतः लंबी विदेशी दासता और विजातीय शिक्षा ने एक वर्ग को आत्महीन बना दिया है। वे हिंदुओं पर होने वाले अन्याय, भेदभाव से निर्विकार रहते हैं, जबकि बाकी देश-विदेश के किसी भी समूह के लिए भरपूर परेशान होते हैं। इसी का नया उदाहरण सामने है। सत्तर वर्षों से उपेक्षित, अनाथ हिंदुओं, बौद्धों और अन्य ऐसे ही अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने के निर्णय से वे तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए। वे मुस्लिम आव्रजकों के लिए चिंतित हैं और इस पर संविधान की दुहाई दे रहे हैं। यह भूलकर कि संविधान देश के नागरिकों पर लागू होता है, विदेशी लोगों पर नहीं। अन्य देशों, लोगों, घटनाओं आदि पर नीति आवश्यकतानुसार बनती है। जैसे यह तर्क मूर्खतापूर्ण है कि किसी देश के साथ संधि की तो दूसरे के साथ क्यों नहीं की? वैसे ही कहा जा रहा है कि एक शरणार्थी को लिया तो दूसरे को क्यों नहीं लिया? जो लोग अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम 'उत्पीड़ितों' के लिए आहें भर रहे हैं, उन्होंने कभी भी देश के अंदर ही चार लाख कश्मीरी पंडितों के अपमान, विस्थापन और सामूहिक संहार पर एक बयान तक नहीं दिया, जुलूस और विरोध तो दूर की बात है। इसी तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, मलेशिया आदि में हिंदुओं और अन्य अल्ससंख्यकों के साथ होते दुर्व्यवहार, जुल्म पर कभी एक शब्द नहीं कहा। अरब देशों में काम करने वाले लाखों हिंदू अपने धर्म-त्योहार नहीं मना सकते, मगर इस पर हमारे बौद्धिकों ने कभी औपचारिक प्रतिवाद नहीं किया। नागरिकता कानून पर सारे शोर-शराबे के पीछे भारतीय हितों के विरोध की राजनीति है। यह अन्य धर्मों के दुखियारों की चिंता हरगिज नहीं है। यह हिंदू धर्म-समाज पर चोट करने, लज्जित, अपमानित करने का नया बहाना है। इन निंदकों ने कभी जेहादियों या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की भी आलोचना नहीं की। माओवादियों, उग्रवादियों की क्रूर हिंसा पर भी उन्हें कुछ

महसूस नहीं होता, किंतु कोई हिंदू संगठन अपने मंदिरों पर इस्लामी या सरकारी कब्जा हटाने की मांग करे तो इन्हें नागवार लगता है। वे अयातुल्ला खुमैनी और यासीर अराफात जैसे शासकों के लिए शोकमग्न होते हैं। यही भावना औपचारिक शिक्षा तक में घुसा दी गई है। पाठ्य पुस्तकों में महानतम हिंदू ज्ञान-ग्रंथों के प्रति भी तिरस्कार मिलता है, जबकि हिंसा और अंधविश्वास से भरी सामग्री के प्रति आदर भरे लंबे-लंबे अध्याय हैं।

रोज घटने वाले ऐसे विचित्र कारनामों की सूची अंतहीन है। उनमें केवल एक समान तत्व है। हर हिंदू पीड़ा और चाह की निंदा, खिल्ली उड़ाना तथा हर मुस्लिम, ईसाई गतिविधि को समर्थन या उनका बचाव, चाहे वह गैर-कानूनी, हिंसक और अमानवीय ही क्यों न हो। नियमित ऐसे समाचार आते रहते हैं, लेकिन नागरिकता का मुद्दा जनसांख्यिकी समस्या से भी जुड़ा है, इसलिए यह अधिक गंभीर है। आज यूरोप और अमेरिका में भी जनसांख्यिकी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यह जेहादी हथियार के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी की हालिया जीत में यह एक प्रमुख कारण है, जहां लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निश्चय दोहराया। वे अरब से आने वाले शरणार्थियों को रोकना चाहते हैं, क्योंकि कई इस्लामी संगठनों की रणनीति मुस्लिम आबादी बढ़ाकर प्रभुत्व कायम करना है। बहुत पहले लाहौर में इस्लामी देशों की एक बैठक में यूरोप में मुस्लिम आव्रजन बढ़ाकर 'जनसांख्यिकी प्रभुत्व' की योजना घोषित की गई थी। कुछ भारतीय मुस्लिम नेता भी ऐसी बातें कहते रहते हैं। वे कश्मीर पर मुंह सिले रखते हैं, पर बोस्निया, अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों के लिए नियमित बयान जारी करते रहते हैं। यह पूरा परिदृश्य मामले की गंभीरता दिखाता है।

पूर्वी यूरोप ने तो मुस्लिम आव्रजन पर पूरी पांबदी लगा दी है। आरके ओहरी की पुस्तक 'लांग मार्च ऑफ इस्लाम' में दुनिया के जेहादी आंदोलनों का लेखा-जोखा है। जब दुनिया में मुस्लिम आबादी 18 प्रतिशत थी तो केवल सात देशों में जेहाद चल रहा था। आज यह आबादी बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है तो तीस देश जेहाद की मार झेल रहे हैं। सीरिया, लेबनान, बोस्निया, कोसोवो इसके उदाहरण हैं।

याद रहे कि भारत विभाजन भी जेहादी सिद्धांत पर हुआ था। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव में भी जेहाद का उल्लेख था। फिर भारत में कश्मीर या बंगाल को भारत से अलग करने की बात भी केवल मुस्लिम संख्या बल के आधार पर ही की जाती रही है। तब क्या दुनिया के एकमात्र हिंदू देश भारत को फिक्र नहीं करनी चाहिए कि यहां जनसांख्यिकी और न बिगड़े? यहां के मुसलमान पहले ही अपने लिए एक अलग देश तक ले चुके हैं। ये बातें कोई सांप्रदायिकता, असहिष्णुता नहीं, बल्कि अपना धर्म और देश बचाने की चिंता है। इससे आंख चुराने को प्रगतिशीलता कहा जा रहा है। वास्तव में इसी कारण बंगाल और दिल्ली की हिंसा पर चुप्पी साधी जा रही है। यह एक सुनियोजित साजिश ही है कि पहले लोगों को उकसाया गया, फिर जब वे हिंसा पर उतरे तो अराजकता फैलाने वालों के बजाय पुलिस और सरकार को कोसा जा रहा है।

यह दुखद है कि सेक्युलर-वामपंथी बौद्धिक जिस पीड़ा, अन्याय और भेदभाव की चिंता सारी दुनिया के लोगों के लिए करते हैं, वह सौ वर्षों से हिंदू भी झेल रहे हैं, किंतु हमारे विचित्र बौद्धिक इन्हें अपने हाल पर छोड़ अपना आक्रोश और दुख बाकी हरेक के लिए व्यक्त करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि व्यक्ति की तरह हर देश की भी अपनी आत्मा और नियति होती है। भारत की आत्मा और नियति हिंदू धर्म से जुड़ी है। इसकी रक्षा और चिंता करना किसी सच्चे भारतीय का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यह हमारे देश ही नहीं, विश्व के हित के लिए भी जरूरी है, लेकिन उसकी अनदेखी करने को ही बौद्धिकता का पर्याय बना दिया गया है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सुधार मांगती आपराधिक न्याय प्रणाली

वैभव कृष्ण

आपराधिक न्याय प्रणाली की किसी एक कड़ी को दुरुस्त करने से काम नहीं चलेगा। इसमें व्यापक सुधारों से ही बात बनेगी

बीते दिनों हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश उबल पड़ा। इस मामले में आरोपितों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने से एक अलग तरह की बहस भी खड़ी हो गई। इस मामले ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली यानी सीजेएस को लेकर नए सिरे से कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन पर विचार करना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहला पहलू तो पुलिस द्वारा एफआइआर यानी प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़ा है। इस पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग, मलिमथ समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तमाम प्रतिवेदन बेहद महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अलग-अलग अनुशंसा की हैं। सबसे पहले तो प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। मसलन क्या हमें वही पुरानी परिपाटी कायम रखनी चाहिए कि कोई पुलिस स्टेशन दुष्कर्म और हत्या से लेकर डाटा चोरी जैसे पेचीदा साइबर मामलों और बैंक धोखाधड़ी एवं फर्जी पोंजी योजनाओं जैसे आर्थिक अपराध और तमाम आम घरेलू झगड़ों के मामले में भी वैसी ही कार्रवाई करे। इन सभी मामलों में पहले एफआइआर दर्ज कर फिर उनकी पड़ताल करनी होगी। या फिर तंत्र को इस तरह सुगठित करना होगा कि आम धोखाधड़ी के मामले किसी और विभाग को सौंपे जाएं। एफआइआर को लेकर हमें यह भी समझना होगा कि पुलिसकर्मियों से लेकर बुनियादी ढांचे के लिहाज से प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पास बेहद सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में मामलों की गंभीरता को लेकर उनकी प्राथमिकता तय की जा सकती है। जैसे कई राज्यों ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए अलग पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था शुरू की है। कुछ ऐसे ही इंतजाम दूसरे आम अपराधों के लिए भी किए जा सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति वाले कुछ दीवानी मामलों को पुलिस स्टेशन की देहरी तक पहुंचने से रोका जा सकता है। कम से कम उन शहरी पुलिस स्टेशनों तक तो इसे संभव किया जाए जो पहले से ही बहुत ज्यादा काम के बोझ तले दबे हैं। इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अपराधों से निपटने के लिए प्रतिभा, नए तौर-तरीकों, वित्तीय एवं मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसमें आंतरिक टकराव न हों, उसे टालने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव करने होंगे।

भारत में एफआइआर का बहुत महत्व है। अगर किसी का नाम किसी कारण से एफआइआर में आ जाए तो वह व्यक्ति आपराधिक इतिहास के दायरे में आ जाता है। इस कारण भविष्य में पासपोर्ट बनवाने, हथियार लाइसेंस लेने या किसी अन्य मकसद के लिए जब भी उसके पुलिस रिकॉर्ड की जरूरत होगी तब-तब वह एफआइआर उसका पीछा करेगी। वर्ष 2007 में मेरी तैनाती बतौर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी में थी। वहां मैंने सभी संज्ञेय अपराध दर्ज कराने को प्रोत्साहन देने के लिए 'एफआइआर मेला' शुरू किया। इससे कुछ ही दिनों में सैकड़ों एफआइआर दर्ज हो गईं। एक एफआइआर में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी का नाम भी आया। असल में गांव में उनके भाई का एक पड़ोसी से विवाद था और जैसा कि अधिकांश भारतीय गांवों में परंपरा है कि किसी विवाद में संबंधित व्यक्ति के पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है वही इस मामले भी हुआ जबकि वह आइएएस अधिकारी काफी अरसे से अपने गांव ही नहीं गए थे। मैंने किसी तरह उनका नाम एफआइआर से हटवाया। यदि निर्बाध रूप से एफआइआर की व्यवस्था करनी है तो उससे पहले इन विसंगतियों को दूर करना होगा।

सीजेएस में सुधार की पहली कड़ी एफआइआर के मोर्चे पर न्यायिक हस्तक्षेप की दरकार होगी ताकि पुलिस अपने लिए सही लक्ष्य तय कर सके। दूसरी कड़ी जांच की गुणवत्ता से जुड़ी है। सभी राज्यों में जांच मुख्य रूप से इकबालिया बयानों पर अधिक और साक्ष्यों पर कम आधारित होती है। आदर्श रूप में जांच साक्ष्यों पर आधारित हो जिसके लिए आधुनिक फोरेंसिक लैब जैसे बुनियादी ढांचे और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की दरकार होगी। तीसरी कड़ी अभियोजन पक्ष को व्यापक रूप से सुधारने से जुड़ी है। निचली, सत्र अदालतों में अभियोजन अधिकारियों की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय है। कुछ राज्यों में तो ये राजनीतिक नियुक्तियां बन गई हैं। उनके प्रदर्शन को आंकने की प्रणाली भी दोषपूर्ण है।

सीजेएस में सुधार की चौथी कड़ी के तहत विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं को कानून में जरूरी बदलावों के अनुसार शीघ्रता से निपटाना होगा। किसी मामले में जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी संबंधित न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में कई साल लग जाते हैं। आरोप तय करना ही मुकदमे का पहला पड़ाव होता है। इस तरह कुछ साल दोषसिद्धि पर चर्चा के बजाय आरोप तय करने में ही निकल जाते हैं। इसमें निचली अदालतें और असंवेदनशील नजर आती हैं जो जांच अधिकारियों की अनदेखी कर महिलाओं से जुड़े अपराधों में बयान दर्ज कराने में ही कई दिन लगा देती हैं। उनमें भ्रष्टाचार भी गंभीर चिंता का विषय है। इस कड़ी में पांचवां पेच जमानत रद करने की पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने से जुड़ा है। क्या इसे तय करने का अधिकार जिला पुलिस अधीक्षक को दिया जा सकता है और क्या जमानत रद करने के मामले में सरकारी वकील अदालतों में उसकी ओर से पैरवी कर सकते हैं? यह बहुत ही लिखापढ़ी और लंबी खिंचने वाली प्रक्रिया है। इन दिनों अदालतों द्वारा अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक जैसा चलन भी बेहद आम है, लेकिन क्या इन मामलों में पुलिस समय से और प्रभावी अपील कर सकती है? वास्तव में आदतन अपराधियों से निपटने में अभियोजन के पास कोई रणनीति नहीं होती। वे बार-बार अपराध करते हैं, लेकिन उन्हें पूर्व में मिली जमानत खारिज नहीं होती। आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने की छठी कड़ी का संबंध दीवानी न्याय प्रणाली में समांतर सुधारों से जुड़ा है। असल में अपराध रोकना दोनों का साझा दायित्व है।

किसी भी समाधान के लिए हमें सबसे पहले समस्या को समझना होगा। अपराध रोकने के लिए सीजेएस में आवश्यक सुधार करने होंगे। पुलिस इसका विकल्प नहीं है। सीजेएस की किसी एक कड़ी को दुरुस्त करने से काम नहीं चलेगा। इसमें व्यापक सुधारों से ही बात बनेगी।

(लेखक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

असंभव के विरुद्ध

जिंदगी की जद्दोजहद पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं होतीं। कभी मनुष्य के सम्मुख तो कभी विरोधी होती हैं। संघर्ष ही जिंदगी है। अतः संघर्ष के लिए व्यक्ति को हर समय मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अस्तित्व एवं वर्चस्व की लड़ाई में विवेकवान व्यक्ति ही सफलता की मंजिल चूम पाते हैं, लेकिन अक्सर संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति का साहस घटने लगता है। वह इतना भयभीत होने लगता है कि संघर्ष की चुनौती को स्वीकार करना ही छोड़ देता है। ऐसे लोगों के लिए भाग्य के दरवाजे भी सदैव बंद ही रहते हैं। जीवन में कुछ किए बिना ही जय जयकार संभव नहीं है। व्यक्ति के कर्म ही उसे इस चराचर जगत में यश, कीर्ति और वैभव के अलंकारों से अलंकृत कर सकते हैं। संघर्ष से मुंह मोड़ने वालों से जिंदगी की तमाम खुशियां भी मुंह मोड़ लेती हैं। दुनिया में जितने भी धनपति हैं उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे से पड़ाव से की और वे परिणाम की चिंता किए बगैर निरंतर गतिशील रहे। भौतिक परिस्थितियां मजबूत इच्छाशक्ति के आगे बौनी हैं। शरीर बीमारियों का घर है और मृत्यु की बीमारी हर व्यक्ति के लिए लाइलाज है, लेकिन मन की शक्ति इन बीमारियों से लड़ने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है।

इतिहास और वर्तमान ऐसे कई व्यक्तियों की दास्तानों से भरा पड़ा है जिन्होंने मृत्यु को भी अपनी अदम्य साहसशक्ति से विचलित करके उसे एक नए जीवन में रूपांतरित करने का करिश्मा किया। इसलिए जो व्यक्ति किसी कार्य को असंभव मानकर मेहनत और उसके लिए साहस जुटाने का प्रयास ही नहीं करता उसके समक्ष ये मिसालें किसी बड़े साक्ष्य से कमतर नहीं हैं। अक्सर यूपीएससी और आइआइटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर ऐसा हौवा बना दिया जाता है कि कई छात्र उसमें सफल होने की कल्पना करना ही छोड़ देते हैं। उन्हें समझना होगा कि यदि किसी व्यक्ति ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते।

देवेंद्रराज सुथार

आदिवासी समाज में विभाजन

चंदन कर्ण

झारखंड में यह मांग उठने लगी है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर किया जाए

झारखंड का आदिवासी समाज भीतर ही भीतर सुलग रहा है। यह सुलगाव उस समाज के ही अंदर घर कर रहे उस विभाजन के कारण है, जो वहां के आदिवासियों को सरना और ईसाई धर्मसमूहों में बांटता है। कई लोगों का मानना है कि राज्य में विभिन्न ईसाई मिशनरी सेवा की आड़ में लंबे समय से राज्य के आदिवासियों के धर्मांतरण में लिप्त हैं, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरना आदिवासियों और उनके नेताओं की ओर से यह मांग उठने लगी है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर किया जाए। इनका तर्क है कि कोई अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति का फायदा एक साथ नहीं ले सकता। धर्मांतरण विरोधी नेताओं के बीच यह धारणा है कि चर्च उनके खिलाफ साजिश रच रहा है और उनके धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि उनकी मौलिकता और पहचान खत्म कर उन्हें ईसाई खेमे में लाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईसाई धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों के जीवन में कई चीजें बदल जाती हैं। मसलन वे चर्च जाने लगते हैं और परंपरागत पूजा स्थलों जैसे मांझी थान एवं जाहेर थान से उनका नाता टूट जाता है। अपने सामाजिक संस्कारों और पर्व-त्योहारों से भी उनका दुराव होने लगता है। उन पर ऐसे आरोप भी हैं कि वे अपने सजातीय सरना परिवार की बेटियों को स्वीकार नहीं करते अथवा इसके लिए उन पर ईसाई धर्म को स्वीकार करने की शर्त रख देते हैं। इन सब कारकों की वजह से सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच दूरी बढ़ रही है।

हालांकि राज्य सरकार ने झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता बिल, 2017 पास किया है, जो लोभ या लालच के आधार पर धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। इस कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया है। कानून बनने से धर्मांतरण पूरी तरह से तो नहीं रुका है, लेकिन विभिन्न आदिवासी बहुल जिलों में धर्म परिवर्तन के लिए उपायुक्तों के पास आने वाले आवेदन पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि झारखंड भी अन्य कई जनजातीय बहुल राज्यों की तरह संविधान की पांचवीं अनुसूची से संरक्षित है, जहां राष्ट्रपति वहां के राज्यपाल की सलाह पर राज्य के लोगों की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं इन जनजातीय समूहों की सभ्यता-संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए? हालांकि इस विचार के विरोधियों का तर्क यह है कि आदिवासी पहचान धर्म पर आधारित नहीं है। लोग आदिवासी जन्म से होते हैं और इनसे जनजातीय अधिकार कोई छीन नहीं सकता। बहरहाल चुनावी मौसम में इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है, जहां भाजपा और सरना आदिवासियों के संगठन धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक के पक्ष में हैं, वहीं प्रदेश के ईसाई संगठन इस तरह के किसी भी संभावित कदम का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल लोभ और लालच के द्वारा धर्मांतरण को अवैध बनाकर भाजपा ने पहली बाजी तो जीत ही ली है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दुविधा-ग्रस्त मानसिकता

अश्विनी कुमार ने अपने आलेख 'अयोध्या प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप' में एक लेखक से अधिक एक राजनीतिक नेता होने का परिचय दिया है। वह कोई बात स्पष्ट कहने से बचे हैं। उनकी दुविधा पूरे आलेख में उजागर है। क्या अच्छा नहीं होता कि वह साफ-साफ कहते कि मुस्लिम समाज के पैरोकार बने कुछ लोग पूरे हृदय से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकार कर विवादित स्थल हिंदू समाज को सौंप दें और मंदिर बनाने में हाथ बटाएं, जैसा कि शिया धर्मगुरुओं ने कहा है। इससे राष्ट्रीय एकता के वातावरण का सृजन होता। कांग्रेसी नेतागण दोनों नावों पर सवार होने की कोशिश करते हैं। एक ओर कट्टरपंथियों को खुश करना, दूसरी ओर न्याय की बात कर निष्पक्ष दिखने का प्रयास। इसी नीति के अंतर्गत उन्होंने अपनी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दिया कि राम काल्पनिक हैं, लेकिन साथ में जनता के बीच रामराज की बात भी करते रहे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, सो बेचारे गए नीचे। अश्विनी कुमार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतुलित और इंसाफ करने वाला बताते हैं, किंतु अगले ही वाक्य में लिख देते हैं कि यह विधि के सिद्धांतों का उल्लंघन है और 'अदालत ने समान नागरिकता के संवैधानिक संकल्प को पूरा नहीं किया।' इसमें समान नागरिकता का संकल्प कहां से आ टपका? अदालत राममंदिर पर निर्णय करने बैठी थी। उससे संबंधित पुरातात्विक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सर्वसम्मत निर्णय उसने सुनाया। वास्तव में इस निर्णय में राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन था। वहीं वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन निरंतर इस कोशिश में रहे कि अंतिम निर्णय टला रहे, ताकि दोनों प्रमुख समाजों में खटास का मुख्य कारण विद्यमान रहे। राष्ट्रीय हित पर ऐसी चोट एक राष्ट्रीय कहे जाने वाले दल को शोभा नहीं देती। कांग्रेस यह बात कब सीख सकेगी, यह देखना बाकी है।

अजय मित्तल, मेरठ

दोषियों को मिले सजा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्भया के एक दोषी की पुनर्विचार याचिका पर अभी सुनवाई की जाएगी। वर्ष 2012 में घटी यह दुखद घटना अभी तक लोगों के दिलों दिमाग में ताजा है, ऐसे में सात साल बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिल पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान होना चाहिए।

वैशाली, पूर्वी दिल्ली

बढ़ती महंगाई

देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर अब दूध में भी 3 रुपये किलो तक बढ़ोतरी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई पर नियंत्रण ऐसे विषयों पर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आम जनता इस महंगाई के एवं गिरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रकोप से बच सके।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

दहेज की बुराई

देश में देहज प्रथा बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे जहां गरीब लोगों के सामने बेटियों की शादी की समस्या खड़ी होती है, वहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। बहुत लोग गलत तरीके से भी पैसा कमाकर शादियों में दिखावा करते हैं। अगर इस पर रोक लग जाए तो बेटियों को लेकर गरीब की चिंता दूर होगी और भ्रष्टाचार भी कुछ सीमा तक कम हो सकता है।

मो. जमील, नई दिल्ली

चिंतनीय घटनाएं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दुष्कर्म पर दिए बयान पर जो प्रतिक्रिया हो रही है वह जायज है, लेकिन विरोध करने वाले दलों एवं नेताओं को यह भी सोचना होगा कि वाकई में पिछले छह-सात सालों से जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और फलस्वरूप हत्याएं की जा रही हैं, वह वाकई में बहुत ही चिंतनीय है। राहुल गांधी या अन्य इस मुद्दे पर बोलें या ना बोलें, लेकिन महिला अपराध के आंकड़े इस कड़वी सच्चाई को झुठला नहीं सकते। महिला सुरक्षा के हित में कानून व्यवस्था को कड़ा करना होगा। साथ ही विकृत मानसिकता के लोगों पर अंकुश लगाना होगा।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

18 करोड़ भारत के नागरिकों को रात में भर पेट भोजन नसीब नहीं होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र की एक संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक भी दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में रहते हैं।

आजकल

ऐतिहासिक भूल सुधार है नागरिकता कानून

शिव प्रकाश
संयुक्त महासचिव (संगठन) भाजपा

धर्म के आधार पर हुए देश के बंटवारे को स्वीकार कर कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूल की थी उसका परिणाम भुगतने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह गए लाखों-करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों के हितों की सुरक्षा का उपाय केंद्र की भाजपा सरकार ने कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिये उन सभी अल्पसंख्यकों के लिए भारत अब कानूनी तौर पर उनका स्थायी निवास बन पाएगा। सरकार का यह कदम किसी खास धर्म के विरोध में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि इसे भारतीय समाज को उसकी जड़ों की तरफ लौटाने वाले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो काम देश की आजादी के तुरंत बाद शुरू हो जाना चाहिए था वह अब शुरू हो रहा है

नागरिकता संशोधन कानून के विसेध में नई दिल्ली में पुलिस पर पत्थर फेंकते उपद्रवी। एपी

नागरिकता संशोधन कानून को ऐतिहासिक परिदृश्य में देखना आवश्यक है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था, तब के अखंड भारत में देश की स्वाधीनता के लिए चल रहे आंदोलन में प्रत्येक क्षेत्र के देशभक्त लोग हिस्सा ले रहे थे। वर्ष 1947 में देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना। बंगाल का एक हिस्सा भी धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे में पाकिस्तान का अंग बना जो अंततः बाद में बांग्लादेश के रूप में सामने आया। यहां महत्वपूर्ण यह है कि बंटवारे के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के कई लोग थे जो अपने-अपने क्षेत्रों रहकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और विभाजन के बाद वहीं रह गए।

बांग्लादेश में ऐसे ही एक महान देशभक्त थे त्रिलोक नाथ चटर्जी। उच्च कोटि के देशभक्त चटर्जी का अपनी जन्मभूमि पर ही रह जाना क्या उनके दोष के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने भारतमाता को अपनी मां मानकर अपने प्राण उसके सम्मान की खातिर बलिदान कर दिए, ऐसे असंख्य लोगों के हितों की रक्षा करना आज के सभी राष्ट्रभक्तों का दायित्व है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए ऐसे सभी हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई राष्ट्रभक्तों को समायोजित करने का काम किया है।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध वही राजनीतिक दल कर रहे हैं जो अरसे से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वर्ग विशेष के मतों की राजनीति करते आए हैं। उनके विरोध का मूल आधार भी मात्र उनका राजनीतिक लाभ ही है। सभी ने एक स्वर में संसद और उसके बाहर मुसलमानों को नागरिकता देने के अधिकार से वंचित रखने का आरोप सरकार पर लगाया। जबकि इस विधेयक के मूल प्रस्ताव से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को भारत में बसने में मदद प्रदान करना है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता। उनकी नागरिकता को यह कानून किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में अपने भाषण में स्पष्ट किया कि यह नागरिकता लेने वाला नहीं, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए और नागरिकता बिल के नाम पर देश के मुसलमानों में भय व संशय पैदा करने से बाज आना चाहिए। यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के समय धर्म के आधार पर देश विभाजन कांग्रेस स्वीकार नहीं करती तो आज यह नौबत ही नहीं आती।

ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा काम पहली बार किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर तेरह हजार सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। इसके अतिरिक्त मनमोहन सिंह ने भी वर्ष 2003 में बांग्लादेश के उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का समर्थन संसद में किया था। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 1947 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भयानक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। कौन नहीं जानता कि इन देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों व ईसाइयों को किस किस प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर महिलाओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए भारत का यह कर्तव्य बनता है कि इतने वर्षों से उत्पीड़ित हिंदू धर्म के विभिन्न समुदायों के इन लोगों को भारत में नागरिकता मिले, ताकि ये लोग सम्मान और अधिकार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

अपने धर्म और समुदाय के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम भाजपा कोई पहली बार नहीं कर रही है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में अपने प्रसिद्ध शिकागो भाषण में यहूदी और पारसियों को शरण देने का जिक्र किया था। भारत ने भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को शरण देने का काम किया है। सभी जानते हैं कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हुई है। अकेले पाकिस्तान के आंकड़े ही बताते हैं कि कैसे वहां हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों की स्थिति खराब होती चली गई। स्वतंत्रता के समय वहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी। आज वहां इनकी संख्या ढाई प्रतिशत से भी कम रह गई है। यह स्थिति तब है जब स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखने संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने समझौते का सम्मान किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया यह वहां के अल्पसंख्यकों के आंकड़ों से ही स्पष्ट हो जाता है।

विपक्षी दल संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देकर सरकार पर जनता के समानता के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा रहे हैं। इन दलों का यह भी कहना है कि भाजपा चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर सभी फैसले ले रही है। इसी तरह के आरोप कश्मीर में धारा 370 और तीन तलाक समाप्त करने के समय भी लगाए गए थे। लेकिन इन दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा से इनका विरोध करते आ हैं और हमारा स्पष्ट मानना रहा है कि ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलें है जिनका सुधार करना आवश्यक है। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों में भी सदैव ये मुद्दे शामिल रहे हैं। जनता ने हमारी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह भी इन मुद्दों का अब स्थायी हल चाहती है। कांग्रेस छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमेशा इन मुद्दों को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करती रही है।

विरोध से झलकती हताशा!

लोकमित्र

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर भारत के अनेक इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई विश्वविद्यालयों के छात्र विरोध के नाम पर अपनी ताकत अराजकता पैदा करने में दिखा रहे हैं। हालांकि नागरिकता कानून को लेकर तमाम लोगों को आशंकाएं हैं और एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है, लेकिन इस विरोध का एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक रास्ता था। राजनीतिक पार्टियों को अपने विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से आम लोगों के बीच ले जाना चाहिए था, तब शायद इसका असर सरकार पर भी पड़ता और लोकतंत्र भी मजबूत होता। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपने विरोध को महज संसद में मतदान तक सीमित कर दिया है। जब एक बार ये पार्टियां संसद के पटल पर मतदान में पराजित हो गईं तो उन्हें लगता है अब उनके विरोध की इतिश्री हो गई है।

अगर देश में छात्र इस कदर उबल रहे हैं तो कहीं न कहीं यह विरोधी पार्टियों के अंदर घटती लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, जद्दोजहद और लोकतांत्रिक चेतना का अभाव तो है ही, साथ ही यह उनमें व्यावहारिक धरातल पर उतरकर पसीना बहाने की आनाकानी का भी नतीजा है। यही वजह है कि जो काम राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए था, वह काम अराजकता की स्टाइल में छात्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिहाज से यह कतई सही नहीं है।

विरोधी राजनीतिक पार्टियां अपनी जिम्मेदारी और भूमिका का बोझ छात्रों के कंधों पर नहीं डाल सकतीं, ना ही छात्रों को विरोधी राजनीतिक पार्टियों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निश्चित रूप से किसी भी जीवंत लोकतंत्र में छात्रों की अपनी राजनीतिक भूमिका होती है, लेकिन यह भूमिका सरकार के विरुद्ध विपक्ष देने की नहीं होती है। विरोध की अगुवाई विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को ही करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के पहरेदारी के मामले में उनकी भूमिका ना सिर्फ छात्रों से कहीं ज्यादा है, बल्कि छात्रों में लोकतांत्रिक समझ व चेतना विकसित करने का दायित्व भी इन्हीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का है। अगर विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका नहीं निभाएंगी और उनकी भूमिका निभाने की कोशिश छात्र करेंगे तो यह न सिर्फ राजनीतिक माहौल के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य पर भी रोड़े अटका सकता है। जीवित लोकतंत्रों में हर वर्ग की अपनी तय और सशक्त भूमिका होती है। अगर किसी ने भी अपने हिस्से की भूमिका किसी और को सौंपी तो लोकतंत्र अराजकता के रास्ते पर चल पड़ेगा, और फिलहाल ऐसा ही होता लग रहा है।

छात्रों को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, बसों में आग लगाएं, दमकल गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ करें, शहर के नागरिक जीवन को बंधक बनाने की कोशिश करें। किसी भी तर्क से इस सबकी छूट नहीं हो सकती। निश्चित रूप से अगर जामिया के छात्रों के साथ वे राजनीतिक दल, जो नागरिकता कानून के संबंध में वैसी ही सोच रखते हैं, जैसी सोच यहां के छात्रों की है तो उन्हें आगे आकर इन छात्रों की अगुवाई करनी चाहिए थी। इससे पुलिस को यह छूट नहीं मिलती कि वह छात्रों के साथ दमनपूर्ण रवैया अपनाती और ना ही छात्र इस तरह उग्र होते कि वे नागरिक जीवन को बंधक बनाने की कोशिश करते।

विस्तार से देखें तो देश भर में इस कानून को लेकर छात्रों और दूसरे आम लोगों में असंतोष दिख रहा है, वह कहीं न कहीं देश के राजनीतिक विपक्ष के असफल हो जाने का नतीजा है। दरअसल जब लोकतंत्र में विपक्ष किसी भी वजह से अर्थहीन हो जाता है तो राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ और संदेश दोनों ही मनमानी शक्ल अख्तियार करने लगते हैं। फिलहाल ऐसा ही होता दिख रहा है। नागरिकता कानून के संबंध में चाहे आम लोग हों या विश्वविद्यालय छात्र, ये सब वही समझ रहे हैं, जो उनकी समझ में आ रहा है। अगर राजनीतिक विपक्ष इस मामले में राजनीतिक बहस छेड़कर इसके लिए देश में एक राजनीतिक शिक्षण का माहौल बनाता तो इस कानून के बारे में आम लोगों को व छात्रों को भी बेहतर जानकारी होती। तब अगर इसका विरोध भी हो रहा होता तो उसका रूप अलग होता और उसका प्रभाव भी अलग होता। लेकिन फिलहाल विरोध का जो रूप है, वह हताशा से भरा है।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

खरी-खरी

शेर के नाखून पर सत्ता की नेलपॉलिश

जवाहर चौधरी

आप जंगल के राजा हैं। सरकार आपकी ही होनी चाहिए। पांव आगे कीजिए, नेलपॉलिश लगा दें आपको। 'बुजुर्ग अनुभवी दादू' ने शेर के पंजे के नाखून रंग दिए। फिर बोले, देखिए शेर साहब, लाल चमकते नाखून कितने सुंदर लगते हैं। ध्यान रखिएगा पॉलिश खराब न हो।

समय के साथ हरेक को बदलना पड़ता है। बुजुर्ग दादू नाखून पकड़ कर दांत पकड़ने में माहिर है। उसने कहा- राजन, लोकतंत्र में शेर वही होता है जो दहाड़ने के बजाए मुस्कराए और हमला करने के मौकों पर हाथ जोड़े।

'ये मुझसे नहीं होगा। आप कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहे हैं।'

'सरकार बनानी है या नहीं? जंगल आपके हाथ से निकल जाएगा। आप मुस्कुराना सीखिए। हम लिपस्टिक लगा देते हैं,' दादू ने शेर के होठ रंग दिए।

शेर का दिमाग घूमने लगा- 'दादू! कितना गलत मैसेज जाएगा!'

'राजन, राजनीति में मैसेज का नहीं, मैसेज में राजनीति का महत्व होता है। आप अगर शेर के अलावा कुछ समझे गए तो सीटें बढ़ेंगी। सीटों के चक्कर में ही हमें एक और हरल्ली पार्टी का समर्थन लेना पड़ रहा है।'

'ठीक है, सरकार हर हाल में हमारी बननी चाहिए,' शेर ने कहा।

'उनका कहना है कि आपको डायपर पहनना होगा और खादी भी,' दादू बोले।

'खादी पहनी नहीं हमने आजतक। वैसे भी खादी हमारे उसूलों के खिलाफ है। और ये डायपर क्यों?'

'देखिए राजन, नंगा शेर अच्छा नहीं लगता। वैचारिक नंगापन दिखाने के बाद डायपर पहनना जरूरी है। विकास का प्रतीक है डायपर। और करोड़ों लोग खादी देखकर ही वोट देते हैं।'

'लेकिन दादू, खादी पहनेंगे तो हमारी पहचान खो जाएगी।'

'शेर की पहचान सत्ता से होती है!'

'चलो ठीक है, पहन लूंगा। अब सरकार बनवाइए फटाफट।'

'अब तो बन ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाथी निकल गया है, बस पूंछ फंसी है,' दादू ने पांसा फेंका।

'अभी भी पूंछ बाकी है!' शेर चौंका।

'कभी-कभी मैडम हाथ में रिंग लेकर दिखाएंगी। बस आपको उसमें से कूदते रहना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक-दो बार कुछ लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। बाद में तो मजा भी आने लगेगा। सोचिए सरकार बनाने जा रहे हैं आप।' दादू ने समझाया।

ट्वीट-ट्वीट

मनीष सिसोदिया रविवार को दिल्ली पुलिस पर जिस बस फूंकने का आरोप लगा रहे थे वह बस डिपो में पूरी तरह सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, ऐसा करना एकदम उचित होगा।

सुनील जैन@thesuniljain

अगर जामिया में दिल्ली पुलिस ने ज्यादती की है तो उसकी जवाबदेही बनती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को भी जायज करार नहीं दिया जा सकता।

वीर सांघवी@virsanghvi

मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए और समझाए कि अगर भारत सरकार राजकीय धर्म इस्लाम वाले पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करती है जो 2014 से पहले भारत आ गए थे तो उससे हमारे देश के मुसलमानों पर क्या असर पड़ने वाला है?

इम्तियाज हुसैन@hussain_imtiyaz

उत्तराखंड डायरी

चुनौती संगठन का मुखिया चुनने की

कुशल कोठियाल
स्थानीय संपादक, उत्तराखंड

प्रदेश में भाजपा आजकल संगठनात्मक चुनाव की चुनौती से जूझ रही है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी यह तलाश अब भी जारी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर तक नए प्रदेश अध्यक्ष को बागडोर सौंपी जानी थी, लेकिन अब दिसंबर अंत तक का समय इसके लिए घोषित किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष का पद चुनौती इसलिए बना, क्योंकि सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी होने के कारण दावेदारों की संख्या बढ़ी है। साथ ही भीतर ही भीतर तिकड़म और जुगाड़ भी बहुतायत में चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो पैरामीटर सामने आए हैं वे कुल मिलाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुविधापूर्वक सरकार चलाने में सहायक होने वाले हैं। यह सावधानी बरती जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा न हो जो सरकार पर भी हावी हो जाए एवं बात बेबात सरकार पर संगठन का चाबुक चलाने लगे। भाजपा की पिछली सरकारों में कई मर्तबा यह देखने को मिला है। इसके अलावा जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्यमंत्री गढ़वाल से हैं तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो। मौजूदा राजनीतिक बिसात पर फिट बैठने वाले को ही खोजने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री को सुहाने वाले प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कब पूरी होगी यह तो भाजपा के बड़े नेताओं को भी नहीं मालूम, लेकिन सीएम के करीबी इस बात से भी आशंकित हैं कि कहीं खोज लंबी चली तो पुराने प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को ही दूसरी बार यह कुर्सी नसीब न हो जाए। पार्टी का एक धड़ा इसके लिए प्रयासरत भी है।

प्रतीकात्मक

चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक : सामान्य तौर पर भगवा रुझान के लिए जाने जानी वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार इसी तरफ से विरोध का सामना कर रही है। प्रदेश सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम सहित 51 मंदिरों के व्यवस्थित संचालन एवं यात्रियों की सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड के गठन का फैसला लिया। कैबिनेट के फैसले के बाद से ही चारधाम के पुरोहित समाज ने आंदोलन खड़ा कर दिया है।

दरअसल सरकार द्वारा कई बार यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि श्राइन बोर्ड बनने से उनके परंपरागत अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पुरोहित समाज देहरादून की सड़कों पर उतर आया है। मामला गरम होते हुए देखते ही देखते कांग्रेस के नेताओं एवं विधायकों ने इसे लपक लिया है और परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक मानी जाने वाली इस जमात में सेंध मारने की सुनियोजित कोशिशें सदन से लेकर सड़क तक कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पंडा-पुरोहितों के साथ अखाड़ा परिषद का होना भी स्वाभाविक ही था। बावजूद भारी विरोध के प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित करके ही दम लिया। हालांकि विरोध अब भी जारी है, लेकिन आम लोग इसे सही कदम मान रहे हैं। आम जन की राय को देखते हुए कांग्रेस कुछ तो परेशान भी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए हरिद्वार में स्लाटर हाउस बनाना भी भारी पड़ रहा है। स्थानीय जरूरतों को देखते हुए जनपद हरिद्वार के मंगलौर नाम के स्थान पर प्रदेश सरकार स्लाटर हाउस बनाने जा रही है। हरिद्वार जनपद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद भी इसके विरोध में उतर आई है। हालांकि यह हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सरकार को तो करीब से ही विरोध झेलना पड़ रहा है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या प्रशांत किशोर के साथ आने से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा?

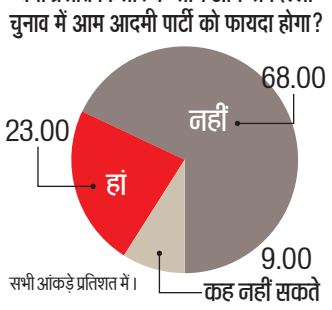

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नागरिकता कानून पर सरकार अपना पक्ष सही तरह से पेश नहीं कर पाई है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शिक्षा के मंदिर लगें यदि करने उत्पात,
इससे बढ़कर देश से क्या हो सकता घात।
क्या हो सकता घात कौन इनको भड़काता?
छात्र वेष में कौन भला है आग लगाता??
एक बहाना ढूंढ़ उपद्रव की है इच्छा,
करि इनकी पहचान दीजिए इनको 'शिक्षा'।

- ओमप्रकाश तिवारी

समस्या- समाधान

आबादी नियंत्रण के लिए बने नीति

डॉ. शांत लाल
सेवानिवृत्त अध्यापक, गो.ब.पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विवि, पंतनगर

देश भर में निरंतर बढ़ती आबादी से पैदा हो रही समस्याओं को देखते हुए आबादी नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने की ओर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए

भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी तीन दशक यानी वर्ष 2050 तक इसमें 27 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। वर्ष 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना एक चुनौती होगी।

बढ़ती हुई जनसंख्या सचमुच एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। केंद्र सरकार के सभी प्रयत्नों के बावजूद आर्थिक विषमता बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार करीब 18 करोड़ भारतीय नागरिकों को रात को भर पेट खाना नसीब नहीं हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में रहते हैं। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सबसे अधिक भारत में है। आर्थिक विषमता और बेरोजगारी के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है। आबादी बढ़ेगी तो मकान बनाने ही पड़ेंगे। कृषि योग्य भूमि कम होगी। रेत, बजरी तथा इमारती लकड़ी की मांग बढ़ेगी तो खनन होगा और पेड़ भी कटेंगे। मोटर वाहन तथा रेलगाड़ियां अधिक चलेंगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। खेती में प्रयुक्त होने वाले पानी के साथ-साथ पीने योग्य पानी की भी उपलब्धता कम होगी। अतः देश की सभी बढ़ती हुई समस्याओं का मूल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है।

जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधनों में चिंता जता चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह समस्या एक चुनौती होगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां बनानी होंगी। केंद्र और राज्य सरकारें पहले से अधिक सुविधाएं देकर छोटे परिवार की ओर लोगों का ध्यान खींच सकती हैं। बेहतर यह होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ऐसी आकर्षक नीति बनाई जाए जिसे देश के अधिकांश लोग अपनाएं, क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है तथा एक धर्म विशेष पर सीमित परिवार रखने का कानूनी दबाव बनाना उचित नहीं होगा। अतः केंद्र की ओर से एक ऐसी आकर्षक प्रोत्साहन वाली नई परिवार नियोजन वाली नीति लाई जाए जिसे सभी लोग अपनाने के लिए आकर्षित हों।

इस परिवार नियोजन प्रोत्साहन नीति में 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवा (युवक एवं युवतियां, जिनकी पारिवारिक आय छह लाख रुपये वार्षिक से कम हो) शामिल किए जाएं। इस नई परिवार नियोजन नीति में 18 से 25 वर्ष के नौजवान युवाओं से स्वैच्छिक अनुबंध भरवाया जा सकता है कि वे 25 वर्ष की आयु तक शादी नहीं करेंगे और उन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। 25 से 30 वर्ष के बीच शादी करने वालों से अधिकतम दो बच्चे पैदा करने का अनुबंध भरवाया जाए और एक-एक हजार रुपये दोनों यानी पति-पत्नी को प्रतिमाह दिया जाए। जो युवक-युवतियां इस बीच शादी नहीं करते हैं उन्हें भी एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह देना जारी रखा जाए और शादी न करने वालों को दो हजार रुपये प्रतिमाह आजीवन भत्ता दिया जा सकता है। इस तरह दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रत्येक परिवार में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इससे गरीब परिवारों को बहुत लाभ होगा। 30 वर्ष बाद जिस परिवार में एक या दो बच्चे ही हैं उन्हें एक हजार का इजाफा करते हुए यानी तीन हजार रुपये प्रतिमाह परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता मिल सकता है।

पति-पत्नी के बीच तलाक होने की स्थिति में पुनः शादी न करने तक दो हजार रुपये प्रतिमाह महिला को तथा एक हजार रुपये प्रति माह पुरुष को मिलता रहेगा। 60 वर्ष की आयु के पश्चात दो हजार रुपये प्रतिमाह या 24 हजार रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा। यह योजना कुछ इस प्रकार की स्वैच्छिक होनी चाहिए जैसी स्वास्थ्य की अटल आयुष्मान योजना है। इस योजना पर व्यय होने वाली राशि का 80 प्रतिशत भार केंद्र सरकार तथा 20 प्रतिशत भार राज्य सरकार वहन करें। इस योजना का लाभ यह होगा कि नौजवान युवा शादी होने से पूर्व ही छोटे परिवार का लाभ समझने लगेंगे। इस प्रकार जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

प्रतीकात्मक

इस योजना का लाभ यह होगा कि पूरे देश में परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता आ सकती है और निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ सकती है।

योजना से हो सकते हैं ये लाभ : इससे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बच्चों में कुपोषण कम होगा तथा शिक्षा बढ़ेगी। बेरोजगारी की समस्या कम होगी। कृषि योग्य भूमि के घटने की दर कम होगी। वाहनों की संख्या धीरे-धीरे कम होने से प्रदूषण का संकट कम होगा। जल संकट भी कम होगा। गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ने से आर्थिक मंदी कम होगी। अपराध कम होने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा।

अब आप के मन में दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला यह कि यदि अनुबंध करने के पश्चात भी तीसरा बच्चा हुआ तो क्या दंड दिया जाएगा। इसके लिए जिस दंपति ने अनुबंध किया है उनका तीसरा बच्चा होता है तो दो से तीन हजार रुपये मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता बंद कर दिया जाए और साथ ही पिता को वोट देने का अधिकार नहीं रहे। इसके बाद भी अगर चौथा बच्चा होता है तो पत्नी अर्थात माता को भी वोट देने का अधिकार नहीं रहे। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े तो संविधान में भी संशोधन करके दो बच्चों से अधिक पैदा करने वालों की व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक योजना है, इसलिए किसी एक धर्म विशेष के विरोध करने का भी कोई औचित्य नहीं है और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सीमित परिवार रखना भी एक प्रकार की देशभक्ति है तो जो अपने देश से प्यार करते हैं वह इस योजना को अवश्य अपनाएंगे।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इतना पैसा कहां से आएगा? तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस योजना के फायदे देखते हुए इस पर किए जाने वाले धन की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहे तो इस कार्य हेतु संपन्न लोग तथा सामाजिक संस्थाएं भी केंद्रीय कोष में धन जमा कर सकती हैं।

डाटागीरी

कम हो रहे हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले

देश में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर लंबे समय से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के आंकड़े इस चिंता को कम करने वाले हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देशभर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में गिरावट आई है।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

जागरूकता के चलते देश में साल दर साल मच्छर जनित बीमारियों के मामले कम हो रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इनमें बताया गया है कि वर्ष 2018 में देशभर में मलेरिया के 4,29,928 मामले सामने आए हैं, जबकि 2018 में ही डेंगू और चिकनगुनिया के क्रमशः 1,01,192 व 57,813 मामले दर्ज किए गए। 2017 की तुलना में तीनों बीमारियों के मरीजों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में मलेरिया के 8,44,558, डेंगू के 1,88,401 और चिकनगुनिया के 67,769 मामले सामने आए थे।

इस रिपोर्ट में मच्छर जनित रोगों के बारे में राज्यों की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2018 में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए थे, जहां 86,486 मरीज इस बीमारी से ग्रस्त पाए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ (78,717), ओडिशा (66,311), झारखंड (57,095) और बंगाल (26,440) में इस बीमारी से पीड़ित सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ कर शेष इन सभी राज्यों में वर्ष 2017 के मुकाबले मलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी आई। 2017 में उत्तर प्रदेश में मलेरिया के 32,345 मामले सामने आए थे।

डेंगू की बात की जाए तो 2018 में इसके सबसे ज्यादा मामले पंजाब में (14,890) सामने आए। हालांकि, 2017 में इसमें गिरावट देखी गई। 2017 में पंजाब में डेंगू के 15,398 मरीज पाए गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र (11,011), राजस्थान (9,587) गुजरात (7,579) और दिल्ली (7,136) में डेंगू के सबसे ज्यादा केस 2018 में सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 की तुलना में पंजाब और दिल्ली में जहां डेंगू के मरीजों की संख्या में गिरावट आई, वहीं अन्य तीन राज्यों में इसके मामले बढ़ गए।

चिकनगुनिया की बात की जाए तो कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा 20,411 संदिग्ध केस सामने आए। वहीं, 2017 में कर्नाटक में इनकी संख्या 32,831 थी। कर्नाटक के बाद 2018 में गुजरात (10,601), महाराष्ट्र (9,884), झारखंड (3,405) और मध्य प्रदेश (3,211) का नंबर आता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया महामारी की तरह फैलने वाली बीमारी हैं, इसलिए इनके मरीजों की संख्या अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न समय पर बदलती रहती है। यानी किसी राज्य में किसी साल में मरीज अधिक हैं तो संभव है कि अगले साल इसमें कमी आए। इसके विपरीत स्थिति भी संभव है।

मलेरिया के मामले

राज्य	2018	2017
उत्तर प्रदेश	86,486	32,345
छत्तीसगढ़	78,717	1,40,727
ओड़िशा	66,311	3,47,860
झारखंड	57,095	94,114
बंगाल	26,440	31,265
देश में कुल	4,29,928	8,44,558

डेंगू के मरीज

राज्य	2018	2017
पंजाब	14,890	15,398
महाराष्ट्र	11,011	7,829
राजस्थान	9,587	8,427
गुजरात	7,579	4,753
दिल्ली	7,136	9,271
देश में कुल	1,01,192	1,88,401

चिकनगुनिया के संदिग्ध मामले

राज्य	2018	2017
कर्नाटक	20,411	32,831
गुजरात	10,601	7,953
महाराष्ट्र	9,884	8,110
झारखंड	3,405	269
मध्य प्रदेश	3,211	2,477
कुल मामले	57,813	67,769

आसान शिकार के चक्कर में आलसी हो चले बाघ!

बड़ा बदलाव ▶ जंगल में भरपूर शिकार उपलब्ध होने के बावजूद आबादी का रुख कर रहे हैं बाघ

जंगल में फुर्तीले पशुओं का कठिन शिकार करने की जगह आबादी में आसान शिकार की पड़ी लत

श्वेतांक शंकर उपाध्याय, लखीमपुर

प्रतीकात्मक चित्र। फाइल फोटो

अपनी फुर्ती और रफ्तार के लिए दुनियाभर में मशहूर बाघ आसान शिकार के चक्कर में आलसी हो चले हैं। अब वे जंगल में मुश्किल से हाथ आने वाले हिरन, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय जैसे जानवरों को छोड़कर आबादी में आसानी से मिल जाने वाले पालतू जानवरों को निवाला बनाकर काम चलाने लगे हैं। इस कारण न केवल उनका विचरण क्षेत्र सीमित हो रहा है, बल्कि फुर्ती भी घटने लगी है।

पर्यावरण संरक्षण

जंगल में भरपूर शिकार उपलब्ध होने के बावजूद बाघ आबादी का रुख क्यों कर रहे हैं बाघ? उत्तर प्रदेश स्थित लखीमपुर खीरी के जंगलों में बाघों पर हुआ यह अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहा है कि आसान शिकार की लत से बाघ आलसी हो रहे हैं। अमूमन एक दिन में छह से सात किलोमीटर तक घूमने वाले बाघ आज महज तीन से चार किमी टहलने के बाद थककर बैठे जाते हैं। बाघों की आरामतलबी और बदलते व्यवहार से वन्यजीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी भी चिंतित हैं। शिकार के नजरिए से वन्य जीवों का संभावित जीवन चक्र प्रभावित होने की आशंका देखते हुए बाघों को पुराने ढर्रे पर लाने के बारे में सोचा जा रहा है।

तराई के लखीमपुर खीरी स्थित बफरजोन को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर सेंचुरी रेंज, महेशपुर रेंज, मैलानी रेंज में 884 वर्ग किलोमीटर जंगल फैला है। यहां 35 से ज्यादा बाघ स्वच्छंद विचरण करते हैं, लेकिन कुछ समय से उनका रुख आबादी की ओर लगातार बढ़ा है। खासकर जंगल से सटे किशनपुर, महेशपुर रेंज के 200 किलोमीटर एरिया में, जहां गन्ने की खेती बहुतायत है। इसी आबादी के निकट 12 से 15 बाघ लगातार डेरा डाले रहते हैं।

पिछले दिनों वन्य जीव विशेषज्ञ और वनकर्मियों ने मानव-बाघ के बीच बढ़ते संघर्ष के बाद यह अध्ययन शुरू किया था। यह पता लगाने के लिए कि आखिर बाघ आबादी के पास ही क्यों डटे हुए हैं? पता चला कि एक तो बाघों की बढ़ती संख्या के चलते जंगल छोटा पड़ रहा है। इस कारण वे आबादी का रुख कर रहे हैं। आबादी-खेतों में उन्हें गोवंश समेत अन्य पालतू जानवरों का शिकार भी आसानी से मिल जाता है।

पांच वर्ष की उम्र होने पर बाघ को व्यस्क माना जाता है। बीमारी या चोट न लगने की दशा में बाघ 15 साल तक फुर्तीला रहता है। जंगली जानवरों का आसानी से शिकार कर लेता है। इसके बाद बाघ कमजोर होने लगता है और आसान शिकार की ताक में आबादी की ओर बढ़ता है, लेकिन अब कम उम्र में ही वह आबादी पर निर्भर हो चला है।

चिड़ियाघर में बाघ को एक दिन में 10 से 12 किलोग्राम, बाघिन को सात से आठ किग्रा मांस दिया जाता है। जबकि जंगल क्षेत्र में सामान्य तौर पर बाघ हफ्ते में एक बार शिकार करता है और 10 से 15 किग्रा मांस तुरंत खा जाता है। अगले दो दिन में उसी शिकार का करीब 30 से 40 किलो भोजन करता है। वन विभाग के मानक के अनुसार, 1200 से 1400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक बाघ का विचरण क्षेत्र (टेरेटरी) होता है। अकेले महेशपुर रेंज में छह हजार हेक्टेयर में करीब 10 बाघों का मूवमेंट इन दिनों है।

शिकार के पीछे दौड़ना दूभर : बाघ के पगचिह्न और उनके मूवमेंट के अध्ययन में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बार-बार जंगल से बाहर जाने वाले बाघ दोबारा जंगल की ओर लौटना नहीं चाहते। वे हिरन, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय जैसे तेज रफ्तार दौड़ने वाले जानवरों के शिकार से भी मुंह मोड़ रहे हैं। लगातार गोवंश और पालतू पशुओं की आसान उपलब्धता ही उनके आलस का कारण बन रही है। एक बार भोजन करने के बाद बाघ सप्ताह भर बाद ही शिकार करता है। लिहाजा, वे आबादी के ही नजदीक ठिकाना बना रहे हैं।

खीरी ही नहीं, हर जगह अब बाघ आसान शिकार के आदी हो रहे हैं। इसीलिए जंगल से निकल आबादी का रुख कर रहे हैं, जहां गाय-भैंस और अन्य पालतू जानवरों के रूप में शिकार आसानी से मिल जाता है। यह सही है कि उसके विचरण का दायरा सिमट रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाघ समय के साथ खुद को ढाल लेगा। स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं।

- डॉ. अनिल कुमार पटेल, उपनिदेशक बफरजोन, लखीमपुर खीरी

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा जल्द ही अतीत के पन्नों में हो जाएगी दर्ज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

प्रतीकात्मक

- सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'नमस्कार भारत' का अंतिम प्रसारण 27 को
- 31 जनवरी को 'दिन भर' कार्यक्रम के अंतिम प्रसारण के साथ बंद हो जाएगी हिंदी सेवा
- डिजिटल माध्यमों पर कुछ नियमित कार्यक्रम का प्रसारण जारी रखने की घोषणा

63 साल के चिन्मय महतो निराश हैं, क्योंकि वे 27 दिसंबर के बाद दिन की शुरुआत करने वाले शब्द 'नमस्कार भारत' नहीं सुन पाएंगे। पिछले 45 साल से उनके दिन की शुरुआत बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन) की हिंदी सेवा की ओर से प्रतिदिन सुबह साढ़े छह बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'नमस्कार भारत' से होती है, जिसका प्रसारण 27 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

चिन्मय महतो जैसे पांच करोड़ भारतीयों के दिन की शुरुआत 'नमस्कार भारत' से होती है। वहीं शाम साढ़े सात बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'दिन भर' का प्रसारण 31 जनवरी 2020 तक होगा। 'दिन भर' के अंतिम प्रसारण के बाद अगले साल 31 जनवरी को बीबीसी हिंदी सेवा की शॉर्ट वेव सर्विस इतिहास बन जाएगी। बीबीसी का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए रेडियो सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। गाइड इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स क्लब चलाने वाले चिन्मय बताते हैं कि शॉर्ट वेव चलाना काफी खर्चीला हो चला है। साथ ही डिजिटल माध्यम आसान होने के कारण अब लोग रेडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं। ड्यूचे विले व वॉयस ऑफ अमेरिका ने भी अपना प्रसारण बंद कर दिया है। फिलहाल रेडियो जापान व चाइना रेडियो इंटरनेशनल से हिंदी व बांग्ला का प्रसारण हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। 1974 से बीबीसी के कार्यक्रमों को सुनने वाले चिन्मय ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब बीबीसी ने हिंदी में शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण समाप्त करने का फैसला किया है। इससे पहले फरवरी 2011 में भी बीबीसी ने घोषणा की थी कि हिंदी रेडियो बंद करने पर विचार कर रहा है।

दिसंबर 2016 से कम कर दिये थे कार्यक्रम : बीबीसी प्रबंधन ने 12 दिसंबर 2016 से अपने रेडियो कार्यक्रमों को कम कर दिया था। हिंदी सेवा ने पहले सुबह आठ से साढ़े आठ तक प्रसारित होने वाला विश्व भारती और शाम को साढ़े नौ से दस बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम घटनाचक्र बंद कर दिया था। हालांकि वह डिजिटल माध्यमों पर अपने कुछ नियमित कार्यक्रम डिजिटल ऑडियो के रूप में प्रसारित करता रहेगा। इनमें विवेचना और दुनिया-जहां जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

कई और सेवाएं भी हो रही बंद : कैरिबियाई देशों के लिए अंग्रेजी प्रसारण, अफ्रीका के लिए पुर्तगाली भाषा में प्रसारण, मैसेडोनियाई और अल्बानियाई और सर्बियाई सेवाएं भी बंद होने जा रही है। इनके अलावा मैंडरिन, तुर्की, रूसी, यूक्रेनी, स्पेनिश, अजेरी और वियतनामी भाषा के रेडियो प्रसारण बंद हो जाएंगे। पिछले साल भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की पहुंच तीन करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ तक हो गई। इसके बाद बीबीसी के श्रोता बड़ी संख्या में शॉर्टवेव रेडियो से डिजिटल और टीवी की ओर चले गए।

सोने की स्याही से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे मनकिरत

बठिंडा के मनकिरत सिंह सोने की स्याही से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हुए। जागरण

साहिल गर्ग, बठिंडा

- बठिंडा के गांव कल्याणा सुखा स्कूल के संगीत अध्यापक का अनोखा संकल्प
- पत्नी के प्रोत्साहित करने पर शुरू किया लिखना, स्कूल प्रबंधन भी कर रहा सहयोग

3 साल में पूरा होगा का काम
2.25 लाख खर्च होंगे स्याही पर
6 घंटे में **19** लाइनें रोज लिखते हैं
10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान

बठिंडा के भगता भाई का के युवा शिक्षक मनकिरत सिंह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन कर उभरे हैं। उन्होंने सोने की स्याही से पुरातन ढंग से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखने का संकल्प लिया है। मौजूदा समय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पदच्छेद कर लिखा गया है, लेकिन मनकिरत पुराने समय में लड़ीवार तरीके से गुरबाणी लिख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) से मंजूरी ली है। उसने प्राचीन तकनीक से विशेष किस्म की स्याही तैयार की है। इसे तैयार करने का फॉर्मूला सिख विद्वान भाई साहिब सिंह ने उन्हें दिया है।

गांव कल्याण सुखा के गार्डन पब्लिक स्कूल में मनकिरत सिंह बतौर संगीत अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं। वह रोज छह घंटे में दो अंग (पन्ने) लिखते हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने भी उनको शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दिया है। मनकिरत ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए स्याही पर ही करीब 2.25 लाख रुपये खर्च होंगे। पूरी लिखाई में 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसकी जिल्द भी सोने की होगी।

कैसे बनती है खास स्याही : श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए भाई साहिब सिंह से लिखित में जानकारी लेकर मनकिरत ने विशेष स्याही तैयार की है। उन्होंने बताया कि आम तौर पर उगने वाली बूटी भृंगराज समेत अन्य सामान डालकर इसकी करीब 20 दिन तक रगड़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद स्याही में सोना मिलाया जाता है। लिखने का काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है। पन्ना नंबर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सिख विद्वान भाई गुरदास के समय लिखे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तर्ज पर ही उन्होंने लिखने का प्रण लिया है। यह काम तीन साल में पूरा होगा।

जपुजी साहिब की वाणी लिख चुके हैं : मनकिरत सिंह ने बताया कि वह जपुजी साहिब की बाणी भी लिख चुके हैं। संगीत से परास्नातक कर चुके मनकिरत अमृतधारी सिख हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें इस पवित्र कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। वे चाहती हैं कि मनकिरत अपने हाथों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखें। मनकिरत ने कहा कि वह अपने काम में इतना खो जाते हैं कि गुरबाणी लिखते हुए पता ही चलता कब छह घंटे बीत गए।

मोबाइल का बैक्टीरिया भी ले सकता है मुन्ने की जान

संतोष शुक्ल, मेरठ

- मेडिकल लैब में की गई मोबाइल की जांच, इकोलाई बैक्टीरिया मिला
- शिशुओं में संक्रमण रोकने में नाकाम हो रहीं तमाम दवाएं
- सतर्कता बरतने की जरूरत

हाथ धोने के बाद मोबाइल छुने से बैक्टीरिया आ जाते हैं हाथ में। प्रतीकात्मक

मोबाइल फोन भी शिशुओं की जिंदगी निगल रहा है। मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की शोध रिपोर्ट में पता चला कि मोबाइल पर चिपके बैक्टीरिया नवजातों की मौत का कारण बन रहे हैं। बाल रोग विभाग ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मोबाइल का कल्चर कराया। इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया (इकोलाई) की पुष्टि हुई। मोबाइल का नियमित कल्चर कर स्टडी रिपोर्ट बनाई जाएगी। शोध में सामने आया है कि यह बैक्टीरिया शिशुओं को कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है।

शिशु के दिमाग तक पहुंच रहा बैक्टीरिया : मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, नवजात शिशुओं में संक्रमण मौत की सबसे बड़ी वजह है। प्रोफेसर डॉ. विजय जायसवाल ने बताया कि वार्ड में सक्शन मशीन, बेड व अटेंडेंट के हाथ पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं, लेकिन मोबाइल फोन सर्वाधिक खतरनाक पहलू बनकर उभरा है। एंटीसेप्टिक विलयन से हाथ धोने के बाद भी मेडिकल स्टाफ व परिजन अक्सर मोबाइल छूते रहते हैं, जिससे इकोलाई और क्लबजेला समेत दर्जनों अन्य घातक बैक्टीरिया संक्रमित होते हैं। नवजातों में कई बार बैक्टीरिया शरीर व दिमाग तक पहुंच जाते हैं। दिमाग के पानी की जांच में मेनिन्जाइटिस की भी पुष्टि हो चुकी है। पेट के संक्रमण से लेकर सेप्सिस तक शिशुओं की जान ले लेते हैं।

दवाएं भी हो रहीं नाकाम

डॉ. विजय जायसवाल ने बताया कि एंटीबायोटिक दवाओं के गलत प्रयोग से बैक्टीरिया दवा से बेअसर हो जाता है। पुरानी दवाएं नाकाम हो रही हैं। सेंसिटिविटी कल्चर में पता चला कि बैक्टीरिया पैटर्न बदल रहे हैं।

ये रखें सावधानी

- अंगूठी, घड़ी व कलावा भी बाहर निकालकर शिशु के वार्ड में जाना चाहिए।
- हाफ शर्ट ही पहनें। सिक्स स्टेप हैंडवाशिंग करना जरूरी है।
- कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया का संक्रमण ज्यादा है, भीड़ से बचें।

मोबाइल फोन सबसे खतरनाक पहलू है। इसके जरिये इकोलाई व क्लबजेला बैक्टीरिया शिशुओं की जान ले रहे हैं। अस्पतालों में नए बैक्टीरिया पल रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाएं बिना परामर्श न खिलाएं। हाथ ठीक से धोएं।

- डॉ. विजय जायसवाल, विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज

पेनकिलर न स्टेरॉयड, तलाशा सर्वाइकल स्पांडलाइटिस का बेहतर इलाज

जागरण संवाददाता, मेरठ

- चरक और चक्रदत्त से लिया फार्मूला, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध

डॉ. निधि शर्मा फाइल

100 से ज्यादा मरीजों पर किया शोध, 20 जड़ी-बूटियों से बना तेल रहा कारगर

एलोपैथ के लिए चुनौती बन चुकी बीमारी सर्वाइकल स्पांडलाइटिस के इलाज में 20 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों से बना तेल रामबाण साबित हुआ। मेरठ की डॉ. निधि शर्मा ने स्पांडलाइटिस के 100 से ज्यादा मरीजों पर शोध किया, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम मिले। शोध को इंटरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस में प्रकाशित किया गया है। मरीजों को दर्द निवारक और स्टेरॉयड से भी निजात मिली। शोध को देशभर में कई कार्यशालाओं में प्रस्तुत किया गया।

महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की पंचकर्म विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. निधि शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल स्पांडलाइटिस के मरीजों पर नस्य, पोटली, स्वेद और अभ्यंग-मालिश की चिकित्सा बेहद कारगर मिली। चरक संहिता और चक्रदत्त के वातरोग अधिकार खंड में इस तेल का जिक्र है, जो दशमूल, उड़द की जड़, रासना, अरंड मूल, निर्गुन्डी समेत करीब 20 जड़ी-बूटियों से बनाया गया। इस तेल की दो-दो बूंद मरीज की नाक में डाली जाती हैं। साथ ही तिल के तेल और घी का पाक बनाकर इसमें सेंधा नमक मिलाते हुए सर्वाइकल स्पांडलाइटिस के मरीजों पर लेप किया गया। मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 15 दिन में मरीजों का न सिर्फ दर्द दूर हुआ, बल्कि उनके बैठने की स्थिति भी सुधर गई। दक्षिण भारत में इस पद्धति से कारगर इलाज किया जा रहा है।

सर्द मौसम में दर्द से परेशान मरीज : कंप्यूटर पर देर तक बैठने, ऑफिस वर्क करने वालों और उठने-बैठने के गलत तरीकों से रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती नसों पर दबाव बनता है। हाथ-पैर में झनझनाहट, सिर दर्द, गर्दन दर्द व चक्कर के रूप में सर्वाइकल स्पांडलाइटिस उभरता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में वातविकार बढ़ने से मरीज परेशान होते हैं। डॉ. निधि ने बताया कि पंचकर्म के इलाज से मरीजों में बीमारी दोबारा नहीं उभरी।

सेब की नई प्रजाति पर दो साल में ही लगेंगे फल

अनुराग उनियाल, नई टिहरी

- पहले चरण में हिमाचल प्रदेश से एक हजार पौधे मंगा रहा उद्यान विभाग
- परंपरागत पेड़ लगाने के बाद छह से दस साल के अंतराल में देते हैं फल

पहले चरण में बड़े काश्तकारों को मिलेंगे पौधे

उद्यान विभाग पहले चरण में नई प्रजाति के एक हजार पौधे मंगाएगा। सेब के बड़े काश्तकारों को यह पौधे दिए जाएंगे। अच्छी पैदावार मिलने पर अगले चरण में जिले के अन्य काश्तकारों को भी पौधे दिए जाएंगे।

उत्तराखंड के टिहरी जिले के सेब काश्तकारों को अब फलों के लिए छह साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उद्यान विभाग पहली बार जिले में एक हजार नई मलिंग मार्टिन सीरीज के सेब के पौधे ला रहा है। इस प्रजाति के सेब की खासियत यह है कि वह दो साल में फल देना शुरू कर देगा। इसमें बीमारी का खतरा भी कम रहता है।

टिहरी में सेब काश्तकार अभी तक परंपरागत पेड़ों के ही भरोसे हैं, जो लगाने के बाद छह से दस साल के अंतराल में फल देता है। यह सेब बीमारी की भी जल्द चपेट में आ जाता है और इसके दो पेड़ों के बीच में छह मीटर की दूरी होना आवश्यक है। इसी को देखते हुए उद्यान विभाग अब हिमाचल प्रदेश से नई मलिंग मार्टिन सीरीज के सेब के पौधे लाने की तैयारी में है। इस सेब की एम-9, एम-111 और एम-26 प्रजाति का पौधे लगाने के दो साल बाद ही फल देना शुरू कर देते हैं। इन पौधों को एक मीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता है। इससे पैदावार भी ज्यादा होती है। इन पौधों को जिले में छह हजार फुट की ऊंचाई वाले स्थानों पर लगाया जाएगा। इन पर बीमारी का खतरा कम होने से नुकसान की आशंका भी कम हो जाती है, जिससे काश्तकारों को राहत मिलेगी।

मलिंग सीरीज के सेब के पौधे आगामी फरवरी में लगाए जाएंगे। इससे सेब की पैदावार बढ़ेगी और काश्तकारों को भी फायदा होगा। इस प्रजाति के पेड़ आकार में छोटे होते हैं, जिस कारण काश्तकारों में इनकी मांग बढ़ रही है।

- डॉ. डीके तिवारी, जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल

हिमाचल प्रदेश के एक बगीचे में लगे मलिंग मार्टिन सीरीज के सेब के पेड़। फाइल फोटो

100 भाषाएं बोलने वाला रोबोट बनाया है ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय ने। अनुवाद करने में दक्ष यह रोबोट चेहरों को पहचान सकता है और फुटबॉल को किक भी मार सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाएं लोग...

जागरण विशेष ▶ दुर्गा शक्ति ने दैनिक जागरण से कहा, आम व्यक्ति को भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत मिले तो खुशी होगी

मनु त्यागी, नई दिल्ली

▶ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण या तापसी पन्नू निभा सकती हैं भूमिका

▶ 'बदला', 'केसरी' जैसी फिल्में देने वाला अजूर एंटरटेनमेंट कर रहा निर्माण

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में खनन माफिया को धूल चटाने वाली आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बनने की खबर पिछले दिनों आई। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण या तापसी पन्नू यह किरदार निभा सकती हैं। फिल्म को लेकर उत्साहित दुर्गा शक्ति ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि इस फिल्म के माध्यम से यदि आम व्यक्ति को भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत मिले तो उन्हें बेहद खुशी होगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष और अनुभव के बारे में दुर्गा ने विस्तार से चर्चा की। कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में आने के बाद बतौर एसडीएम (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट) गौतमबुद्ध नगर में पदस्थापना मेरे करियर का अहम पड़ाव था। मैं देशसेवा के भरपूर जज्बे, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्व का श्रेष्ठतम निर्वाह करने को दृढ़संकल्पित थी। आज यह सोच कर सुखद आश्चर्य से भर उठती हूं कि मेरे जीवन के उस हिस्से पर फिल्म बनने जा रही है...।

दिल्ली टेक्नीकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन से स्नातक (बीटेक इन कंप्यूटर साइंस) 2010 बैच की आइएएस अधिकारी दुर्गा ने कहा, मेरे जीवन का वह हिस्सा देश-समाज के लिए इस तरह प्रेरणादायी समझा जाएगा, तब यह सोचा भी नहीं था। आज खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि फिल्म निर्माता ने प्रेरक विषय के रूप में इसे चुना और अब फिल्म के माध्यम से पर्दे पर लोग उस हकीकत को देखेंगे। दुर्गा ने कहा, इसे देखकर लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पैदा हो सके तो मेरे लिए सर्वाधिक खुशी की बात होगी...।

दुर्गा ने बताया कि प्रोडक्शन हाउस इस रोल के लिए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू से संपर्क में है। संभव है कि दीपिका या तापसी में से ही कोई यह किरदार निभाए। वैसे भी मैं बहुत सरल और सहज महिला हूं, मेरा किरदार करना कठिन नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने खनन के अवैध कारोबार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसे फिल्म के रूप में उसी तरह प्रभावी तरीके से दिखाना निर्देशक के लिए एक चुनौती हो सकती है। सनीर खेत्रपाल (निर्माता, अजूर एंटरटेनमेंट) से मेरी अब तक की बातचीत में मुझे यह लगा कि वे इस विषय को लेकर काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि वह बेहतर फिल्म बनाएंगे।

फिलहाल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में बतौर डेप्युटी सेक्रेटरी तैनात दुर्गा ने 2013 की याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि तब मैंने कैसे खनन माफिया के खिलाफ संघर्ष किया। रात को सुनसान इलाकों में जाकर छापे मारना, बेखौफ खनन माफिया से भिड़ना, इसमें लिप्त लोगों का विरोध झेलना, किसानों की समस्याओं को सुनना, और भी बहुत सारी बातें, आज भी वह सारी घटनाएं मेरे समक्ष मानो दृश्यों के रूप में हैं। पर्दे पर भी सब वैसा ही दिखेगा, वही सब जीवंत होगा। हालांकि जब कोई सच्ची घटना पर्दे पर दिखाई जाती है तो उसमें मनोरंजन का पुट भी दिया जाता है, जो जरूरी भी है।

34 वर्षीय दुर्गा कहती हैं, छह माह बाद फिल्म आ जाएगी, तब देखते हैं कि यह फिल्म किस रूप में और कितना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती है। जिस तरह से मैं अपने माता-पिता से और अपने पति अभिषेक सिंह से, जो खुद भी आइएएस अधिकारी हैं, प्रेरित हूं, उसी तरह लोग इस फिल्म को देखकर प्रेरित हो सकें तो यह मेरे लिए इसका सबसे बड़ा हासिल होगा...। वर्ष 2013 में खनन माफिया से लड़ने वाली दुर्गा को निलंबन झेलना पड़ा था। उसी दौरान पति अभिषेक सिंह को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

फिल्म के नाम के सवाल पर दुर्गा कहती हैं, मैंने अपनी तरफ से निर्देशक को कुछ नहीं कहा है। नाम तय होने पर वह मुझसे जरूर चर्चा करेंगे। हां इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेरित करने वाला ही कोई प्रभावी नाम रखा जाएगा। दुर्गा के पति अभिषेक सिंह वर्तमान में दिल्ली में उपायुक्त पद पर तैनात हैं। एक बेटी है, जिसका नाम दानिया है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

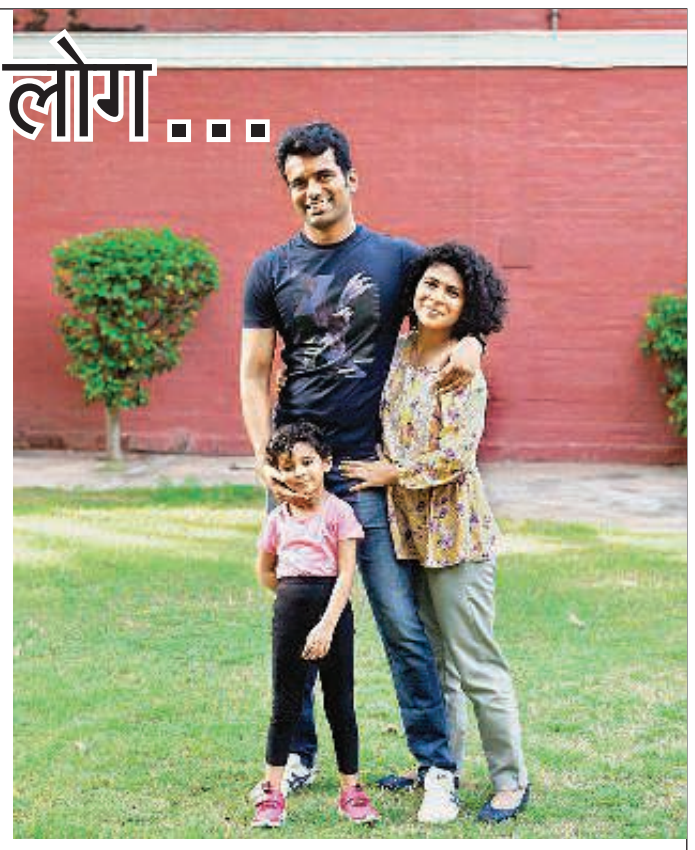

बेटी दानिया शक्ति सिंह और पति आइएएस अभिषेक सिंह के साथ आइएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। सौजन्य : दुर्गा शक्ति

अब रेलवे स्टेशन पर जमा करें बिजली बिल

राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी : अब बिजली बिल नजदीकी रेलवे स्टेशन पर भी जमा करिए। वहां ई-सर्विसेज की सारी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। डिजिटल ट्रैक पर रफ्तार भर रहा रेलवे रोजगार सृजन के साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध सुविधाओं में से अधिकांश सेवा देने जा रहा है। 200 रेलवे स्टेशन पर एक साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद धीरे-धीरे पूरे देश को कवर करने की तैयारी है।

ई-सर्विसेज क्या है : डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सरकार जी-तोड़ मेहनत कर रही। गोपनीय कुछ नहीं, सबकुछ ऑनलाइन। बिजली बिल, आय-जाति, खसरा-खतौनी, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादि। देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, लिहाजा रेलवे ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

वाराणसी मंडल के 64 स्टेशनों पर सुविधा: वाराणसी रेल मंडल के 64 स्टेशनों पर सुविधा देने की तैयारी है। रणनीति सफल हुई इसे 120 स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। स्टेशनों पर वाई-फाई सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।

रेलवे के वाई-फाई उपयोग कर लोगों को ई-सर्विसेज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। रेल मंडल में 22 स्टेशनों पर यह सुविधा दी जा रही है।

-आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ मंडल अभियंता सिग्नल एवं टेलीकॉम

अफ्रीका, पश्चिम एशिया, भारत व चीन होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था मानव

शोध ▶ आनुवंशिक खोज से अछूते मुल्क बांग्लादेश में डीएनए नमूना लेने भारत से पहुंचा दल

एस्टोनिया, भारत और बांग्लादेश के वैज्ञानिक तैयार कर रहे आनुवंशिक डाटा बेस

मुहम्मद रईस, वाराणसी

जीवन की उत्पत्ति और विकास के क्रम में दक्षिण अफ्रीका से निकल कर हजारों साल पहले मानव भारत होते हुए चीन और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। भारत, म्यांमार में कुछ हद तक शोध कार्य जरूर हुए, लेकिन बीच का बांग्लादेश का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह अछूता रहा। अब भारत व एस्टोनिया के वैज्ञानिक इस अछूते हिस्से के लोगों के आनुवंशिक डाटा बेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय व एस्टोनियन जीनोम सेंटर की टीम ने 13 दिसंबर को सिलहट और 14 दिसंबर को ढाका में सैकड़ों नमूने एकत्र किए।

दल पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह भारत व म्यांमार के बीच की आबादी है या बहुत पुरानी जनजाति है, जो उसी समय से इस क्षेत्र में रह रही है जब मानव इधर आया।

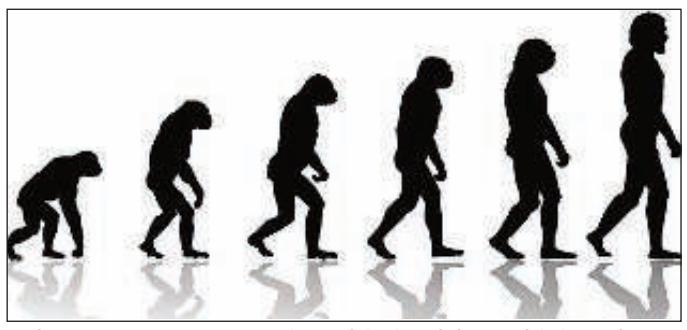

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ढाका विवि व एस्टोनियन जीनोम सेंटर की टीम कर रही है शोध। प्रतीकात्मक

वैज्ञानिकों के मतानुसार दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया से होता हुआ मानव पलायन भारत में हुआ। बाद में समुद्री किनारा पकड़ते हुए मानव बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा।

इस तरह हुई शुरुआत : बीएचयू के डॉ. ज्ञानेश्वर चौबे, ढाका विवि की डॉ. गाजी नूरुन नहर सुल्ताना व एस्टोनिया के डॉ. माइट मैट्सपालू ने नेशनल जियोग्राफी को प्रस्ताव भेजा। एस्टोनिया इस तरह के अध्ययन के लिए आदर्श है, इसलिए नेशनल जियोग्राफी ने प्रस्ताव स्वीकारने में जरा भी देरी नहीं की और 25 लाख का ग्रांट स्वीकृत किया।

65 जिले और 5000 नमूने : शोध के क्रम में बांग्लादेश के नौ राज्यों के 65 जिलों को कवर करते हुए कुल 5000 डीएनए नमूने जुटाने हैं। अब तक करीब 1000 नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें जनजातियों के साथ ही स्थानीय निवासी भी शामिल हैं।

मिश्रित है जबड़ों की बनावट : दंत चिकित्सक डॉ. पवन दुबे के मुताबिक, ऑब्जर्वेशन में स्थानीय जन जातियों के जबड़ों की बनावट में विविधता पाई। मानव विकास के क्रम में जबड़ों की संरचना भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हुई। भारत में ऊपरी जबड़ा आगे की ओर या अधिक आगे की ओर जबकि चीन, तिब्बत एवं पूर्वी एशिया में निचला जबड़ा बाहर की ओर होता है। सिलहट के बेनी बाजार क्षेत्र में इनका मिश्रण पाया गया है।

प्रकृति ने मलेरिया से की रक्षा : मलेरिया से बचाने के लिए प्रकृति ने इनके शरीर में बदलाव किए। हीमोग्लोबिन औसत से कम होना इनमें से एक है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि हीमोग्लोबिन कम होने के बावजूद ये लोग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

बीमारियों से बचाएगी जीनोमिक कुंडली : डीएनए या जीनोमिक स्ट्रक्चर की जानकारी होने पर डायबिटीज, कैंसर सहित हृदय संबंधी बीमारियां समय से पहले डायग्नोस की जा सकती हैं। यानी कुंडली की तरह जीनोमिक कुंडली एक बच्चे में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों की सटीक जानकारी देता है। समय से पूर्व कुछ सावधानियां बरतने पर कई तरह के रोगों से बचा भी जा सकता है। डॉ. ज्ञानेश्वर के मुताबिक, किसी बीमारी में जीनोमिक स्ट्रक्चर के आधार पर यदि व्यक्ति को दवा दी जाए तो वह सबसे कारगर साबित होगा। आने वाला समय पर्सनलाइज मेडिसिन का है।

घाट-घाट के गंगा प्रदूषण पर पीएमओ को पहुंचेगी रिपोर्ट

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

▶ नेशनल सेल साइंस लेबोरेटरी पुणे और इविवि के वैज्ञानिकों की टीम जुटी

▶ प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने दिए साढ़े तीन करोड़ रुपये

गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए बड़े स्तर पर कवायद शुरू हुई है। गंगा जल और इसकी मिट्टी में प्रदूषण के कारण, उनमें जीवाणु और विषाणु की प्रचुरता को जानने के लिए केंद्र सरकार गहन पड़ताल करा रही है। माघ मेला क्षेत्र में सभी घाटों के पानी व मिट्टी का नमूना लिया जा रहा है। इसके लिए नेशनल सेल साइंस लेबोरेटरी पुणे और सेंटर ऑफ बायो टेक्नालॉजी डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए दोनों संस्थानों को साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। दोनों संस्थानों की संयुक्त रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भेजी जाएगी।

सेंटर ऑफ बायो टेक्नालॉजी डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. आदित्यनाथ ने बताया कि संगमनगरी में फाफामऊ से छतनाग और सोमेश्वर महादेव घाट तक के गंगा जल व मिट्टी का नमूना लिया जा रहा है। नागवासुकि, रामघाट, संगम नोज तक आठ घाटों पर किनारे व बीच के पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। मिट्टी और पानी के नमूने की सेंटर ऑफ बायो टेक्नालॉजी डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा नेशनल सेल साइंस लेबोरेटरी पुणे में जांच कराई जाएगी। दोनों संस्थानों की जांच की संयुक्त रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, जल संसाधन व नदी विकास मंत्रालय, नमामि गंगे, जलशक्ति मंत्रालय को भेजी जाएगी। रिपोर्ट में इस बात का विवरण होगा कि किस घाट पर मिट्टी और पानी में बैक्टीरिया, वायरस की मौजूदगी और कितनी है।

डॉ. आदित्यनाथ के मुताबिक, इस पड़ताल से एक प्रकार से जल के डीएनए (डीआक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड) और आरएनए (राइबो न्यूक्लिक एसिड) के स्तर की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें दोनों संस्थानों के 24 वैज्ञानिकों को लगाया गया है। पुणे के वैज्ञानिक भी जल्द ही प्रयागराज आएंगे और फिर दोनों संस्थानों के वैज्ञानिक नमूनों की जांच पर चर्चा करेंगे।

प्रतीकात्मक

तीर्थनगरी ऋषिकेश में होंगे केदारनाथ मंदिर के दर्शन

दुर्गा नौटियाल, ऋषिकेश

▶ योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन के भवन पर तैयार हो रहा केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप

▶ स्टेशन के प्रवेश द्वार पर होंगे भगवान शिव व नंदी की विशालकाय मूर्ति के दर्शन

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का ख्वाब जितना खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत इसकी परिकल्पना है। उत्तराखंड में इस स्वप्निल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे रेल विकास निगम ने इसके रेल स्टेशनों को भी स्थानीय भवन शैली में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसीलिए परियोजना में बन रहे 11 में से चार स्टेशनों पर चारों धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रतिरूप नजर आएगा। इस कड़ी में सबसे पहले तैयार हो रहे योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन को केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है।

रेलवे स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश का काम अपने अंतिम चरण में है। चार फरवरी 2020 से यहां ट्रेनों का संचालन होना है। स्टेशन की खासियत यह होगी कि यहां आकर यात्रियों को विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी और इसके सामने ही भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जा रही है। स्टेशन का मुख्य भवन भी बाहर से केदारनाथ मंदिर की तरह नजर आएगा। परियोजना के निदेशक ओपी मालगुड़ी ने बताया कि शेष अन्य स्टेशनों का निर्माण भी किसी न किसी पर्वतीय भवन की प्रतिकृति होगा। परियोजना के 11 में से किन्हीं तीन स्टेशनों को बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का स्वरूप दिया जाएगा। इन स्टेशनों के चयन को प्रस्ताव मांगे गए हैं।

ऋषिकेश के निर्माणाधीन नए रेलवे स्टेशन को केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। नए स्टेशन की प्रतिकृति। साभार-रेलवे

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के स्टेशन : ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में यूं तो वीरभद्र स्टेशन को मिलाकर कुल 12 स्टेशन होंगे, लेकिन नए स्टेशनों की संख्या 11 है। इनमें पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश है। इसके बाद शिवपुरी, व्यासी, देवप्रयाग, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गौचर व सेवई (कर्णप्रयाग) शामिल हैं।

योग नगरी ऋषिकेश में होंगी 13 लाइन : योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। इस स्टेशन यार्ड में 13 लाइन होंगी। यानी स्टेशन तैयार होने के बाद लंबी गाड़ियों के ऋषिकेश पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी पुराने स्टेशन पर लंबी गाड़ियों के खड़े होने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में गिनती की गाड़ियां ही हरिद्वार से आगे आ पाती हैं।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

घायल बच्ची की तस्वीर का सीएए से कोई लेना-देना नहीं

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

विश्वास न्यूज,एजेंसी: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनने के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ बुरी तरह से घायल बच्ची की तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीएए के विरोध प्रदर्शन में यह बच्ची घायल हुई है। विश्वास न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल हो रही तस्वीर फर्जी है। यह बच्ची बांग्लादेश के ढाका में हुए रेल हादसे में घायल हुई थी। इसका सीएए से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

बनारस: तेरे रंग हजार नाम के फेसबुक पेज पर एक घायल बच्ची की तस्वीर को अपलोड करते हुए लिखा है कि 'बच्ची उस ट्रेन में थी, जिसपर

सीएए के विरोध में शांतिप्रिय कौम के कुछ हजार लोगों ने पत्थरबाजी की थी! हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब केवल एक तरफ से नही बन सकती! हमेशा चाहते हैं देश और शहर का अमन चैन बना रहे लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें अंदर से झकझोर के रख देती हैं! हर मुसलमान शोसल मीडिया पर बाकियो को भड़का रहा है, आखिर वह गलत को गलत कहकर अपने दूसरों लोगों को समझा तो सकता है न???'

पड़ताल: वायरल हो रही पोस्ट और तस्वीर की सत्यता जानने के लिए विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले तस्वीर को Yandex रिवर्स इमेज टूल में अपलोड कर सर्च किया। सर्च के नतीजों में टीम को कई जगह यह तस्वीर अपलोड मिली। इसके बाद टीम "gonews24.com" नाम की वेबसाइट पर गई, जहां इस तस्वीर को अपलोड कर हेडलाइन लिखी गई थी 'महिमा अब अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगी'। यह खबर 12 नवंबर 2019 को अपडेट की गई थी। इस खबर के अनुसार तस्वीर में दिख रही बच्ची का नाम महिमा है और यह बांग्लादेश के ढाका में हुए रेल हादसे में घायल हो गई थी। यह बच्ची अपनी मां की गोद में सो रही थी जब वह रेल हादसा हुआ था। यह तस्वीर टीम को 12 नवंबर 2019 को ही प्रकाशित "dailysomoyerkhobor.com की एक खबर में भी मिली।

अब टीम ने इस मामले को लेकर "gonewswy24" में संपर्क किया तो पता चला कि जिस रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट तैयार की है उसने दृढ़ता से पुष्टि की है कि घायल बच्ची की तस्वीर बांग्लादेश की है। अंत में टीम ने इस पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर की सोशल स्कैनिंग करने का फैसला किया तो पता चला इस पेज को 223,061 लोग फॉलो करते हैं और यह पेज भारत के बनारस शहर से जुड़ी खबरों को ज्यादा अपडेट करता है।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

बदलती तस्वीर

उत्तरकाशी जिले के डामटा में लग रहा कागजी अखरोट का पहला बगीचा, इसके लिए डुंडा में तैयार हो चुकी है कागजी अखरोट और पिकनट की नर्सरी

अखरोट का सिरमौर बनेगा गंगा-यमुना का मायका उत्तरकाशी

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

सेब की तरह अखरोट उत्पादन के लिए भी गंगा-यमुना का मायका उत्तरकाशी जिला सबसे मुफीद है। इसी को ध्यान में रख उद्यान विभाग ने जिले को मिशन अखरोट के तहत बागवानी के लिए चुना है। इस कड़ी में विभाग ने यहां कागजी अखरोट और पिकनट की नर्सरी भी तैयार कर दी है।

अभी तक उत्तरकाशी जिले में फल उत्पादन को लेकर केवल सेब का नाम भी सामने आता है, लेकिन अब जल्द ही यहां के अखरोट भी अपनी खास पहचान बना सकते हैं। इसके लिए उद्यान विभाग ने जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर डुंडा में अपनी भूमि पर कागजी अखरोट और पिकनट की नर्सरी तैयार की है। कागजी अखरोट का पहला बगीचा नौगांव ब्लॉक के डामटा में लगाया जा रहा है। इसके लिए काश्तकारों ने अखरोट उत्पादन का प्रशिक्षण भी ले लिया है। यहां इसी शीतकाल में दो हेक्टयर भूमि पर कागजी अखरोट की पहल चरण में दो हेक्टेयर में अखरोट की बागवानी की जा रही है। अखरोट उत्पादन में उत्तरकाशी को सिरमौर बनाने का लक्ष्य है। साथ ही पिकनट की बागवानी के लिए काश्तकारों को प्रेरित किया जा रहा है। पिकनट अखरोट प्रजाति का ही फल है। विदेशों में पिकनट की काफी मांग है।

- प्रभाकर सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी

बागवानी की जानी तय है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार, दोनों ही पहल कर रहे हैं।

काश्तकारों का बढ़ रहा रुझान : अखरोट उत्पादन में काश्तकारों का रुझान बढ़ रहा है और वह अखरोट के बगीचे लगाने के लिए उद्यान विभाग को प्रस्ताव दे रहे हैं। डामटा के अलावा डुंडा, चिन्यालीसौड़ व भटवाड़ी ब्लॉक के काश्तकारों ने भी आवेदन किया है। बाजार में अखरोट की बढ़ती मांग और अच्छे दाम भी काश्तकारों के रुझान बढ़ने का कारण हैं।

उत्तरकाशी के डुंडा स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी में तैयार की गई कागजी और पिकनट प्रजाति के अखरोट की पौध। साभार : उद्यान विभाग

बच्चों का आधार बनाने में हरियाणा देश में सबसे आगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ प्रदेश में दो करोड़ 88 लाख 24 हजार 146 लोगों के पास आधार कार्ड

▶ नए आधार कार्ड बनाने और संशोधन के लिए जनवरी में विशेष अभियान

पांच साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के मामले में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर है। वहीं सभी नागरिकों का आधार बनाने में दूसरे और पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों-युवाओं का आधार बनाने के मामले में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। 30 नवंबर तक प्रदेश में कुल दो करोड़ 88 लाख 24 हजार 146 लोगों ने आधार कार्ड बनवाए थे। इनमें पांच साल की आयु के 20 लाख 84 हजार 656 बच्चे, 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 66 लाख 6 हजार 783 और 18 साल से अधिक आयु वर्ग के दो करोड़ एक लाख 32 हजार 707 नागरिक शामिल हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला उपायुक्तों से मुखातिब मुख्य सचिव ने कहा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में आधार बनवाने और अपडेशन के लिए 10 दिन के कैंप लगाए जाएं। इस दौरान प्रत्येक जिले में दो मोबाइल वैन चलाई जानी चाहिए। जिन खंडों में आधार बनाने के लिए एनरोलमेंट किट आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं है या काम नहीं कर रहीं तो इसकी सूचना आइटी विभाग को दी जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक महीने में चार दिन के कैंप लगाए जाएं। निजी स्कूलों में भी यह कैंपेन चलाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में शाम को आधार बनाए जा सकते हैं। पांच साल तक के बच्चों का आधार अस्पतालों में बनाना सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 17 दिसंबर 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

एनईएफटी से आठ घंटे में 11.40 लाख लेनदेन

मुंबई : एनईएफटी सेवा 24 घंटे करने के बाद लेनदेन में जबर्दस्त तेजी देखी गई है। आरबीआइ ने बताया कि नए नियम लागू होने के आठ घंटे के भीतर 11.40 लाख लेनदेन हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सेवा को 24 घंटे जारी रखने का प्रावधान किया है। इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से हुई। आरबीआइ ने बताया कि 12 बजे से लेकर शाम आठ बजे तक कुल 11.40 लाख लेनदेन हुए। इस बीच पेटीएम पेमेंट एप 24 घंटे एनईएफटी सर्विस देने वाला पहला एप बन गया है। (प्रेट्र)

कुछ घटनाएं निवेशकों का भरोसा तोड़ती हैं। हालांकि जहां तक सेबी की सीमा में मामला होता है, जरूरत के हिसाब से हम तत्काल कदम उठाते हैं। कार्वी समेत कई मामले इसकी नजीर हैं।
— अजय त्यागी, सेबी के चेयरमैन

सेंसेक्स	40,938.72	निफ्टी	12,053.95	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 38,698	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 45,460	डॉलर	₹ 71.00	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 65.28
▼ 70.99		▼ 32.75		▲ ₹50		▲ ₹234		▲ ₹0.17	

कारपोरेट हलचल

सीजीईडब्ल्यूएचओ कैलेंडर जारी

आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव शिव दास मीणा ने साल 2020 का सीजीईडब्ल्यूएचओ कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर मंत्रालय में संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार एसएस दूबे, डीओपीटी में निदेशक व सीडब्ल्यूओ वनिता सूद, हडको के ईडी अखिलेश कुमार, सीजीईडब्ल्यूएचओ के सीईओ भूपिंदर सिंह और निदेशक (एफएंडए) आरसी अग्रवाल भी उपस्थित थे।

भारत को बैंक और श्रम सुधारों पर जोर देने की जरूरत : आइएमएफ

वाशिंगटन, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारतीय इकोनॉमी की बेहतरी के लिए ढांचागत सुधार की सलाह दी है। आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि भारतीय इकोनॉमी को विकास की राह पर ले जाने के लिए बैंक और श्रम जैसे बुनियादी सुधारों पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।

सरकार का ध्यान सुस्ती को दूर करने, घरेलू मांग और उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर होना चाहिए। पिछली छह तिमाहियों से जीडीपी ग्रोथ सुस्त रही है। मैन्यूफैक्चरिंग में गिरावट के चलते जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान यह 4.5 परसेंट के स्तर पर आ गई। गोपीनाथ ने मोदी सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में ढांचागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजकोषीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास की नीतियां बनाने और कर्ज के उच्च स्तर को कम करने की जरूरत है। इसके लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा और सब्सिडी के रूप में होने वाले खर्च को तार्किक बनाना होगा।

एक प्रश्न के जवाब में गोपीनाथ ने कहा कि भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को पाने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिए जाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने जीएसटी के उचित अनुपालन, टैक्स सुधार और व्यापार

आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने बुनियादी सुधारों पर दिया जोर

गीता गोपीनाथ। फाइल फोटो

के अनुकूल नीतियां बनाने की सलाह दी। इकोनॉमी में बुनियादी सुधारों पर बात करते हुए आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री ने भारत सरकार को तीन नीतिगत प्राथमिकताएं तय करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत सरकार को बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों के सुधार पर जोर देने की जरूरत है। इसके लिए बैंकों का एनपीए कम करना होगा और सरकारी बैंकों में प्रशासनिक सुधार करने होंगे। इसके साथ ही एनबीएफसी सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी पर नजर बनाए रखनी होगी।

गोपीनाथ ने कहा कि राजकोषीय लक्ष्यों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। इसे केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अंजाम देना होगा। प्रशासनिक सुधार और टैक्स अनुपालन के जरिये सरकारी कर्ज को कम करना होगा। उन्होंने राजकोषीय पारदर्शिता में और सुधार की गुंजाइश पर भी जोर दिया। तीसरे ढांचागत सुधार का जिक्र करते हुए गोपीनाथ ने कहा कि भारत में श्रम, भूमि और उत्पाद बाजार में सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अमेरिका-चीन समझौते से ग्लोबल इकोनॉमी को मिलेगी गति : गीता गोपीनाथ ने कहा है कि अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड डील और ब्रेक्जिट जैसे मुद्दों के हल होने से ग्लोबल स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। पिछले कुछ समय से ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती देखी जा रही है। गोपीनाथ ने कहा कि व्यापार के साथ-साथ भू-राजनैतिक कारणों के चलते वैश्विक आर्थिक गतिविधियां सुस्त हुई हैं। आइएमएफ ने वर्ष 2019 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर तीन और 2020 के लिए 3.4 परसेंट आंकी है।

न्यूज गैलरी

उबर ईट्स को खरीदने की तैयारी में जोमैटो

नई दिल्ली : ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो भारत में उबर ईट्स के कारोबार को खरीदने की तैयारी में है। इस महीने के अंत तक यह सौदा पूरा होने की उम्मीद है। सौदे में उबर ईट्स की कीमत करीब 40 करोड़ डॉलर (2800 करोड़ रुपये) आंकी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जोमैटो में उबर 15 से 20 करोड़ डॉलर का निवेश करने जा रही है। (आइएएनएस)

जियो के टावर 25,215 करोड़ रुपये में बेचेगी रिलायंस

नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वह जियो टेलीकॉम के 1.30 लाख टावर 25,215 करोड़ रुपये में कनाडा की कंपनी ब्रूकफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेचेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसकी इकाई रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (आरआइआइएचएल) ने ब्रूकफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी और उसके साझेदारों के साथ टावर कारोबार सौदे पर समझौता किया है। ब्रूकफील्ड इस टावर कंपनी की 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी। (प्रेट्र)

पूर्वोत्तर में 31 दिसंबर तक हो सकेगा अग्रिम टैक्स भुगतान

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अग्रिम कर भुगतान की तीसरी किस्त भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 15 दिसंबर थी। इन राज्यों में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। यह फैसला हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद शुरू हुए तनाव को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान इन राज्यों में इंटरनेट सेवा बाधित रही थी। (प्रेट्र)

तीसरी तिमाही में बढ़ सकता है एसबीआइ का मुनाफा

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि एस्सार स्टील मामले के समाधान से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक के मुनाफे में सुधार की उम्मीद है। दिवालिया में चल रहे कुछ अन्य मामलों के समाधान का असर चौथी तिमाही में दिख सकता है। एस्सार स्टील पर वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं का करीब 54,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। आर्सेलरमित्तल ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना जमा की है। (प्रेट्र)

अमेरिका ने जताई ट्रेड-डील से निर्यात बढ़ने की उम्मीद

वाशिंगटन : अमेरिका ने कहा है कि चीन के साथ हुए पहले दौर के व्यापार समझौते के बाद चीन को होने वाले अमेरिकी निर्यात में इजाफा होगा। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कहा कि पहले दौर की डील को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इस डील से अमेरिकी हितों को बढ़ावा मिलेगा। (रायटर)

कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के जिम्मेदार हैं गैरकानूनी बूस्टर्स

दलील ▶ टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से की शिकायत

विभाग ने 200 दोषियों को भेजे कानूनी नोटिस, कंपनियां एफआइआर के पक्ष में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कॉल ड्रॉप की परेशानी का हल खोजने में विफल टेलीकॉम कंपनियों ने अब गैरकानूनी बूस्टर्स और रिपीटर्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दूरसंचार विभाग से शिकायत में कंपनियों ने कहा है कि गैरकानूनी बूस्टर्स और रिपीटर्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से आम मोबाइल ग्राहकों को कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अकेले दिल्ली-एनसीआर में इस वजह से कॉल ड्रॉप में दस गुना तक बढ़ोतरी हो गई है।

सूत्रों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि गैरकानूनी बूस्टर्स के कारण दिल्ली-एनसीआर में लगभग 8000 सेल साइट्स से जुड़े ग्राहकों को कमजोर सिग्नल्स का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कॉल ड्रॉप में सात से 10 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को दिल्ली की 200 ऐसी जगहों की सूची सौंपकर ऐसे लोगों

प्रतीकात्मक फोटो

के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। टेलीकॉम कंपनियों की शिकायत पर दूरसंचार विभाग ने उक्त सभी उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी नोटिस भेजे हैं। हालांकि नोटिस का कोई खास असर नहीं हुआ है। ये बूस्टर अब भी काम कर रहे हैं। टेलीकॉम उद्योग ने इस पर असंतोष प्रकट करते हुए दूरसंचार विभाग से ऐसे गैरकानूनी रिपीटर्स वाले स्थानों पर छापे डालकर उन्हें हमेशा के लिए बंद कराने तथा बूस्टर्स की बिक्री और इंस्टॉलेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है।

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा इस्तेमाल : टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कमजोर मोबाइल तरंगों को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बूस्टर या रिपीटर्स के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ा है। पहले कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में सिग्नल की तीव्रता बढ़ाने के लिए यह काम केवल टेलीकॉम कंपनियां करती थीं। अब ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइटों तथा ग्रे मार्केट में सस्ते गैरकानूनी बूस्टर मिलने से कोई भी व्यक्ति या संस्था इनके इस्तेमाल में सक्षम है। यहां तक कि मकान मालिक और भूस्वामी भी किरायेदारों को आकर्षित करने के लिए गैरकानूनी ढंग से बूस्टर्स लगवा रहे हैं। इससे सभी ग्राहकों को कॉल ड्रॉप अथवा टूटती आवाज और स्लो डाटा स्पीड जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी वाले इलाकों में 2जी, 3जी और यहां तक कि 4जी के ग्राहकों को भी यह स्थिति झेलनी पड़ रही है।

क्या है बूस्टर?

बूस्टर या रिपीटर्स कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में नजदीकी मोबाइल टावर से उपलब्ध सिग्नल्स को एंप्लीफाइ करके उन्हें छोटी जगहों जैसे इमारतों अथवा कालोनियों में पहुंचाते हैं, जहां टावर लगाना संभव नहीं होता। इससे उस क्षेत्र विशेष के लोगों को बेहतर नेटवर्क मिलता है। हालांकि आसपास के क्षेत्र में सिग्नल और कमजोर हो जाते हैं।

थोक महंगाई में भी बना ऊपर का रुख

प्रतीकात्मक फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से अब थोक महंगाई की दर ने भी ऊपर का रुख अख्तियार कर लिया है। नवंबर, 2019 में थोक महंगाई की दर 0.58 फीसद हो गई है। अक्टूबर में यह 0.16 फीसद थी। पिछले साल नवंबर में थोक महंगाई दर 4.47 फीसद थी।

थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर को ऊपर बढ़ाने में खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी अहम रही है। इन वस्तुओं की महंगाई दर नवंबर में 11 फीसद पर पहुंच गई है। अक्टूबर, 2019 में यह 9.80 फीसद रही थी। गैर खाद्य उत्पादों के वर्ग की महंगाई दर में नवंबर में कमी आई है। यह अक्टूबर के 2.35 फीसद के मुकाबले नवंबर में 1.93 फीसद रही है। मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों में नवंबर में भी 0.84 फीसद की गिरावट का स्तर बना रहा।

खाद्य उत्पादों के मामले में सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अहम रही है। सब्जियों में प्याज की थोक महंगाई दर नवंबर में 34.4 फीसद रही है। सालभर पहले यह 8.32 फीसद थी। कीमतों में वृद्धि के चलते आलू की थोक महंगाई दर 10.32 फीसद हो गई। बीते साल इसी महीने आलू की कीमतों में 3.85 फीसद की दर से कमी आई थी।

वैश्विक पूंजीगत सामान निर्माता भारत में लगाएं प्लांट : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **इस्पात मंत्री बोले, हम बाहर से मशीनों का आयात कर असेंबल नहीं करना चाहते**
- **देश का स्टील सेक्टर विस्तार के दौर से गुजर रहा है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए**

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मशीनरी व अन्य पूंजीगत सामान बनाने वाले वैश्विक निर्माताओं से भारत में अपनी यूनिट स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ा बाजार है और वैश्विक कंपनियां आसानी से यहां आने को तैयार हो सकती हैं।

सीआइआइ द्वारा आयोजित 'स्टीलिंग समिट' में स्वदेशी स्टील एवं खनन कंपनियों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि भारत का स्टील सेक्टर इन दिनों विस्तार के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में नई क्षमता सृजित करने के लिए 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत सामानों की आवश्यकता होगी। स्टील का आयात करते वक्त उद्योग को देखना चाहिए कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं।

जेएसडब्ल्यू का उदाहरण देते हुए प्रधान ने कहा, 'इस कंपनी ने अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने के लिए वहां अपना स्टील प्लांट लगाया है। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम दूसरे देशों के स्टील को भारत आने की अनुमति क्यों दें। हमें इस दिशा में सोचना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि जिन कंपनियों से हम पूंजीगत सामान खरीदते हैं उनसे भारत में प्लांट लगाने को कहें।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत बाहर से बनी मशीनों का आयात कर उन्हें देश में असेंबल नहीं करना चाहता। प्रधान बोले, 'अगर आप उनसे कहेंगे तो वे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि पूंजीगत सामान निर्माताओं को ऐसा विशाल बाजार, ऐसे बड़े ऑर्डर और

स्टीलिंग समिट को संबोधित करते पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पीआइबी

कहां मिलेंगे। भारत ही है जहां इतने बड़े पैमाने पर क्षमता विस्तार होने जा रहा है। किसी अन्य देश में स्टील सेक्टर में इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हमें इसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए।'

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टील इंपोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम (सिम्स) लांच किया है। यह इस दिशा में एक हथियार है। सिम्स सरकार व स्टील निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं को उपयुक्त नीतियां अपनाने के लिए स्टील के आयात के बारे में अपडेट सूचनाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्टील नीति, 2017 के अनुसार भारत ने अपनी स्टील क्षमता को बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है।

'कर व्यवस्था में पूर्वानुमान और निश्चितता की गुंजाइश जरूरी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने टैक्स दरों में निश्चितता और स्थायित्व की वकालत की है। जीएसटी दरों में हुए बदलावों के संदर्भ में सिंह का कहना है कि टैक्स व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूर्वानुमान की भी पूरी संभावना रहे। वहीं रेवेन्यू में वृद्धि के लिए उन्होंने राज्यों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। जीएसटी रेवेन्यू में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की वजह से केंद्र से मिलने वाले कंपनसेशन की दर को लेकर भी सिंह का रुख लचीला है। उनका मानना है कि 14 फीसद की दर से कंपनसेशन दिया जाना जीएसटी विधेयक का हिस्सा है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं हुआ है।

इसी संदर्भ में उन्होंने टैक्स व्यवस्था में निश्चितता बनाए रखने की आवश्यकता बताई। निजी राय के तौर पर उन्होंने राज्यों को रेवेन्यू वृद्धि के उपाय करने को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इनसेंटिव देने की बात भी कही। वित्त आयोग 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुका है, जिसे संसद के बजट सत्र में पेश करने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। साल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की दूसरी रिपोर्ट पर आयोग फिलहाल काम कर रहा है। सिंह ने बताया कि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोग के पास कम से कम तीन तिमाही का वक्त है। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू कलेक्शन की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी जिससे आयोग अगले पांच साल में रेवेन्यू का बेहतर अनुमान लगा पाएगा। जम्मू-कश्मीर के विषय में स्पष्ट करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने वाले आदेश में या उसके बाद आयोग को कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है। लिहाजा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रीय पूल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हें गृह मंत्रालय अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की भांति अनुदान देगा। आयोग की रिपोर्ट में केवल 28 राज्यों को ही शामिल किया जाएगा।

सोमवार को आयोग की आर्थिक सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक थी। बैठक में केंद्र और राज्यों के स्तर पर रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग और जीएसटी काउंसिल के बीच संबंध जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

बजट पूर्व बैठक में टैक्स कटौती की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां इस बार आम बजट में टैक्स छूट की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में इस सेक्टर ने टर्म इंश्योरेंस में जीएसटी कटौती की फरमाइश रखी। सेक्टर का कहना है कि जीएसटी में कटौती से टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा और केवाईसी नियमों के व्यवस्थित होने से वित्तीय समावेश को बल मिलेगा।

बैठक के दौरान वित्तीय और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने सरकारी बैंकों में प्रशासनिक सुधारों की मांग भी की। इस दौरान पीजे नायक कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की अपील की गई। वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि चर्चा के दौरान वित्तीय सेक्टर के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे बैंक, बीमा, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से सुझाव पेश किए गए। बैठक के दौरान टैक्स को लेकर कई तरह के सुझाव आए। सरकार राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इन सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई में वृद्धि हुई है और कर्ज भी बढ़ रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए टैक्स सुधार का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि इसी महीने की 18 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है।

देश में घरेलू मांग बढ़ने पर ही तेज हो पाएगी आर्थिक विकास दर : मूडीज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने वृद्धि दर अनुमान घटाकर 4.9 फीसद किया**
- **आर्थिक सुस्ती का होगा बड़ा असर, कई सेक्टर आएंगे जद में**

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में घरेलू मांग में लगातार हो रही कमी को एक गंभीर समस्या के तौर पर चिन्हित किया है। मूडीज हाल के महीनों में कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को लेकर अपनी चिंता जता चुकी है। सोमवार को उसकी तरफ से जारी एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग के महत्व को देखते हुए इसमें सुधार के बिना बाकी हालात भी नहीं बेहतर होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर घरेलू मांग की स्थिति नहीं सुधरी तो इसका विपरीत असर देश के कई दूसरे कारोबारी क्षेत्रों पर पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करने के साथ ही मूडीज ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 4.9 फीसद पर आ जाएगी। इसमें अगले वर्ष सुधार तो होगा लेकिन विकास दर हाल के वर्षों की तुलना में कम ही रहेगी। पहले मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 5.8 फीसद रहने की बात

प्रतीकात्मक फोटो

कही थी। मूडीज के सहायक वाइस प्रेसिडेंट देवराह टैन का कहना है कि निवेश नहीं आने से मंदी की शुरुआत हुई थी लेकिन अब इसने उपभोग को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में खास बढ़ोतरी नहीं होने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। अगले वर्ष स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वह बहुत उल्लेखनीय नहीं होगा। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनका थोड़ा बहुत ही असर दिखेगा।

रेटिंग एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग की हिस्सेदारी 57 फीसद थी। लेकिन घरेलू मांग कई औद्योगिक व कारोबारी सेक्टर से जुड़ी होती है। इसमें कमी आने का असर दूसरे सेक्टरों पर भी पड़ने लगता है। घरेलू बाजार में ऑटोमोबाइल की मांग में भारी कमी आने का भी कई सेक्टरों पर असर पड़ेगा। मांग में कमी होने का असर है कि आम जनता की वित्तीय लेन देन की शक्ति कम हो रही है, जिससे देश के ऋण बाजार पर असर पड़ेगा।

ग्राहकों को ज्यादा कर्ज देने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों को इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने से लोगों को कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। कर्ज देने वाली कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के मुश्किल हालात सबके सामने हैं।

उठापटक

सत्र की शुरुआत में सार्वकालिक उच्च स्तर तक गया सेंसेक्स, एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में दबाव से आई गिरावट

शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : पिछले तीन सत्रों में तेजी दर्ज करने के बाद सोमवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सत्र की शुरुआत में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जबर्दस्त उछाल दर्ज करते हुए 41,185.03 के सार्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन जल्द ही एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में दबाव के चलते यह गिरावट का शिकार हो गया। इस दौरान जमकर मुनाफावसूली हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 70.99 अंक की गिरावट के साथ 40,938.72 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 32.75 अंक की गिरावट आई। यह 12,053.95 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में आइटीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.97 परसेंट की गिरावट आई। इसके अलावा टाटा स्टील, एचयूएल, वेदांता, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.80 परसेंट तक गिरकर बंद हुए। दूसरी ओर टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, एचडीएफसी और कोटक बैंक के शेयरों में 2.70 तक की तेजी दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते से शेयर बाजारों में उत्साह देखा गया। इसके चलते

प्रतीकात्मक फोटो

सत्र की शुरुआत में जमकर खरीद हुई। लेकिन थोक महंगाई के आंकड़े आने के बाद निवेशकों के उत्साह में कमी देखी गई और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। एशिया के अन्य शेयर बाजारों शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो में मिलाजुला रुख रहा। इस बीच सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 17 पैसे की गिरावट आई। यह 71 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

पीएनबी : आरबीआइ द्वारा इस सरकारी कर्जदाता की एनपीए गणना में खामियां पाए जाने के बाद इसके शेयरों में गिरावट देखी गई। सोमवार को बीएसई में बैंक के शेयर 0.85 परसेंट गिरावट के साथ 63.90 रुपये के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में यह 1.01 परसेंट तक फिसलकर 63.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ।

इंडोको रेमिडीज : सोमवार को इस फार्मा कंपनी के शेयरों में तीन परसेंट तक की तेजी देखी गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 3.03 परसेंट उछाल के साथ 153 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में कंपनी के शेयर 2.44 परसेंट उछाल दर्ज करते हुए 151 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी यूके द्वारा इसके गोवा प्लांट को मान्यता मिलने की सूचना के बाद आई।

नेहा गुप्ता और केपी जोशी एंड कंपनी पर प्रतिबंध

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ट्रेड इंडिया रिसर्च की मालिक नेहा गुप्ता और केपी जोशी एंड कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे उत्पादों को बेचा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसके लिए उन्होंने ग्राहकों को फेक पोर्टफोलियो दिखाए और इनसे लाभ कमाने का लालच दिया। सेबी ने अपनी प्राथमिक जांच में इन आरोपों को सही पाया है। दूसरी ओर ऑडिट फर्म केपी जोशी एंड कंपनी पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। फर्म पर आरोप है कि उसने कोरल हब कंपनी की ऑडिट प्रक्रिया में झूठे दस्तावेज तैयार किए। केपी जोशी इस कंपनी के मालिक हैं।

नीतिगत ब्याज दरों में अभी और कटौती की गुंजाइश : दास

मुंबई, रायटर : रिजर्व बैंक ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह नीतिगत दरों में और कटौती कर सकता है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी ब्याज दरों में और कटौती करने की गुंजाइश है। मौद्रिक समीक्षा के दौरान विकास और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए आगे भी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। हालांकि पिछली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया था।

आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी को गति देने के लिए सरकार और आरबीआइ ने मिलकर कई प्रयास किए हैं। लेकिन ग्लोबल स्तर पर नरमी के कारण यह उपाय अधिक प्रभाव नहीं डाल सके। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष फरवरी में ही आर्थिक सुस्ती को भांप लिया था। इसीलिए रेपो रेट में लगातार कटौती की गई। फरवरी से लगातार पांच मौद्रिक समीक्षाओं में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कुल 1.35 परसेंट यानी 135 आधार अंकों की कटौती की है। नीतिगत दरों में कटौती का यह सिलसिला दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में थमा। इस बार रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए दरों में कटौती से इन्कार कर दिया। दास ने कहा कि इकोनॉमी की बेहतरी के लिए आरबीआइ हरसंभव कदम उठाएगा।

- **महंगाई और अन्य संकेतकों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला**

भारतीय इकोनॉमी में सुस्ती को ग्लोबल सुस्ती से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी भी कहीं न कहीं ग्लोबल स्लोडाउन से प्रभावित हुई है। अमेरिका-चीन के बीच हुई ट्रेड डील के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार होने की उम्मीद है। इस समय दुनियाभर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर सुस्ती का मुकाबला करने की जरूरत है। गौरतलब है कि जुलाई-सितंबर के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5 परसेंट रही थी। यह 2013 के बाद सबसे निचला स्तर है।

304 लोगों की जान चली गई तीन दिनों में ईरान में नवंबर माह में हुए विरोध-प्रदर्शनों के खिलाफ हुई कार्रवाई में। इंटरनेशनल ब्यूरो ने मृतकों की इस नई संख्या की जानकारी दी है। यहां ईंधन की कीमतों में उछाल के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए थे।

चीन में पाकिस्तानी 'दुल्हनों' को बेचे जाने पर घिरी इमरान सरकार

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में 'दुल्हन' के रूप में बेचे जाने के मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार घिरती जा रही है। पाकिस्तान के जानेमाने वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता राहत जॉन आस्टिन ने इमरान सरकार की निंदा करते हुए कहा कि वह उन चीनी नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जो पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। हाल में खबर आई थी कि 2018 से अब तक 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर 'दुल्हन' चीनी नागरिकों को बेच दी गईं। लेकिन चीन के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के चलते पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं कर रहा।

एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान आस्टिन ने कहा, 'पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस भयावह सच को नजरअंदाज कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह विदेशी एजेंडा है। यह पाकिस्तान-चीन की रणनीतिक साझेदारी के खिलाफ साजिश है।' उन्होंने चीनी नागरिकों के हाथों 600 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों को बेचे जाने के सरकारी आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है। आस्टिन ने बताया कि पाकिस्तानी लड़की को बेचने का पहला मामला तीन साल पहले सामने आया था। तब सलीम इकबाल नामक ईसाई लड़की ने यह उजागर किया था कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था। लेकिन इस मामले को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।

भारत के लिए जासूसी का आरोप : आस्टिन ने कहा, 'कुछ पत्रकारों ने इस तरह के मामलों को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसे दबाव का सामना करना पड़ा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हम पर पाकिस्तान व चीन के संबंधों और सीपीईसी प्रोजेक्ट को खराब करने का आरोप लगाया जाता है। लोग हम पर यह आरोप भी लगाते हैं कि अगर कोई हिंदू है तो वह भारत के लिए जासूसी कर रहा है और ईसाई तो इजरायल या अमेरिका के लिए जासूसी या काम कर रहा है।'

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने लगाया आरोप, सरकार नहीं कर रही कार्रवाई

गरीब लड़कियां निशाने पर

पाकिस्तान में गरीब परिवारों और खासतौर पर ईसाई समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उनके परिवारों को मोटी रकम का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि शादी के बाद उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी।

तस्करी में पकड़े गए 31 चीनी किए गए थे बरी

मानव तस्करी में पकड़े गए 31 चीनी नागरिक गत अक्टूबर में फैसलाबाद की एक अदालत से बरी हो गए। एक जांचकर्ता ने बताया था कि पुलिस के सामने मुंह खोलने वाली कई युवतियों ने बाद में अदालत में बयान देने से मना कर किया क्योंकि उन्हें धमकाया गया था या पैसे देकर मुंह बंद करा दिया गया था।

सीपीईसी के रूट में बदलाव कर रही इमरान सरकार : बिलावल

क्वेटा, एएनआइ : पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान सरकार बलूचिस्तान के लोगों को सीपीईसी के फायदे से वंचित रखने के लिए इस प्रोजेक्ट के रूट में बदलाव कर रही है।

विपक्षी दल पीपीपी के नेता ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा, 'हमने बलूचिस्तान के लोगों के लिए सीपीईसी जैसी क्रांतिकारी परियोजनाओं की शुरुआत की थी। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की यह सोच थी कि इस प्रोजेक्ट के रूट की शुरुआत पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाके फाटा और बलूचिस्तान से हो। लेकिन यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि रूट को बदल दिया गया है और प्रोजेक्ट को लाहौर और सिंध से शुरू किया गया है। हम चाहते हैं कि सीपीईसी से बलूच लोगों को फायदा हो। लेकिन अक्षम, अयोग्य और कठपुतली सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने में विफल हो गई है।' बिलावल ने यह आरोप भी लगाया कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री इमरान खान ना सिर्फ मुल्क के संसाधनों की चोरी कर रहे हैं बल्कि अपनी अक्षमता का बोझ लोगों पर डाल रहे हैं।

पीपीपी के नेता ने कहा, बलूचों को फायदे से वंचित करने के लिए उठाया जा रहा कदम

क्या है सीपीईसी : अरबों डॉलर की लागत वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीन के शिनजियांग क्षेत्र से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक सड़क, रेल और ऊर्जा परियोजनाओं का नेटवर्क विकसित किया जाना है।

प्लेटलेट्स स्थिर होने तक शरीफ का अमेरिका जाना मुश्किल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का फाइल फोटो।

लंदन, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या जब तक स्थिर नहीं हो जाती, तब तक उनका अमेरिका जाना संभव नहीं होगा। उनके बेटे हसन नवाज ने रविवार को यहां मीडिया से यह बात कही। शरीफ इलाज के लिए 20 नवंबर से लंदन में अपने बेटे हसन के फ्लैट पर रह रहे हैं। शरीफ को ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। इसके चलते मरीज का प्लेटलेट्स काउंट खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। शरीफ के निजी चिकित्सक अदनान खान के अनुसार, पूर्व नेता की बीमारियों की हर पहलू से समीक्षा की जा रही है। साथ ही हेमेटोलॉजिस्ट की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

नाइजीरिया के नजदीकी समुद्र से 20 भारतीय फिर अगवा

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक व्यापारिक जहाज पर सवार 20 भारतीयों का अफ्रीका महाद्वीप में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया है। वाकया नाइजीरिया के नजदीक के समुद्री इलाके में रविवार को घटित हुआ। भारत सरकार ने मामले की जानकारी नाइजीरिया के अधिकारियों को देकर कार्रवाई की मांग की है। नाइजीरिया तट के नजदीक से ही दस दिन पहले हांगकांग के जहाज से 18 भारतीयों का अपहरण हुआ था। रविवार को हुई अपहरण की घटना की जानकारी शिपिंग कंपनी ने दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि एमटी ड्यूक नाम के जहाज से अगवा हुए 20 भारतीयों को लेकर हम चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया के नजदीक के समुद्र में इस साल यह तीसरी घटना हुई है। इन सभी में भारतीय अगवा हुए हैं। कुमार ने बताया- अबुजा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने घटना से नाइजीरिया के अधिकारियों को अवगत कराया है। वे पड़ोसी देशों के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। अगवा लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भारत सरकार नाइजीरिया और अन्य देशों के अधिकारियों के संपर्क में है।

न्यूज गैलरी

मुशर्रफ के देशद्रोह मामले में इमरान सरकार को नोटिस

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार को इमरान सरकार को नोटिस जारी किया। वर्ष 2007 में मुशर्रफ द्वारा संविधान निलंबित कर आपातकाल लगाने के मामले में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चल रहा है। याचिका में मुशर्रफ ने अपने खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को असंवैधानिक घोषित करने की गुजारिश की है। (प्रेट्र)

जंगलों की आग से सिडनीवासियों का बुरा हाल

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के जंगलों में लगी भयंकर आग से तटीय शहर सिडनी का बुरा हाल है। अस्पताल में सांस से जुड़ी परेशानियों को लेकर मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होने पर सोमवार को चिकित्सकों के समूह ने इसको लेकर सरकार को आगाह किया है। क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस संस्था ने कहा है कि सिडनी में सेहत को लेकर आपातकाल की स्थिति बन गई है। न्यू साउथ वेल्स में फेफड़े से जुड़ी समस्याओं को लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में पिछले दो सप्ताह में 48 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। (एएफपी)

अमेरिका में छात्रा की हत्या में 13 साल का किशोर गिरफ्तार

न्यूयॉर्क : अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के पॉश इलाके मैनहट्टन के एक पार्क में 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा की चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में 13 साल के किशोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, किशोर ने बीते बुधवार को दो अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देते वक्त छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। (रायटर)

खाद्य सुरक्षा पर चीन को मिली संयुक्त राष्ट्र से तारीफ

शर्म अल शेख : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने खाद्य सुरक्षा पर चीन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में चीन ने चमत्कार कर दिखाया है। मिस्र के तटीय शहर शर्म अल शेख में चल रहे वर्ल्ड यूथ फोरम में रविवार को डोंग्यू ने कहा, 'दुनिया की सात फीसद कृषि योग्य भूमि वाला चीन विश्व की 22 फीसद आबादी का पेट भर रहा है। खाद्य सुरक्षा हासिल करने में चीन की सफलता का राज बेहतरीन कृषि नीति, नई खोज और अच्छा प्रबंधन है। चीन ने कृषि क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से निवेश आकर्षित करने के लिए स्थायी नीति अपनाई है। जबकि विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए खुला बाजार भी बना रखा है।' एफएओ प्रमुख ने बताया कि चीन कृषि क्षेत्र के अनुभवों को अपने अफ्रीकी साझीदारों के साथ कई दशकों से साझा कर रहा है। वह कृषि विकास के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का भी इच्छुक है। (आइएएनएस)

महाभियोग से ट्रंप को राजनीतिक नफा-नुकसान के आसार नहीं

अनुमान ▶ रिपब्लिकन सोच रहे, ट्रंप को मिल सकता है क्लिंटन जैसा लाभ

वाशिंगटन, रायटर : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव से किसी को खास नफा-नुकसान होता नहीं लग रहा। इससे न तो ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के मतदाता कम हो रहे और न ही ट्रंप को बिल क्लिंटन जैसी सहानुभूति मिलने जा रही। क्लिंटन को 1998 में मोनिका लेविंस्की मामले में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। सीनेट में प्रस्ताव गिरने के बाद उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़कर जीता था।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा में राय जानने को इसी सप्ताह आने वाले प्रस्ताव से पहले रायटर और इपसॉस के सर्वे में यह बात उभरकर आई है। सर्वे में साफ हो गया है कि ट्रंप के खिलाफ इस मुहिम से विपक्ष को खास राजनीतिक लाभ नहीं होने जा रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को शुरू से 2020 के चुनाव से जोड़कर चल रही है। उसके अनुसार उसके संभावित उम्मीदवार जो बिडेन का रास्ता रोकने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की पर बिडेन की भूमिका की जांच का दबाव डाला। बिडेन 2015 में अमेरिका के उप राष्ट्रपति थे, उस समय यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सैन्य सहायता में गड़बड़ी

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

के लिए उन पर अंगुली उठी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसी आरोप को लेकर वह अपने बहुमत वाले संसद के सदन प्रतिनिधि सभा में इसी सप्ताह महाभियोग प्रस्ताव पर आगे बढ़ने वाली है। हालांकि ट्रंप ने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया है। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए देश में मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सफल नहीं होगा। ट्रंप के प्रचार प्रबंधक ब्रैड पार्कल ने कहा है कि रिपब्लिकन इस महाभियोग का असर 1998 में क्लिंटन के चुनाव जैसा होता देख रहे हैं। आगामी चुनाव में ट्रंप को विपक्षी साजिश का जनसमर्थन के रूप में फायदा मिल सकता है। गैलप की पोलिंग में क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग पर मतदान के समय 73 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

अमेरिका के दो सैन्य अड्डे बंद कर सकता है तुर्की

अंकारा, आइएएनएस : तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने कहा है कि अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों को बंद किया जा सकता है। एर्दोगन ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा, तुर्की में अमेरिकी सेना के इनसिर्लिक और कुरेसिक सैन्य ठिकानों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें बंद करने से पहले तुर्की अपने सहयोगियों से चर्चा करेगा। अदाना स्थित इनसिर्लिक बेस अमेरिकी वायु सेना का प्रमुख अड्डा है, जबकि कुरेसिक रडार प्रणाली से लैस नाटो सेना का अहम ठिकाना है। तुर्की ने इन सैन्य ठिकानों को बंद करने की बात अमेरिकी संसद द्वारा हाल में पारित एक प्रस्ताव के बाद की है। बीते सप्ताह अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने 1915 से 1923 तक तुर्की में ओटोमन साम्राज्य के दौरान अमेरिकियों के नरसंहार पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है।

बोइंग रोक सकती है 737 मैक्स विमानों का उत्पादन

वाशिंगटन, एएफपी : अपने 737 मैक्स विमानों के कारण निशाने पर आई अमेरिकी कंपनी बोइंग इन विमानों का उत्पादन बंद कर सकती है। दो हादसों के बाद से दुनियाभर में इन विमानों की उड़ानें ठप हैं। पहला मैक्स विमान हादसा गत वर्ष 29 अक्टूबर को इंडोनेशिया में हुआ था, जबकि दूसरा विमान गत दस मार्च को इथोपिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इन दोनों हादसों में 346 लोगों की जान गई थी।

वाल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ अधिकारियों के हवाले से रविवार को बताया कि इस अमेरिकी विमानन कंपनी का प्रबंधन विकल्प के तौर पर उत्पादन रोकने पर विचार कर रहा है। दो विमान हादसों के बाद मैक्स विमानों के उत्पादन में पहले ही कटौती कर दी गई थी। हर माह 52 विमानों की जगह 42 विमानों के उत्पादन का निर्णय लिया गया था। 737 मैक्स विमान मामले को लेकर गत गुरुवार को बोइंग के प्रमुख डेनिस मुलेनबर्ग ने अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के प्रमुख स्टीव डिक्सन से मुलाकात की थी। बोइंग कई बार यह उम्मीद जता चुकी है कि उसके विमानों को 2020 से पहले तक उड़ान की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मैक्स विमानों की पिछले नौ माह से कोई उड़ान नहीं हो पाई है। बोइंग के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम मैक्स विमानों की वापसी को लेकर एफएए और वैश्विक नियामकों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। हम विमानों की वापसी के हालात और समय के मद्देनजर उत्पादन का आकलन करते रहेंगे।'

कोई नहीं कह सकता कि पाक एफएटीएफ की बात मान रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। इस कार्य के लिए उस पर दबाव बढ़ाए जाने की जरूरत है। यह बात सोमवार को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लिनैन ने कही।

पेरिस मुख्यालय वाले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकियों को आर्थिक संसाधन मुहैया कराने के कारण ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी दी है। फरवरी 2020 में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला हो सकता है। तब तक उसने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर कार्य करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एफएटीएफ आतंकी संगठनों और अपराधी गिरोहों को धन मुहैया कराने वाले देशों पर नजर रखती है और उनकी भूमिका निर्धारित करती है। लिनैन ने कहा, फरवरी तक हमें देखना होगा कि पाकिस्तान ने कितना काम किया।

नागरिकता संशोधन कानून पर पूछे गए सवाल के जवाब में फ्रांसीसी राजदूत ने कहा, भारत लोकतांत्रिक देश है। कई बार किसी मसले पर विचारों का टकराव होता है। ऐसे में लोग अपनी बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर सही फैसला हो जाएगा।

पाकिस्तान पर फ्रांसीसी राजदूत की तल्ख टिप्पणी

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है

पाकिस्तान का झंडा। फाइल

लिनैन ने कहा, वह नहीं सोचते कि किसी भी देश का भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करना उचित होगा। हम धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं और हमारे लिए किसी मसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में जाने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किए जाने के मामले में लिनैन ने कहा, यह सामान्य स्तर की एडवाइजरी है जो वहां चल रहे आंदोलनों को देखते हुए जारी की गई है।

ब्रिटिश मॉडल के घर से 470 करोड़ के जेवरात चोरी

लंदन, रायटर : ब्रिटिश मॉडल और सेलेब्रिटी तमारा एक्लेस्टोन के वेस्ट लंदन स्थित घर से पांच करोड़ पौंड (करीब 470 करोड़ रुपये) कीमत के जेवरात चोरी हो गए। तमारा फॉर्मूला वन समूह के पूर्व मुख्य कार्यकारी बर्नी एक्लेस्टोन की बेटी हैं। चोरी से कुछ देर पहले ही तमारा क्रिसमस की छुट्टियां मनाने देश से बाहर गई थीं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, 25 वर्षीय तमारा का घर लंदन के पॉश इलाके हाइड पार्क में है। शुक्रवार रात तीन बदमाश सिक्योरिटी गार्डों को धता बताकर बगीचे के रास्ते घर में घुसे और बेडरूम में छिपाकर रखी गई तिजोरियों से कीमती जवाहरात चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान में कीमती अंगूठियां, बालियां और शादी के तोहफे में मिली 75 लाख रुपये से अधिक कीमत की चूड़ियां शामिल हैं।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बदमाशों ने इस पूरे काम को 50 मिनट के अंदर अंजाम दिया और खिड़की के रास्ते भागने में सफल रहे। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में गार्ड बैठा रहा और उसे कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं तमारा का 57 कमरों का बंगला लंदन के जिस इलाके में है वहां पुलिस 24 घंटे गश्त करती है और कई जगह बेरिकेडिंग भी की गई है। इसके बावजूद बदमाशों ने चोरी को अंजाम दे दिया।

फॉर्मूला वन समूह के पूर्व प्रमुख बर्नी एक्लेस्टोन की बेटी हैं तमारा

बदमाशों ने इस पूरे काम को 50 मिनट के अंदर अंजाम दिया

घटना के बाद से तमारा और उनका परिवार भयभीत

एक्लेस्टोन परिवार के प्रवक्ता ने चोरी की पुष्टि करते हुए कहा कि घर पर तैनात सिक्योरिटी एजेंसी इस मामले में पुलिस का सहयोग कर रही है। तमारा और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से वे बुरी तरह डर गए हैं।

फ्रांस में हड़ताल का मेट्रो पर असर...

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के पेंशन सुधारों के विरोध में शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। राजधानी पेरिस में सोमवार को 16 मेट्रो लाइनों में से दो का ही परिचालन शुरू हुआ है। अंडरग्राउंड चेटलेट मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में यात्री। 17 दिसंबर को शुरू हुई इस हड़ताल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आरएटीपी और फ्रांसीसी राज्य रेलवे कंपनी एसएनसीएफ के कर्मचारी भी शामिल हैं। करीब 80 प्रतिशत चालक हड़ताल पर हैं, इससे रेल सेवाएं लगभग ठप हो गई है। एएफपी

अमेरिका ने उत्तर कोरिया से की बातचीत की पेशकश

सियोल, आइएएनएस : दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बीगन ने कहा है कि अमेरिका, उत्तर कोरिया से बातचीत के लिए तैयार है। सोमवार को यहां अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष ली हून के साथ बैठक के बाद उन्होंने इसका एलान किया। वह तीन दिनों के अधिकारिक दौरे पर दक्षिण कोरिया में हैं। हाल में उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षणों से क्षेत्र में जारी तनाव के बीच बीगन ने कहा, उत्तर कोरिया को बातचीत के जरिये अपने मुद्दे सामने रखने चाहिए। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को खत्म करने में अमेरिकी मदद की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

परमाणु निरस्त्रीकरण के दबाव का सामना कर रहे उत्तर कोरिया ने हाल में अपने मिसाइल परीक्षणों को तेज कर दिया है। अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों में छूट पाने के लिए उत्तर कोरिया ने यह धमकी भी दी है कि ऐसा नहीं होने पर वह अगले साल से खतरनाक रास्ता अपना सकता है। अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया की वार्ता के लिए किसी तय समय सीमा के सवाल पर बीगन ने कहा कि अमेरिका ऐसी किसी समय सीमा से नहीं बंधा है।

ब्रिटेन में भारतवंशी रेडियोग्राफर ने किडनी देकर बच्ची को दी जिंदगी

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक महिला रेडियोग्राफर ने अपनी एक किडनी देकर दो साल की बच्ची की जान बचाई है। इसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है। वह सोशल मीडिया पर बच्ची को किडनी दान करने की अपील देखकर मदद के लिए आगे आई थीं।

लीड्स टीचिंग अस्पताल में बतौर रेडियोग्राफर काम करने वालीं सुरिंदर सपाल ने सोशल मीडिया पर अनाया कंदोल के परिवार की अपील के बाद किडनी दान करने का निर्णय लिया। 36 वर्षीय सपाल ने कहा, 'मैं यह जानकर खुश हूं कि मैंने एक बच्ची की सेहत दुरुस्त करने में मदद की। अब वह सामान्य रूप से बचपन गुजार सकती है। मैं खुद भी एक मां हूं। इसलिए मैं ज्यादा खुश हूं कि मैंने एक दूसरी मां की बच्ची की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की।' जबकि अनाया के पिता अमरीक कंदोल ने कहा, 'सुपरहीरो वास्तव में भले नहीं होते, लेकिन हमारे पास सच में एक सुपरहीरो है। अगर वह यह प्रत्यारोपण नहीं करतीं तो मुझे नहीं लगता कि अनाया इस दुनिया में रह पाती।'

सोशल मीडिया पर किडनी दान की अपील देखकर मदद को बढ़ाया कदम

बच्ची के परिजनों ने गदगद होकर सुरिंदर पाल को बताया सुपरहीरो

इस कारण पड़ी जरूरत

भारतीय पृष्ठभूमि वाली अनाया का कई समस्याओं के साथ समय पूर्व जन्म हुआ था। असामान्य लिवर के साथ उसकी दोनों किडनी भी सामान्य से ज्यादा बड़ी थीं। उसके फेफड़े भी विकसित नहीं थे और हृदय की भी समस्या थी। जन्म के समय अनाया का वजन महज डेढ़ किलो था। अनाया को जीवित रखने के लिए रोजाना 10-12 घंटे डायलिसिस पर रखा जाता था।

जॉनसन ने शुरू किया कामकाज, ब्रेक्जिट है सबसे बड़ा लक्ष्य

लंदन, एएफपी : चुनाव में मिली भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार से कामकाज में जुट गए। सबसे पहले उन्हें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना है, सरकार की भविष्य की योजनाओं को सार्वजनिक करना है और उसके बाद ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव) की प्रक्रिया को पूरा करना है।

ब्रिटेन में नई सरकार के लिए जल्द होने वाले मंत्रिमंडल गठन में प्रमुख विभागों के मंत्रियों की पुरानी स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। इनमें गृह मंत्री पद पर भारतीय मूल की प्रीति पटेल की नियुक्ति प्रमुख है। इससे पहले वह कंजरवेटिव पार्टी के 109 नव निर्वाचित सांसदों का हाउस ऑफ कॉमंस में स्वागत करेंगे। जॉनसन का सबसे बड़ा लक्ष्य 31 जनवरी, 2020 तक यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलगाव है।

इसी मुद्दे पर वह पहली बार सत्ता में आए थे और इसी नारे पर वह हालिया चुनाव जीते हैं। मतदाताओं ने उन्हें मर्जी के अनुसार कार्य करने वाला बहुमत दिया है। इसलिए अब उनके ऊपर जनता की आकांक्षा पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है।

ब्रेक्जिट की शर्तों पर यूरोपीय यूनियन के साथ उनका समझौता हो गया है। अब इन शर्तों को लागू करते हुए अलगाव को अंजाम देना है। इसके लिए उन्हें स्कॉटलैंड को भी संतुष्ट करना है। कारोबार के सवाल पर जॉनसन की सोच यूरोपीय यूनियन के साथ कनाडा की तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की है। लेकिन इसको लेकर यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों के मन में आशंकाएं हैं।

बोरिस जॉनसन। रायटर

प्रीति पटेल के पास गृह मंत्रालय बने रहने की संभावना

ब्रिटिश राजनीति में रूसी दखल

प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटिश राजनीति में रूसी दखल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट तैयार है। इसे उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। 50 पेज की यह रिपोर्ट ब्रिटिश राजनीति में रूसी दखल के बारे में जानकारियां दी गई हैं। शक जताया गया है कि 2016 में ब्रेक्जिट के लिए हुए जनमत संग्रह में भी रूस ने सक्रिय भूमिका निभाई।

उत्तरी आयरलैंड की पार्टियों ने किया सत्ता के लिए मंथन

बेलफास्ट, एएफपी : उत्तरी आयरलैंड की पार्टियों ने तीन साल बाद क्षेत्रीय सरकार की संभावनाओं को पुनर्जीवित करने की उम्मीद से सोमवार को मुलाकात की। बता दें कि जनवरी 2017 से वहां कोई सरकार नहीं है और इसी के चलते वहां राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल है। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन के आम चुनावों में कंजरवेटिव पार्टी की जीत के बाद यूरोपीय यूनियन से उसका अलग होना मात्र औपचारिकता रह गया है।

दरअसल, आर्थिक घोटाला सामने आने के बाद ब्रिटिश समर्थक कंजरवेटिव डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) और वामपंथी आयरिश रिपब्लिकन सिन फेइन के बीच गठबंधन टूट गया था, लेकिन आम चुनावों के बाद पार्टी अब फिर से एक होने की कोशिश करने लगी हैं। ब्रेक्जिट उत्तरी आयरलैंड व यूरोपीय संघ के आयरिश गणराज्य से सटी सीमा के लिए विवाद का विषय रहा है।

लंदन और ब्रसेल्स के बीच ब्रेक्जिट समझौते पर सहमति बनी थी जिसमें उत्तरी आयरलैंड को मुख्य भूमि ब्रिटेन से अलग करने सहित उस पर यूरोपीय संघ के कुछ नियम लागू रहेंगे। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उत्तरी आयरलैंड की विधानसभा इसका अनुमोदन करती है।

ये भी जानिए

2013 से 2018 तक भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर रोहित ने बनाया था। इस वर्ष रोहित ऐसा नहीं कर पाए। अभी तक धवन (143) के नाम यह स्कोर है।

आलोचना की परवाह नहीं करता, सीख रहा हूं : पंत

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा मेरा ध्यान खेल पर है वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रिषभ ने खेली थी अर्धशतकीय पारी

चेन्नई, प्रेट्र: अक्सर अपना विकेट गैर जिम्मेदाराना तरीके से गंवा देने के आरोप झेलने वाले भारत के उदीयमान बल्लेबाज रिषभ पंत ने कहा कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्वाभाविक खेल दिखाने जैसा कुछ नहीं है और हालात के अनुरूप खेलना अहम होता है।

बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में खराब फॉर्म से जूझ रहे पंत लगातार आलोचकों का कोपभाजन बने हुए थे। उन्होंने हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक जमाकर खराब फॉर्म को अलविदा कहा। उन्होंने कहा, 'मैं इतना समझ गया हूं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्वाभाविक खेल जैसा कुछ नहीं है। इसमें टीम की जरूरत या हालात के अनुरूप खेलना होता है। मैं सीख रहा हूं। टीम की जीत के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं, उस पर ध्यान करूंगा। आखिर में मैंने रन बनाए।'

उन्होंने कहा कि वह आलोचना की परवाह किए बिना अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं। पहले वनडे में 71 रन बनाने वाले पंत ने कहा, 'मैं प्रक्रिया पर ध्यान करना चाहता हूं। कई बार आपके बारे में अच्छा कहा जाता है और कई बार नहीं। मैं पूरा ध्यान अपने खेल पर लगा रहा हूं।' लगातार आलोचना के बीच प्रेरणा के बारे में पूछने पर पंत ने कहा कि उन्होंने खुद पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा, 'खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। लोग आसपास चाहे जो बात करें। कई बार रन बनते हैं और कई बार नहीं, लेकिन प्रक्रिया अहम होती है।'

मौजूदा हालात में यह पारी कितनी अहम है, यह पूछने पर उन्होंने कहा, 'जब मैं भारत के लिए खेल रहा हूं तो हर पारी अहम है। मैं अपने प्रदर्शन में रोज सुधार देखना चाहता हूं।' अक्सर मैदानों पर पंत का स्वागत 'धौनी, धौनी' की गूंज के साथ होता है, लेकिन चेन्नई में यह देखने को नहीं मिला। पंत ने कहा, 'कई बार दर्शकों का समर्थन जरूरी होता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्रदर्शन में सुधार हो सके।'

हेटमायर बोले, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ पारी थी: वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में 139 रन की अपनी पारी को करियर की सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन कहा कि अंत तक नाबाद रहकर उन्हें और खुशी होती। हेटमायर 39वें ओवर में आउट हो गए थे। उन्होंने शाई होप (नाबाद 102) के साथ दूसरे विकेट के लिए 218 रन की साझेदारी की। उस समय वेस्टइंडीज को जीत के लिए 11.2 ओवर में 59 रन और चाहिए थे। हेटमायर ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह मेरा सर्वोच्च स्कोर है, लिहाजा यह सर्वश्रेष्ठ पारी है। लक्ष्य का पीछा करना हमेशा अच्छा होता है। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत तक ले जाने का अनुभव अलग ही है। काश मैं अंत तक टिककर खेल सकता, लेकिन मैं सीख रहा हूं। हम एक-दूसरे के साथ काफी समय से खेल रहे हैं और हमें एक-दूसरे के खेल की जानकारी है। मैं आक्रामक खेलता हूं और वह एक छोर संभालकर खेलता है।' आइपीएल की नीलामी 19 दिसंबर को है और उससे ठीक पहले हेटमायर ने यह पारी खेली है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान लीग पर नहीं है। यह पूछने पर कि क्या वह आइपीएल नीलामी से पहले कुछ साबित करना चाहते थे, उन्होंने कहा, 'मैं अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं। क्रिकेट में कई बार आपसे रन बनते हैं तो कई बार नहीं। इस साल मैं आइपीएल में अच्छा नहीं खेल सका, लेकिन अनुभव अच्छा रहा। इससे मुझे मजबूती में वापसी करने में मदद मिलेगी।'

लारा ने कहा, क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं कोहली: वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का मानना है कि विराट कोहली खेल के प्रति अपने समर्पण के मामले में सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह हैं, जबकि केएल राहुल भी प्रतिभा के मामले में भारतीय कप्तान के समकक्ष ही हैं।

लारा ने कहा कि बल्लेबाजी को अविश्वसनीय स्तर तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने के कोहली के फन के वह मुरीद हैं। उन्होंने कहा, 'यह विराट की तैयारी के अलावा क्रिकेट के प्रति उसके असाधारण समर्पण की भी बात है। मुझे नहीं लगता कि वह केएल राहुल या रोहित शर्मा से ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन खुद को तैयार करने के लिए उसका समर्पण उसे अलग बनाता है। वह क्रिकेट का क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उसकी फिटनेस का स्तर अविश्वसनीय है। उसे किसी भी दौर की टीम से बाहर नहीं रखा जा सकता। खेल के सभी प्रारूपों में जिसका औसत 50 हो, वह तो अविश्वसनीय ही होगा।' वेस्टइंडीज क्रिकेट की मौजूदा दशा और अधिकांश खिलाड़ियों के टी-20 लीगों में खेलने के बारे में उन्होंने कहा, 'हर क्रिकेटर की अपनी पसंद होती है। हर कोई तो वेस्टइंडीज टीम में नहीं होगा तो अगर टी-20 लीग खेलकर पैसा कमाने का मौका मिलता है तो क्यो नहीं। भारतीय टीम को देखिए। उसके पास आकर्षक टी-20 लीग (आइपीएल) है।

विंडीज पर पहले मैच में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना

चेन्नई, प्रेट्र: वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए मैच शुल्क का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। आइसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने निर्धारित समय के दौरान चार ओवर कम करने के कारण कीरोन पोलार्ड की टीम पर यह जुर्माना लगाया। आइसीसी ने कहा, 'आइसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार टीम के निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने की स्थिति में खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से उनके मैच शुल्क का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से उसके प्रत्येक खिलाड़ी पर मैच शुल्क का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। यह अनुच्छेद धीमी ओवर गति से जुड़ा है।' वेस्टइंडीज के कप्तान पोलार्ड ने मैच समाप्त होने के बाद अपनी गलती और प्रस्तावित जुर्माना स्वीकार कर लिया था और इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं होगी।

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत ● **फाइल फोटो, एएनआई**

टेस्ट रैंकिंग में विराट शीर्ष पर कायम, बुमराह खिसके

क्रिकेट

- **कोहली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं**
- **भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत पांचवें से छठे स्थान पर आ गए**

दुबई, प्रेट्र: भारतीय कप्तान विराट कोहली सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गए। कोहली (928) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं। स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए डे-नाइट टेस्ट में 43 और 16 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 296 रन से अपने नाम किया था।

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (791) और अजिंक्य रहाणे (759) क्रमशः चौथे और छठे स्थान पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने का रैंकिंग में ऊपर चढ़ना जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 143 और 50 रन की शानदार पारियां खेलने वाले लाबुशाने तीन स्थान के सुधार के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गए। लाबुशाने हालांकि पाकिस्तान के जहीर अब्बास और मुदस्सर नजर के उस रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गए थे, जिसमें उन्होंने लगातार तीन पारियों में 150 से ज्यादा का स्कोर किया था। ताजा जारी इस रैंकिंग में उन्होंने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया और स्मिथ के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।

श्रीलंका के साथ पहले घरेलू टेस्ट में नाबाद 102 रन की पारी खेलने वाले बाबर आजम पहली बार शीर्ष-10 में पहुंचे हैं। टी-20 रैंकिंग में शीर्ष और वनडे में दूसरे स्थान पर काबिज यह बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में 13वें से नौवें स्थान पर पहुंच गया। अपने पहले वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज आबिद अली ने टेस्ट रैंकिंग में 78वें स्थान से अपना सफर शुरू किया। वह करियर के पहले वनडे और पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले इकलौते पुरुष क्रिकेटर हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे बुमराह छठे पायदान पर खिसक गए। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सात विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के नील वैगनर करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 834 अंक के साथ एक बार फिर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। मैच में नौ विकेट लेने वाले टिम साउथी भी शीर्ष-10 में जगह बनाने में सफल रहे।

इस मैच में नौ विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क करियर के सर्वश्रेष्ठ 806 रेटिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ पांचवें स्थान पर पहुंच गए, जबकि जोश हेजलवुड भी आठवें से सातवें पायदान पर आ गए। ऑलराउंडर खिलाड़ियों की रैंकिंग में रवींद्र जडेजा वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर के बाद दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारतीय टीम आइसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 360 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (216), श्रीलंका (80), न्यूजीलैंड (60) और इंग्लैंड (56) की टीमें हैं।

नहीं बदलेगा आइपीएल नीलामी का कार्यक्रम

नई दिल्ली, प्रेट्र: विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) की खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार को कोलकाता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन कोलकाता इससे अधिक प्रभावित नहीं है। पता चला है कि दिल्ली कैपिटल्स की प्रबंधन टीम नीलामी में फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधित्व के लिए मंगलवार को कोलकाता पहुंच रही है, जिससे कि अंतिम तैयारी शुरू की जा सके।

बीसीसीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम तक की स्थिति के अनुसार आइपीएल नीलामी होगी। फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधि मंगलवार शाम और बुधवार सुबह तक आना शुरू कर देंगे। कोलकाता में 19 दिसंबर को 332 क्रिकेटर नीलामी में हिस्सा लेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने सर्वाधिक दो करोड़ रुपये का आधार मूल्य चुना है। इस साल की नीलामी छोटी है जिसमें आठ टीमों में केवल 73 स्थान भरे जाने हैं और इनमें से केवल 29 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं।

इस सत्र की समाप्ति के बाद करूंगा भविष्य पर फैसला : जाफर

रणजी ट्रॉफी के 86वें सत्र का आगाज नौ दिसंबर को हो चुका है और इस सत्र के पहले ही मैच के साथ वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मूल रूप से मुंबई के रहने वाले और लंबे समय तक मुंबई के लिए ही खेलने वाले जाफर फिलहाल कुछ वर्षों से विदर्भ के लिए खेल रहे हैं। लगातार पिछले दो सत्रों से विदर्भ की टीम रणजी चैंपियन बनी है। इस सत्र में जाफर विदर्भ की खिताबी हैट्रिक पूरी करना चाहते हैं। साथ ही वह रणजी में 200 कैच पकड़ने वाले पहले खिलाड़ी बनने और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20000 रन पूरे करने की दहलीज पर भी हैं। रणजी सत्र और कई अन्य मुद्दों पर **उमेश राजपूत** ने **वसीम जाफर** से खास बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

साक्षात्कार

- **आप 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने, लेकिन पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं?**

-ऊपर वाले का मुझ पर बहुत बड़ा करम है। मैं इतने साल से लगातार खेल रहा हूं, इसलिए 150 रणजी मैच खेल पाया। इसमें विदर्भ की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई के बाद में विदर्भ से जुड़ा और जिस तरह से विदर्भ की टीम जीतने लगी तो उससे मुझे और खेलने की प्रेरणा मिली। जहां तक सत्र के पहले ही मैच में पहली गेंद पर आउट होने की बात है तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अभी काफी मैच हैं और उम्मीद है मैं आगे अच्छा करूंगा।

- **कई रिकॉर्ड आपके निशाने पर हैं। इस बार रणजी ट्रॉफी में क्या लक्ष्य लेकर उतरे हैं?**

-हर बल्लेबाज चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और मेरी भी वही कोशिश होगी। हमने पिछले दो साल खिताब जीते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे रन और कैच विदर्भ के रणजी खिताब की हैट्रिक पूरी करने में काम आएं।

- **आप रणजी फाइनल के लकी चार्म माने जाते हैं। ऐसे में टीम को आपसे क्या उम्मीदें हैं?**

-टीम तो मुझसे हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत भाग्य का साथ होना भी जरूरी होता है। यह हमारी टीम के लिए हैट्रिक साल है, इसलिए टीम के एक सदस्य के तौर पर मैं चाहूंगा कि हमारी टीम को भाग्य का साथ भी मिले।

- **आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। आप बांग्लादेश की हाई परफॉर्मेंस अकादमी और किंग्स इलेवन पंजाब के कोचिंग स्टाफ से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में कब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर को जारी रखने की योजना है?**

-फिलहाल तो मैं इस साल खेलूंगा ही। मैं बांग्लादेश की अकादमी के लिए काम कर रहा हूं। इसके अलावा मुझे किंग्स इलेवन पंजाब का प्रस्ताव मिला है, जो मेरे लिए काफी रोमांचक है। मैं धीरे-धीरे कोचिंग के क्षेत्र में भी आ रहा हूं। इस आइपीएल में मुझे काम करने को मिलेगा, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए यह सत्र खत्म होने के बाद ही मैं अपने खेलने को लेकर और कोचिंग या कमेंट्री करने को लेकर फैसला करूंगा।

- **19 दिसंबर को आइपीएल की नीलामी है। आपकी टीम किंग्स इलेवन पंजाब किसी खास खिलाड़ी को नीलामी में लक्ष्य बनाकर चल रही है?**

-मेरी अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे मुख्य कोच अनिल कुंबले ने जरूर इसके लिए कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी। मुझे उम्मीद है कि कुंबले के मार्गदर्शन में किंग्स इलेवन पंजाब इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी।

- **आप मानते हैं कि शानदार घरेलू रिकॉर्ड के बावजूद आपको भारत के लिए खेलने के मौके कम मिले?**

-ऐसा नहीं है कि मुझे मौके मिले ही नहीं, मुझे मौके मिले, लेकिन मैं लगातार रन नहीं बना सका, खासकर ऑस्ट्रेलिया (2007-08) दौरे पर। मुझे 31 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जो कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसी बात से खुश हूं कि मैं मामूली पृष्ठभूमि से आया और भारत के लिए खेला।

- **आप टेस्ट ओपनर रहे हैं, क्या लगता है, रोहित व मयंक के रूप में भारत को विश्वसनीय ओपनिंग जोड़ी मिल गई है?**

-हर खिलाड़ी के लिए उसकी हर सीरीज एक परीक्षा होती है। आपको हर समय अपने आपको साबित करते रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि रोहित और मयंक के लिए भी जो अगली सीरीज होगी न्यूजीलैंड में या उसके बाद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में कोई और सीरीज, वो भी एक परीक्षा है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत में रन बनाना बहुत आसान है लेकिन, ये दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हें अच्छी शुरुआत मिली है। एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल या केएल राहुल के रूप में जो भारत की बेंच स्ट्रेंथ है, वे लगातार दबाव बनाए रखते हैं। ऐसा ही हमारे तेज गेंदबाजों के साथ है और ये टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत हैं।

- **अगले साल दक्षिण अफ्रीका में अंडर-19 विश्व कप है। ऐसे में प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम में किन-किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?**

-ईमानदारी से कहूं तो मैं इस टीम के बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन प्रियम गर्ग के खिलाफ मैं खेला हूं, थोड़ा बहुत यशस्वी जायसवाल के बारे में जानता हूं, क्योंकि वह मुंबई के लिए खेलते हैं। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनके अलावा मुंबई के ही अथर्व अंकोलेकर हैं, उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी खिलाड़ी चुने गए हैं वे बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमने पिछला विश्व कप जीता था और मुझे विश्वास है कि यह टीम उस खिताब का बचाव जरूर करेगी।

339 स्पर्धा में 1017 पदक होंगे दांव पर

टोक्यो ओलंपिक

- **टोक्यो 2020 ओलंपिक के पदकों की संख्या सामने आई**
- **सबसे ज्यादा 49 स्वर्ण पदक तैराकी में जीत सकेंगे खिलाड़ी**

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो में होने वाले 2020 ओलंपिक में अब सात महीने का समय रह गया है। सोमवार को ओलंपिक में दिए जाने वाले 1017 पदकों की संख्या सामने आई। इन पदकों में 339 स्वर्ण, 339 रजत और इतने ही कांस्य पदक शामिल हैं, जबकि इस बार ओलंपिक में 339 स्पर्धा में मुकाबले खेले जाएंगे। स्पर्धा में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का मौका तैराकी में होगा, जहां सबसे ज्यादा 49 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। इसके बाद 48 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में मौजूद होंगे। कुल मिलाकर 33 खेल इस बार ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। टोक्यो में रविवार को ही 2020 ओलंपिक के लिए 60 हजार सीट वाला ओलंपिक स्टेडियम लांच हुआ। इस स्टेडियम में उमस को मात देने की तकनीक है।

खेल संघों के अध्यक्षों, महासचिवों से मिलेंगे बत्रा: भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के अध्यक्षों और महासचिवों से मिलेंगे। बत्रा ने सभी एनएसएफ को पत्र लिख कर कहा है कि वह सभी महासंघों से एक-एक करके मिलेंगे, जिसका मकसद टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारियों का जायजा लेना है। बत्रा ने एक नोटिस में कहा कि सरकार ने 2020 और 2024 के तैयारियों के लिए खिलाड़ियों का पूरा समर्थन किया है। अब सभी एनएसएफ की जिम्मेदारी है कि वह चीजों का देखें।

रिजिजू ने माना, देश में खेल संस्कृति नहीं

नई दिल्ली, आइएएनएस: खेल मंत्री किरण रिजिजू ने माना है कि देश में खेल संस्कृति का आभाव है और इसे बनाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। रिजिजू ने कहा कि भारत युवाओं का देश है जहां कई सारे खिलाड़ी हैं लेकिन फिर भी हम पदक के लिए तरसते हैं। रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में खेल की संस्कृति नहीं है। पदक आता है तो जश्न मनाया जाता है। नहीं तो खिलाड़ियों को कोई पहचानता भी नहीं है। खिलाड़ी एक साल में पैदा नहीं होता। आज हमने जो तैयारी की है उसका परिणाम कई साल बाद आएगा।

विश्व कप से पहले पृथ्वी शॉ से सलाह ली : प्रियम

रवानगी

- **द. अफ्रीका रवाना होने से पहले बोले भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान**
- **कहा, टीम और उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं**

बेंगलुरु, प्रेट्र: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान प्रियम गर्ग ने कहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से नौ फरवरी तक होने वाले अंडर-19 विश्व कप में टीम के खिताब की रक्षा के अभियान की अपनी योजना बनाने और टीम को एकजुट करने पर पूर्व कप्तान पृथ्वी शॉ से सलाह ली। अंडर-19 विश्व कप से पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में मेजबान टीम के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगी और इसके बाद चतुष्कोणीय सीरीज में हिस्सा लेगी, जिसमें जिंबाब्वे और न्यूजीलैंड की अंडर-19 टीमें भी खेलेंगी।

भारत की अंडर-19 टीम के दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले गर्ग ने कहा कि मैंने अब तक विराट कोहली सर से बात नहीं की है, मैंने पृथ्वी से काफी बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रणनीति, आपकी प्रक्रिया और आपकी टीम की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टीम जितनी अधिक एकजुटता की भावना को महसूस करेगी, उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेगी। पृथ्वी ने साथ ही कहा कि टीम को पता होना चाहिए कि उसका मजबूत पक्ष क्या है। उन्होंने बताया कि 2018 में भारत की सफलता में टीम की एकजुटता ने अहम भूमिका निभाई। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है और अब तक चार खिताब जीत चुकी है। पिछले टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया था और टूर्नामेंट में अजेय रही थी। हालांकि गर्ग ने जोर देते हुए कहा कि टीम पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसे सिर्फ इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करने के मौके के तौर पर देख रहा हूं। हमने इतनी सारी प्रतियोगिताओं में खेले हैं इसलिए यह हमारे लिए फायदे की स्थिति है। एक कप्तान के रूप में मैं सोच रहा हूं कि अपनी टीम को आगे कैसे ले जाऊं। मुश्किल हालात के टीम को कैसे संभालूं।

कोच ने कहा, अभ्यास मैचों से फायदा मिलेगा: भारत की अंडर-19 टीम के मुख्य कोच पारस महाम्ब्रे ने कहा कि टीम संतुलित है और टूर्नामेंट से पहले अभ्यास मैचों में कुछ संयोजनों को लेकर प्रयोग करने का मौका मिलेगा।

रेफरी ने खिलाड़ी को कहा बंदर : कोच

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई सिटी एफसी के मुख्य मैनेजर जॉर्ज कोस्टा ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु एफसी के खिलाफ उनकी टीम के इंडियन सुपर लीग मैच के दौरान रेफरी ने उनके एक खिलाड़ी को बंदर कहा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) इस आरोप की जांच करेगा। रविवार को कांतीर्वा स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ टीम की 3-2 की जीत के बाद कोस्टा ने कहा कि साऊदी अरब के रेफरी तुर्की अलखुदायर ने सर्ज केविन को बंदर कहा और कुछ इशारे किए, जो अपमानजनक थे। कोस्टा ने कहा, 'मैं सम्मान की बात कर रहा हूं जो उसने (मैच अधिकारी) एक खिलाड़ी- सर्ज केविन के साथ मैच के दौरान नहीं दिखाया। इस रेफरी ने कुछ इशारे किए, उसे बंदर कहा और इस तरह की चीजें हुई कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता।' लीग के आयोजक एफएसडीएल के प्रवक्ता ने कहा है कि एआइएफएफ से इस आरोप की जांच करने का आग्रह किया गया है।

फुटबॉल यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 मुकाबलों के ड्रॉ हुए घोषित, रीयल मैड्रिड की राह हो सकती है मुश्किल, मैनचेस्टर सिटी से होगा सामना

अंतिम-16 के मैच में लिवरपूल का सामना एटलेटिको मैड्रिड से

नियोन, एएफपी: गत विजेता मैनेजर जुर्जेन क्लोप की टीम लिवरपूल का सामना यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम-16 के मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड से होगा। सोमवार को चैंपियंस लीग के अंतिम-16 मुकाबलों का ड्रॉ घोषित हुआ।

दो चरणों में होने वाले मुकाबलों में क्लोप की टीम पहले एटलेटिको के वांडा मैट्रोपोलिटेना में मुकाबला खेलेगी, जहां उसने इस साल जून में यह ट्रॉफी उठाई थी। फिर इसके बाद दोनों टीमें एंफील्ड में आमने-सामने होंगी। हालांकि, इस ड्रॉ में स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसका सामना इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन मैनचेस्टर सिटी से होगा। विश्व के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार की टीम पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) पिछले तीन सत्रों से अंतिम-16 से बाहर होती जा रही है और उसकी भिड़ंत बोरुसिया डोर्टमंड से होगी। इसके अलावा फ्रैंक लैंपार्ड की युवा टीम चेल्सी का सामना यूरोपियन मास्टर्स बायर्न म्यूनिख से होगा। मैनेजर जोस मौरिन्हो के मार्गदर्शन में खेल रही पिछले सत्र की उप विजेता टॉटनहम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आरबी लीप्जिग को हराना होगा। वहीं, दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम जुवेंटस को फ्रांस की ल्योन से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लियोन मेसी की बार्सिलोना को नापोली से, जबकि इटली की क्वालीफायर अटलांटा को वेलेंसिया से मुकाबला करना होगा। अंतिम-16 के पहले चरण के मैच 18, 19, 25, 26 फरवरी को खेले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के मैच 10, 11, 17, 18 मार्च में होंगे।

पीएसजी की जीत में एमबापे चमके: पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की लीग-1 के मैच में सैंट इटिएने पर 4-0 की जीत में उसके स्ट्राइकर कायलियन एमबापे चमके। एमबापे ने इस मैच में दो शानदार गोल किए। वह इस सत्र में नौ गोल कर चुके हैं। हालांकि, जोन इडियुस को रेड कार्ड मिलने के कारण सैंट इटिएने को 25वें मिनट से 10 खिलाड़ियों के साथ शेष मैच खेलना पड़ा। पीएसजी के लिए अन्य गोल नेमार और माउरो इकार्डी ने दागे। हालांकि मैच में नेमार 62वें मिनट पर पेनाल्टी पर गोल करने से चूक गए। इस जीत के बाद पीएसजी 17 मैचों में 42 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि सैंट इटिएने 11वें नंबर पर है। मैच के नौवें मिनट में विश्व के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार ने अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद पहला हाफ खत्म होने में सिर्फ दो मिनट बचे थे तब एमबापे ने पीएसजी का स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ के 72वें मिनट में इकार्डी ने बॉक्स के अंदर से गोल कर टीम की बढ़त को बढ़ा दिया। इकार्डी 14 मैचों में 13 गोल कर चुके हैं। इस बीच, मैच के 89वें मिनट में एमबापे ने अपना दूसरा और टीम के लिए चौथा गोल किया। एमबापे के दोनों गोल में नेमार ने उनकी मदद की।

जुवेंटस के साथ शीर्ष पर पहुंचा इंटर मिलान

फ्लोरेंस, रायटर: इंटर मिलान ने सीरी-ए लीग के मैच में फिओरेंटीना के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ खेलकर अंक तालिका में जुवेंटस के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गया। इंटर मिलान 16 मैचों में 39 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम जुवेंटस ने इतने ही मैचों में 39 अंक हासिल किए हैं। हालांकि, गोल अंतर के आधार पर इंटर मिलान शीर्ष पर है। रविवार को जुवेंटस उडीनेसे को शिकस्त देकर शीर्ष पर पहुंच गया था। मिलान के लिए गोल बोर्जा वालेरो ने आठवें मिनट में किया। वहीं, दूसरे हाफ में फिओरेंटीना के दुसान व्लाहोविक ने इंजुरी टाइम (90+2वें मिनट) में गोल कर अपनी टीम को हारने से बचा लिया। दूसरे हाफ में मिलान के अहम स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू के पास गोल करने का मौका था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। उनके शॉट को ड्रेगोवस्की ने खराब कर दिया।

चैंपियंस लीग के अंतिम-16 के मैच

बोरुसिया डोर्टमंड	VS	पीएसजी
रीयल मैड्रिड	VS	मैनचेस्टर सिटी
अटलांटा	VS	वेलेंसिया
एटलेटिको मैड्रिड	VS	लिवरपूल
चेल्सी	VS	बायर्न म्यूनिख
ल्योन	VS	जुवेंटस
टॉटनहम	VS	आरबी लीप्जिग
नापोली	VS	बार्सिलोना

स्टिमक से मतभेद नहीं : थापा

नई दिल्ली, आइएएनएस: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) की तकनीकी समिति के प्रमुख श्याम थापा का कहना है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वह भारतीय टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक के प्रदर्शन से नाखुश हैं। मेरे उनसे कोई मतभेद नहीं है। थापा के मुताबिक इस संबंध में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तकनीकी समिति की 29 नवंबर को एक बैठक हुई थी और उससे यह रिपोर्ट सामने आई थी कि समिति ने स्टिमक से बांग्लादेश और अफगास्तिान के साथ हुए विश्व कप क्वालीफायर मुकाबलों में टीम के प्रदर्शन पर बात की थी।

बेंजेमा ने रीयल मैड्रिड को हार से बचाया

वेलेंसिया, रॉयटर: करीम बेंजेमा ने इंजुरी टाइम में किए गए गोल की मदद से अपनी टीम रीयल मैड्रिड को स्पेनिश लीग ला लीगा के मैच में वेलेंसिया के खिलाफ हार से बचा लिया। दोनों टीमों के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस मैच के बाद रीयल मैड्रिड और बार्सिलोना के समान 35 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के कारण बार्सिलोना शीर्ष पर और उसके बाद मैड्रिड दूसरे नंबर पर विराजमान है। पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। दूसरे हाफ में वेलेंसिया के कार्लोस सोलेर ने 78वें मिनट में गोल करके मैड्रिड को चौंका दिया और टीम को उपयोगी बढ़त दिलाई। मैच के खत्म होने में बेजेंमा ने टीम का लाज बचाई, जिन्होंने चालाकी से गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। 90+5वें मिनट में टोनी क्रूस द्वारा मैड्रिड के खिलाड़ियों को कॉर्नर से गेंद मिली और बेंजेमा ने गोलकीपर बॉक्स के अंदर से अपने दायें पैर से गेंद को उसकी सही जगह भेजकर मैच ड्रॉ करा दिया।

इरफान पठान जामिया के छात्रों को लेकर चिंतित

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके इरफान पठान ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर चिंता जताई है। ये छात्र नागरिकता संशोधन अधिनियम (कैब) के खिलाफ रविवार शाम प्रदर्शन कर रहे थे। पठान ने ट्वीट किया कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मैं और हमारा देश जामिया के छात्रों के लिए चिंतित है।

खिलाड़ियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है।
– मेहुली घोष, भारतीय निशानेबाज

पहली जीत दर्ज करना चाहेगी दिल्ली

रणजी ट्रॉफी ▸ युवा ध्रुव शौरी की टीम का सामना आज आंध्र प्रदेश की टीम से

दोनों ही टीमों के उनके पहले मुकाबले रहे थे ड्रॉ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र के दूसरे चरण के मुकाबले मंगलवार से शुरू होंगे। इस चरण में कुल 18 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान जो मुख्य टीमें मैदान पर जोर-आजमाइश करने उतरेंगी, उनमें गत विजेता विदर्भ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड शामिल हैं।

दिल्ली की टीम पिछले रणजी सत्र में अपने ग्रुप में आठ में से एक मैच ही जीत सकी थी और नौ टीमों में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी। उसके लिए इस सत्र की शुरुआत भी निराशाजनक रही। ध्रुव शौरी की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम ने अपना पहला मुकाबला केरल के खिलाफ खेला, जिसमें उसे फॉलोऑन खेलना पड़ा। हालांकि, उसके लिए राहत की बात यह रही कि मैच ड्रॉ रहा और दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज कुणाल चंदेला और नीतिश राणा ने शतक जड़े। अब दिल्ली का अगला मुकाबला आंध्र प्रदेश से ओंगोले से होगा और ऐसे में दिल्ली की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। पहले मैच में आंध्र प्रदेश का भी कमोवेश दिल्ली जैसा ही हाल रहा। पहली पारी में उसके बल्लेबाजों की नाकामी के बाद दूसरी पारी में रिकी भुई और केएस भरत ने नाबाद शतकीय पारी खेली थीं और मैच ड्रॉ कराया था।

उमेश देंगे विदर्भ को मजबूती : पिछले दो बार की चैंपियन विदर्भ की नजर इस बार खिताबी हैट्रिक पूरी करने पर लगी हैं। उसने इस सत्र की भी शानदार शुरुआत की, लेकिन आंध्र के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के बावजूद उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। विदर्भ अब अपने घरेलू मैदान नागपुर में राजस्थान के खिलाफ उतरेगी। तेज गेंदबाज उमेश यादव की विदर्भ की टीम में वापसी हुई है, जिन्हें भारतीय टीम के भविष्य के दौरों को देखते हुए पहले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन अब बीसीसीआइ ने उन्हें दो मैचों में खेलने की अनुमति दे दी है। विदर्भ के लिए गणेश सतीश ने पिछले मैच में दोहरा शतक जड़ा था। टीम उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। कप्तान फैज फजल और अनुभवी वसीम जाफर भी पिछले मैच की निराशा को भूलकर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

उत्तर प्रदेश की कठिन डगर : उत्तर प्रदेश ने रेलवे के खिलाफ ड्रॉ रहे अपने पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अब उसका सामना आठ बार की चैंपियन कर्नाटक से उसके घरेलू मैदान हुबली में होगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश को अपने गेंदबाजों से ज्यादा निराशा अपने बल्लेबाजों से हुई थी। उसके गेंदबाजों ने रेलवे को दोनों पारियों में 300 रन के अंदर समेट दिया था, लेकिन रेलवे के गेंदबाज के सामने उसकी पहली पारी 175 रन पर ही सिमट गई थी। वहीं, कर्नाटक ने पिछले मैच में तमिलनाडु पर 26 रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी।

जोश में हरियाणा : हरियाणा ने इस सत्र के अपने पहले मैच में महाराष्ट्र को एक पारी और 68 रन से हराकर जोरदार शुरुआत की थी। इस जीत से वह जोश में है और उसका सामना अपने घरेलू मैदान रोहतक में त्रिपुरा से है। हरियाणा के बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला और शिवम चौहान ने पिछले मैच में शतक जड़े थे। उसके गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। हर्षल पटेल ने महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में नौ विकेट झटके थे तो आशीष हुड्डा ने सात विकेट लिए थे। वहीं, त्रिपुरा की टीम अपने पिछले मैच में झारखंड को फॉलोऑन खिलाने के बावजूद मैच गंवा बैठी थी।

जीत की लय कायम रखना चाहेगी झारखंड : झारखंड की टीम ने पिछले मैच में फॉलोऑन खेलने के बावजूद त्रिपुरा को 54 रन से हराकर इतिहास रचा था। वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में फॉलोऑन खेलने के बावजूद जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी थी। त्रिपुरा के खिलाफ पहली पारी में झारखंड के खराब प्रदर्शन के बाद दूसरी पारी में उसके बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके लिए दूसरी पारी में कप्तान सौरभ तिवारी और इशांक तिवारी ने शतक जड़े थे, जबकि गेंदबाजी में आशीष कुमार ने पांच विकेट लिए थे। अब झारखंड की टीम अपने घरेलू मैदान रांची में असम से भिड़ेगी। असम का सर्विसेज के खिलाफ पिछला मैच ड्रॉ रहा था। ऐसे में झारखंड अपनी जीत की लय को कायम रखना चाहेगी।

पंजाब का सामना हैदराबाद से : पटियाला के ध्रुव पांडव स्टेडियम में पंजाब का सामना हैदराबाद से होगा। मनदीप सिंह की कप्तानी वाली पंजाब की टीम ने अपने पिछले मैच में राजस्थान को उसके घर में 10 विकेट से रौंदा था। इस मैच में मनदीप ने शतक जड़ा था, जबकि गेंदबाजी में सिद्धार्थ कौल, बलतेज सिंह और सनवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, सनवीर और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी पहली पारी में नाकाम रही थी, लेकिन दूसरी पारी में इस जोड़ी ने 68 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वहीं, हैदराबाद को गुजरात के हाथों आठ विकेट से शिकस्त मिली थी।

बिहार के सामने मजबूत चंडीगढ़ : बिहार को चंडीगढ़ से उसके घरेलू मैदान पर भिड़ना है। ऐसे में उसके लिए चुनौती आसान नहीं है। बिहार को घरेलू मैदान पर खेलते हुए अपने पिछले मैच में पुडुचेरी के खिलाफ 10 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बल्लेबाज दोनों पारियों में 200 रन भी नहीं बना सके थे। हालांकि, गेंदबाजी में पहली पारी में विवेक कुमार ने पांच और आशुतोष अमन ने चार विकेट झटके थे। वहीं, चंडीगढ़ ने अपने पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश को पारी और 173 रन से शिकस्त दी थी। अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज पूरे मैच में उसके सिर्फ दो विकेट झटक सके थे। ऐसे बिहार के लिए चंडीगढ़ का सामना करना आसान नहीं होगा।

दबाव में उत्तराखंड : अपने पहले मैच में जम्मू-कश्मीर के हाथों 253 रन से हार का सामना करने वाली उत्तराखंड की टीम का सामना रायपुर में छत्तीसगढ़ से होगा। हालांकि, उन्मुक्त चंद की कप्तानी वाली उत्तराखंड की टीम के गेंदबाजों ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और जम्मू-कश्मीर की पहली पारी को 182 रन पर समेट दिया था, लेकिन उसे अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा। पहली पारी में उसके सिर्फ दो ही बल्लेबाज दहाई का अंक छू सके थे। ऐसे में उत्तराखंड के बल्लेबाजों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा और इसमें कप्तान उन्मुक्त भी शामिल हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ की टीम ओडिशा को पारी और तीन रन से हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है।

बल्लेबाजीके दौरान तमिलनाडु के बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। फाइल फोटो, प्रेट्र

रणजी ट्रॉफी में आज से शुरू होने वाले मुकाबले

मैच	स्थान
एलीट ग्रुप-ए	
आंध्र प्रदेश बनाम दिल्ली	ओंगोले
केरल बनाम बंगाल	थुंबा
पंजाब बनाम हैदराबाद	पटियाला
विदर्भ बनाम राजस्थान	नागपुर
एलीट ग्रुप-बी	
कर्नाटक बनाम उत्तर प्रदेश	हुबली
मध्य प्रदेश बनाम बड़ौदा	इंदौर
रेलवे बनाम सौराष्ट्र	विशाखापत्तनम
तमिलनाडु बनाम हिमाचल प्रदेश	डिंडिगुल
एलीट ग्रुप-सी	
असम बनाम झारखंड	रांची
छत्तीसगढ़ बनाम उत्तराखंड	रायपुर
हरियाणा बनाम त्रिपुरा	रोहतक
महाराष्ट्र बनाम जम्मू-कश्मीर	पुणे
ओडिशा बनाम सर्विसेज	कटक
प्लेट ग्रुप	
मणिपुर बनाम नगालैंड	कोलकाता
चंडीगढ़ बनाम बिहार	चंडीगढ़
गोवा बनाम मेघालय	पोरवोरिम
पुडुचेरी बनाम सिक्किम	पुडुचेरी
आंध्र प्रदेश बनाम मिजोरम	पुडुचेरी

मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जहां विराट कोहली हैं : बाबर आजम

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान की नई रन मशीन बाबर आजम की ख्वाइश क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली की 'महानता' की बराबरी करना है, हालांकि रिकॉर्डों के मामले में वह अभी भारतीय कप्तान से काफी पीछे हैं। खुद को कोहली का प्रशंसक बताने वाले 24 साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि उनकी चाहत टेस्ट और वनडे रैंकिंग में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज की बराबरी करना है। आजम ने कहा कि देखिए कोहली पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। वह अपने देश में एक महान खिलाड़ी हैं। ईमानदारी से कहूं तो अभी उनसे मेरी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मैं भी वहां पहुंचना चाहता हूं, जहां वह आज हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और लोगों ने मेरी और कोहली की काफी तुलना की है, लेकिन मुझे इस बात का अहसास है कि विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल होने के लिए टेस्ट मैचों में काफी रन बनाने होंगे। इसलिए हाल के दिनों में मैंने टेस्ट क्रिकेट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान दिया। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट में नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले इस बल्लेबाज ने कहा कि वह कोहली की तरह मैच विजेता खिलाड़ी बनना चाहते है। बाबर की यह पिछले तीन टेस्ट में दूसरी शतकीय पारी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरी तुलना कोहली या स्टीव स्मिथ से करता है तो मैं दबाव में नहीं आता हूं। मैं अब अपनी बल्लेबाजी पर काफी ध्यान देता हूं और घंटों तक मैं अपनी बल्लेबाजी के वीडियो देखता हूं। मैं अपनी गलतियों की पहचान कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूं कि उन्हें दोहराया ना जाए।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो टेस्ट मैचों में एक शतकीय और एक 97 रन की पारी खेलने वाले आजम ने कहा कि खेल का पारंपरिक प्रारूप उनके लिए सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रिसबेन में पहली पारी में खराब शॉट खेलकर सस्ते में आउट हो गया तो मैं खुद से बहुत नाराज हुआ था क्योंकि मुझे अहसास हुआ कि किसी भी शीर्ष बल्लेबाज को इस तरह से आउट नहीं होना चाहिए। दूसरी पारी में मैं धैर्य से खेला और उसका फायदा हुआ। बाबर को अब अपना अगला मुकाबला कराची में खेलना है। बाबर को अपने इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कराची उनका घरेलू मैदान हैं। ऐसे में बाबर अपने करियर में पहली बार कराची में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। बाबर ने कहा कि मैं इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा ही उत्साहित हूं।

पाक बल्लेबाज बाबर आजम। फाइल फोटो

पहले दो टेस्ट से बाहर हुए नगिदी

जोहानिसबर्ग, एएफपी : दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज लुंगी नगिदी इंग्लैंड के साथ सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। नगिदी को हैमस्ट्रिंग की चोट है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को इसकी पुष्टि की। नगिदी को यह चोट एमएसएल टी-20 लीग के दौरान लगी थी। सीएसए के मुताबिक नगिदी अब जनवरी 2020 में क्रिकेट में वापसी करेंगे और इससे पहले रिहैब पर रहेंगे। इंग्लैंड टीम चार टेस्ट, तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच रही है। सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से सेंचुरियन में होने वाले टेस्ट मैच से होगी। दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को पहले दो टेस्ट के लिए टीम की घोषणा की है, जिसमें नगिदी का नाम नहीं है।

टीम फाफ डुप्लेसिस (कप्तान), तेंबा बावुमा, क्विंटन डिकॉक, डीन एल्गर, जुबैर हमजा, ब्यूरेन हैंड्रिक, केशव महाराज, पीटर मलान, एडेन मार्करैम, एनरिच नोर्ट्जे, डेन पीटरसन, एंडिले फेहलुकवायो, वर्नोन फिलेंडर, ड्वेन प्रीटोरियस, कैगिसो रबादा, रूडी सेकंड, रेसे वान डे डूसेन।

बीबीसी वर्ष का खेल चेहरा बने स्टोक्स

लंदन, आइएएनएस : इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को बीबीसी वर्ष का खेल चेहरा चुना गया है। स्टोक्स 2005 के बाद यह सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। साल 2005 में हरफनमौला एंड्रयू फ्लिंटॉफ को यह पुरस्कार मिला था। अब स्टोक्स को यह सम्मान मिला है। स्टोक्स ने अपने शानदार खेल से इंग्लैंड को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। प्रिंसेस रॉयल और मैनचेस्टर युनाइटेड तथा स्कॉटलैंड के पूर्व फुटबॉल स्टार डेनिस लॉ ने स्टोक्स को यह पुरस्कार दिया। पुरस्कार पाने के बाद स्टोक्स ने कहा कि यह एक व्यक्तिगत पुरस्कार है, लेकिन यह एक टीम खेल है। आपके लिए सबसे बड़ा पल अपने साथियों के साथ बैक रूम में शानदार पल बिताना होता है। इनसे ही महान पल बनते हैं। दो साल पहले मैं मुश्किलों से गुजर रहा था और उस समय कई लोगों में मेरी मदद की थी। मैं आप सबके बगैर कुछ नहीं। आपका धन्यवाद। स्टोक्स से पहले यह पुरस्कार एंडी मरे, जॉनी विल्किंसन और स्टीव रेडग्रेव ने जीते थे।

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से बाहर हुए फर्ग्यूसन

पर्थ, एएफपी : दायें हाथ के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें पहले टेस्ट में दायीं पिंडली में चोट लग गई थी। पर्थ स्टेडियम में खेले गए पहले मैच से टेस्ट में पदार्पण करने वाले फर्ग्यूसन पहले दिन सिर्फ 11 ओवर की गेंदबाजी कर सके थे। इसी दिन उनकी पिंडली में चोट लगी थी। इसी कारण वह मैच से बाहर हो गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने सोमवार को ट्वीट किया कि लॉकी फर्ग्यूसन ऑस्ट्रेलिया से घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले टेस्ट मैच में दायीं पिंडली में चोट लग गई है। इस चोट के चार से छह सप्ताह में ठीक होने की उम्मीद है। बोर्ड ने बताया कि वह जल्द ही उनके विकल्प का एलान करेगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट बॉक्सिंग डे से शुरू हो रहा है।

विविध

शादियों के लिए प्लेटफॉर्म और जमीन किराए पर देगा रेलवे

अतुल शुक्ला, जबलपुर : आय बढ़ाने के लिए रेलवे अब स्टेशनों के पास खाली पड़ी व्यावसायिक और अनुपयोगी जमीन शादी-पार्टी के लिए किराए पर देगा। जबलपुर सहित सभी 66 रेल मंडलों ने अपनी सीमा में आने वाली ऐसी भूमि चिह्नित कर जानकारी रेलवे बोर्ड को भेज दी है। बोर्ड से गाइडलाइन तय होते ही खाली जमीनों को किराए पर देने का काम शुरू हो जाएगा। इसमें स्टेशन के ऐसे प्लेटफॉर्म को भी शादी-पार्टी के लिए किराए पर दिया जाएगा, जहां दिन में दो से तीन ट्रेन ही आती हैं या फिर इनका उपयोग वीआइपी मूवमेंट के लिए ही किया जाता है। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने कुछ दिन पूर्व सभी रेल मंडल प्रबंधकों के साथ परिवर्तन बैठक की थी। इसमें अन्य माध्यम से रेलवे की आय बढ़ाने पर सुझाव मांगे थे।

रेलवे की व्यावसायिक भूमि को शादी-पार्टी के लिए किराए पर देने का सुझाव दिया है। अभी इस पर गाइडलाइन तैयार की जा रही है कि किस नियम के तहत किराए पर भूमि दी जाएगी।
– शोभन चौधुरी, एजीएम, पश्चिम-मध्य रेलवे

परमार्थ निकेतन आश्रम में निर्माण पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ डीएम की रिपोर्ट से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं, दोबारा जांच के आदेश
▸ डीएम से पूछा कि भूमि पर वर्तमान में क्या निर्माण हो रखा है?

ऋषिकेश में गंगा किनारे अतिक्रमण और परमार्थ निकेतन आश्रम परिसर में निर्माण कराने के मामले में पौड़ी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट से नैनीताल हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने डीएम से दोबारा जांच कर छह जनवरी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आश्रम परिसर में निर्माण कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आश्रम के घाट को सभी के लिए खोलने के भी आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने इस संबंध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों पौड़ी के डीएम से इस प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। इसके साथ ही आश्रम का सीवरेज गंगा में प्रवाहित करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी थी। इस क्रम में सोमवार को पौड़ी के डीएम धीराज गर्ब्याल हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और रिपोर्ट सौंपी।

1979 में खत्म हुई लीज, नहीं हुआ नवीनीकरण : डीएम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परमार्थ निकेतन को वर्ष 1957 में दी गई 2.39 हेक्टेयर भूमि की लीज वर्ष 1979 में खत्म हो चुकी है। जिसके बाद लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है। वन विभाग के स्तर पर लीज नवीनीकरण का मामला विचाराधीन है। इसी भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। हाई कोर्ट सिर्फ इन तथ्यों से संतुष्ट नहीं हुआ और डीएम से पूछा कि इस भूमि पर वर्तमान में क्या निर्माण हो रखा है? इसका सीमांकन कर मानचित्र पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने डीएम की तरफ से पेश रिपोर्ट पर नाराजगी जताई, साथ ही दोबारा जांच कर छह जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

लोगों के लिए खोला घाट : हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि परमार्थ निकेतन आश्रम जिस घाट पर अपना स्वामित्व बता रहा है, उसे सभी लोगों के लिए खोला जाए। सुनवाई के दौरान आश्रम के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि गंगा किनारे घाट को सबके लिए खोल दिया गया है। इधर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आज कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई।

जनहित याचिका में ये हैं आरोप : जनहित याचिका में कहा गया है कि स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा किनारे 70 मीटर दायरे की सरकारी भूमि पर में कब्जा कर लिया है। गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति बनाने के साथ ही व्यावसायिक भवन का निर्माण भी किया गया है। यह भवन बैंक एवं अन्य लोगों को किराए पर दिया गया है। आश्रम प्रबंधन इनका किराया भी वसूल रहा है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

प्रतीकात्मक

पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध को नीतीश ने लिखा पीएम को पत्र

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध की मांग की है। सोमवार को प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ घटित सामूहिक दुष्कर्म व उसके बाद जघन्य तरीके से हुई हत्या ने पूरे देश के जनमानस को झकझोर दिया है। इस तरह की घटनाएं अत्यंत दुःख एवं चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे व युवा अश्लील, हिंसक व अनुचित सामग्री देख रहे हैं जो अवांछनीय है। कई मामले ऐसे भी हैं कि दुष्कर्म की घटनाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि वैसे तो आईटी एक्ट 2000 (यथा संशोधित 2008) में कुछ प्रावधान किए गए हैं पर वे प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण को ले प्रभावी प्रभावी कार्रवाई की जानी जरूरी है।

शिप्रा मर चुकी, इसे नवजीवन देने को सरकार निभाए दायित्व

नईदुनिया, उज्जैन

▸ 111 नदी घाटी संरचनाओं से जुड़े 250 से अधिक जल सत्याग्रही जुटे

शिप्रा और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार से तीन दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन की शुरुआत हुई। पहले दिन देश की 111 नदी घाटी संरचनाओं से जुड़े 250 से अधिक जल सत्याग्रही इसमें शामिल हुए। उन्होंने शिप्रा की दुर्गति पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह ने कहा कि शिप्रा अब मर चुकी है। इसे फिर से जीवन देने के लिए सरकार को दायित्व निभाना होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि शिप्रा के पुनर्जीवन के लिए समाज और सरकार द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के लिए श्वेत पत्र तैयार किया जा रहा है। ये श्वेत पत्र सरकार को सौंपा जाएगा।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह ने कहा कि शिप्रा की मौजूदा स्थिति के लिए समाज से ज्यादा सरकार दोषी है। नदी का पानी अब न पीने लायक रहा है और न स्नान करने लायक। शिप्रा के मरने के तीन बड़े कारण हैं। पहला, नदी में सारी गंदगी डालकर इसे मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना देना। दूसरा, शिप्रा के दोनों ओर अतिक्रमण और तीसरा शिप्रा के प्रवाह का शोषण। शिप्रा के पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसके बहाव क्षेत्र को ठीक करना होगा।

गंगा की तर्ज पर बनानी होगी योजना : सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा कि शिप्रा को सदानीरा, शुद्ध बनाने के लिए गंगा की तर्ज पर श्वेत पत्र जरूरी है। पहले ही दिन राजेंद्र सिंह ने श्वेत पत्र निर्माण समिति का गठन भी कर दिया। समिति का अध्यक्ष वाटर रिसोर्स एडवाइजर सुधींद्र शर्मा को नियुक्त किया गया। सदस्य पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरसी गुप्ता, जियोलॉजिस्ट डॉ. विजय टेलर, आरके गुप्ता, डॉ. पीपी वशिष्ठ, देवेंद्र जोशी, प्रमोद जैन, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के सलाहकार डॉ. केजी व्यास, मनीष सिंह को नियुक्त किया गया। इन सभी ने तत्काल बैठक कर कार्य योजना बनाई। कहा कि ये कार्य योजना 18 दिसंबर को अंतिम रूप ले लेगी। उद्घाटन से पहले सम्मेलन के आयोजक जल बिरादरी, रोटरी क्लब द्वारा जल यात्रा निकाली गई। सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को तालाबों के अस्तित्व समेत 11 विषयों पर मंथन होगा।

राजेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

वृद्धा पेंशन के लिए इतनी मशक्कत

झारखंड के चतरा जिले के कुंदा के लेवाड़ गांव से पेंशन के लिए 92 वषीया चैतिया देवी को कुछ इस तरह बंगही से लेकर बेटा नागेश्वर भारती और दामाद ननकू भारती सोमवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। मां चैतिया चलने फिरने से लाचार है। पेंशन लेने के लिए बेटा और दामाद हर महीने बंहगी से इसी प्रकार उन्हें लेकर आते हैं। इस बार उनकी मेहनत सार्थक नहीं हो सकी। बैंक की शाखा में लिंक नहीं रहने के कारण घंटों इंतजार करते रहे। अंत में तीन बजे उसी तरह बंहगी से लेकर बैरंग वापस लौट गए।
अरुण कुमार गुप्ता

70 करोड़ की धोखाधड़ी में कंपनी निदेशक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ फर्जी कंपनियों को भुगतान कर खर्च दिखाने और कम लाभ दिखाने का आरोप
▸ कंपनियों को दिए गए अनुबंधों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला

बिना काम कराए फर्जी भुगतान करके कंपनी के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड के निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान मुंबई के निवासी आरएल काबरा के रूप में हुई है। उसे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी में शामिल कंपनी के कई अन्य अधिकारियों की तलाश की जा रही है।

एडिशनल कमिश्नर ओपी मिश्रा ने बताया कि 6 दिसंबर 2018 को मैसर्स एसो इन्फ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आशीष भिवानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि अगस्त 2010 में उनसे मैसर्स आइएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के निदेशक रवि पार्थसारथी, हरि शंकरन और के. रामचंद ने संपर्क किया था। बड़े वादों के आधार पर उन्होंने आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड में निवेश करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड के गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की एसपीवी के 15 फीसद शेयर लेने के लिए 170 करोड़ रुपये का निवेश किया। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को पता लगा कि कंपनी लाभ में नहीं है और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मई 2018 में, शिकायतकर्ता को गुरुग्राम के आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिए गए डिमांड नोटिस के बारे में पता लगा। जिसमें कहा गया था कि आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड ने सिल्वरपॉइंट इन्फ्राटेक लिमिटेड को फर्जी कांट्रेक्ट के ऑर्डर दिए हैं। जबकि वास्तव में इस कंपनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। सिल्वरपॉइंट इन्फ्राटेक लिमिटेड के चालान जाली और मनगढ़ंत हैं। आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड ने अपना खर्च बढ़ाने और कम लाभ दिखाने के लिए ऐसा किया है। सिल्वरपॉइंट कंपनी को भुगतान की गई 21.88 करोड़ रुपये की राशि वास्तविक व्यय नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि आइएलएंडएफएस रेल लिमिटेड के निदेशकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर कंपनी के निधियों का दुरुपयोग किया, जिससे पीड़ित की कंपनी को 70 करोड़ का नुकसान हुआ।

जांच के दौरान आरोपितों से पूछताछ की गई, लेकिन कंपनियों को दिए गए अनुबंधों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोई एस्टीमेट नहीं बनाया गया, किसी भी ठेकेदार का कोई नाम, पता व रिकॉर्ड में नहीं दिया गया। पैसे के उपयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिली। कंपनियों को अलग-अलग बार में कई बार भुगतान किया गया। हर कंपनी ने टीडीएस और सर्विस टैक्स के नाम पर कम से कम दो प्रतिशत का कमिशन रखा था। मामले की जांच करने के बाद आरोपितों की तलाश के लिए टीम बनाई गई। आरोपितों के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया। आरोपित आरएल काबरा को जयपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है और चार दिन की रिमांड पर लेकर मामले की पूरी जानकारी और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर दिन सर्द बना रहेगा। सुबह अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के तापमान में कमी आएगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/21/आंबा	अहमदाबाद	28/15/आंबा
कोलकाता	27/18/आंबा	बड़ौदा	29/17/आंबा
चेन्नई	30/22/आंबा	नागपुर	30/15/आंबा
हैदराबाद	30/19/आंबा	इन्दौर	28/17/आंबा
बंगलूरू	28/17/आंबा	राँची	26/14/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/आंबा	पटना	24/14/व
गुवाहाटी	23/14/आंबा	जमशेदपुर	28/15/आंबा
गंगटोक	09/-2/ आंबा	पुणे	30/18/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
मंगलवार 17 दिसंबर 2019
16
www.jagran.com

इंसान के आसमान में उड़ने के सपने को पहली बार मिले पंख

1903 में आज ही अमेरिका के राइट बंधुओं ने राइट फ्लायर नाम के विमान को पहली बार उड़ाया था। 12 सेकंड की इस उड़ान ने आज के आधुनिक उड्डयन युग की नींव रखी। इस घटना से दो दिन पहले इस विमान की तीन सेकंड की टेस्ट फ्लाइट हुई थी।

क्रांतिकारियों ने सांडर्स को मार लालाजी की मौत का लिया बदला

1928 में आज ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सांडर्स की हत्या कर दी थी। यह हत्या स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी।

भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे मुहम्मद हिदायतुल्लाह

मुहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में आज ही लखनऊ में हुआ था। वह 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे। वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। वह एकमात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। 18 सितंबर 1992 को वह दुनिया से रुखसत हो गए।

इधर-उधर की

पेश है सौ भाषाएं बोलने वाला अनोखा रोबोट

तेहरान,एजेंसी : ईरान में तेहरान विश्वविद्यालय ने एक ऐसा रोबोट बनाया है, जो सौ भाषाएं बोल सकता है। इतनी ही भाषाओं को समझकर यह अनुवाद भी कर सकता है। यह चेहरों को पहचान सकता है और फुटबॉल को किक लगा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने चार साल में इस रोबोट को तैयार किया है। इसका नाम सुरेना रखा गया है। यह चीजों को उठा सकता है। 100 अलग-अलग वस्तुओं को पहचान सकता है। यह हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन भी कर सकता है। रोबोट सुरेना 170 सेंटीमीटर लंबा और 70 किलोग्राम वजनी है। एक घंटे में 700 मीटर चलने में सक्षम है। ऊबड़-खाबड़ जमीन पर यह आगे-पीछे और दाएं-बाएं मुड़कर संतुलन बनाए रख सकता है। इसके अलावा भी इसमें मनुष्यों के समान कई गुण हैं।

एक्सोप्लैनेट में जीवन की संभावना मुश्किल

रहस्यमय ब्रह्मांड ▶ तारों के विकिरण से बचने के लिए किसी भी ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी

अमेरिका की न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन

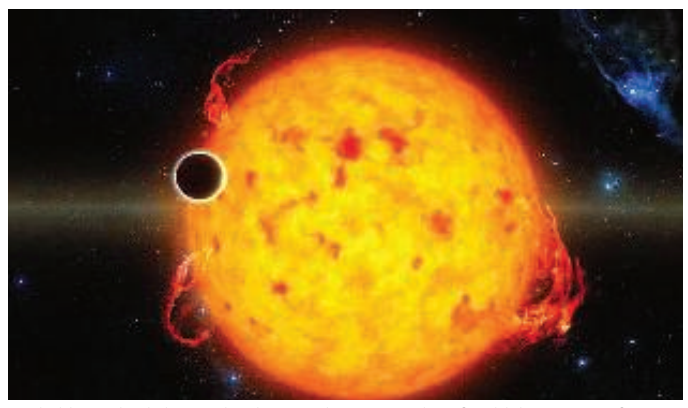

एक्सोप्लैनेट अपने तारे से निकलने वाले विकरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। प्रतीकात्मक

न्यूयार्क, प्रेट्र : हाल के अध्ययनों से और ब्रह्मांड की जुटाई गई जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक यह दावा करते रहे हैं कि सौरमंडल के बाहर के ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है, में जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एसी संभावना एक्सोप्लैनेट के उसके तारे से दूरी और अन्य गणनाओं के आधार पर जताई थी। अनुमान था कि उचित दूरी होने के कारण वहां पानी और रहने योग्य वातावरण मौजूद हो सकता है, लेकिन अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वे सभी एक्सोप्लैनेट जो अपने तारों से उचित दूरी पर भी स्थित हैं, उन सभी में जीवन की संभावना मुश्किल हो सकती है।

अमेरिका में न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से निकलने वाले विकरण (फ्लेयर) के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक किसी एक्सोप्लैनेट में चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय दबाव नहीं मौजूद है वहां रहने योग्य स्थितियां नहीं मौजूद हो सकती हैं। 'रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लेटर्स' में प्रकाशित अध्ययन में पता चला है कि तारों से निकलने वाली फ्लेयर एक्सोप्लैनेट को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इससे केवल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय दबाव ही बचा सकता है।

न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के दमित्रा अत्री ने कहा कि जैसे ही हम किसी एक्सोप्लैनेट का पता लगाते हैं और उसमें जीवन की संभावना ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय दबाव का पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को और अधिक समझ विकसित करने की जरूरत है। एक्सोप्लैनेट में चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय दबाव, तारों से दूरी और अन्य कारकों का बारीकी से अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है वहां जीवन की संभावना है या नहीं।

इसरो ने रिसैट-2बीआर1 का एंटीना सेट किया

नई दिल्ली, एएनआइ : इसरो ने हाल ही में लांच किए गए अपने मिशन की सफलता को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हाल ही में लांच किए गए रिसैट-2बीआर1 का रेडियल रिब एंटीना अंतरिक्ष में सेट होते हुए दिखाया गया है। ट्विटर पर शेयर इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। इसरो ने इस वीडियो को अपने सेटेलाइट के ऑन बोर्ड कैमरे से शूट किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि रिसैट-2बीआर1 में लगा रेडियल रिब एंटीना जो किसी छाते की तरह पहले बंद था, लेकिन सेटेलाइट के अपनी कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे-धीरे खुलकर पूरा फैल जाता है। वीडियो में सेटेलाइट की यह छतरी धीरे-धीरे पूरी तरह खुलती हुई दिखती है। यह वीडियो बीते 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे इस एंटीना के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक तैनाती का है। 3.6 मीटर वाला यह एंटीना लांचिंग के समय स्पेसक्राफ्ट में फोल्ड करके रखा गया था। जिसे बाद में खोला गया।

हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देती हैं छोटी कक्षाएं

वाशिंगटन, प्रेट्र : हमेशा से यह माना जाता रहा है कि कक्षा में जितने कम छात्र होंगे उतना ही पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आम तौर पर परिजन भी स्कूल में बच्चों के लिए छोटी कक्षाओं की मांग करते हैं। उनका मानना होता है कि छोटी कक्षा में शिक्षक छात्र पर अधिक ध्यान देते हैं और कक्षा में उसका पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात को खारिज कर दिया गया है।

गणित और विज्ञान के शिक्षण पर किए गए दीर्घकालिक अध्ययन के अनुसार यह साबित नहीं होता कि छोटी कक्षा होने पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़ जाता है।

अमेरिका की मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि छोटी कक्षाओं का प्रभाव देश, विषय, विद्यार्थियों के कौशल की वजह से भिन्न-भिन्न हो सकता है। इसमें कई अन्य कारकों की भी भूमिका हो सकती है। 'रिसर्च पेपर इन एजुकेशन' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि पहले भी कक्षा के आकार से पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन किए गए हैं। इनमें से कुछ में लाभ बताया गया है तो कुछ में हानि। यानी कुल मिलाकर स्थिति अनिर्णायक रही है। शोधकर्ताओं ने 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमैटिक्स एंड साइंस स्टडी (टीआइएमएसएस) के डाटा का विश्लेषण किया। 'टीआइएमएसएस' ने 1995 से हर चार साल बाद गणित और विज्ञान में 50 देशों के चौथे ग्रेड (9-10 वर्ष की आयु) और आठवीं ग्रेड (13-14 आयु वर्ग) के विद्यार्थियों के प्रदर्शन और उपलब्धि की निगरानी की है। इन

प्रतीकात्मक

रिकॉर्डों में विद्यार्थी की विषय की रुचि, स्वयं के प्रति रुख और कक्षा के आकार की जानकारी भी शामिल है।

शोधकर्ताओं ने इस विश्लेषण में चार यूरोपीय देशों हंगरी, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवेनिया में आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का चार साल का डाटा भी शामिल किया। यहां के 151 स्कूल के 231 कक्षाओं के 4277 विद्यार्थियों को शामिल किया। अध्ययन में पाया गया कि छोटी कक्षाओं का लाभ रोमानिया और लिथुआनिया में तो हुआ, लेकिन हंगरी और स्लोवानिया में इसका कोई प्रभाव नहीं था। शोधकर्ताओं ने बताया कि छोटी कक्षा का विषयों के आधार पर भी प्रभाव पड़ता है। रोमानिया में छोटी कक्षाओं में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की पढ़ाई में खासा लाभ देखा गया। वहीं, लिथुआनिया में दूसरे विषयों में इसका लाभ देखा गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा का आकार कम करने से छात्रों के प्रदर्शन में सुधार होने की गारंटी नहीं है।

शोध अनुसंधान

ई-सिगरेट से बढ़ सकता है फेफड़ों के रोग का खतरा

पारंपरिक सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के दावे के साथ पेश की गई ई-सिगरेट से होने वाले नुकसान को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया कि ई-सिगरेट के इस्तेमाल से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस (श्वसन नली में संक्रमण) जैसी फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष ई-सिगरेट और तंबाकू सेवन को लेकर करीब 32 हजार लोगों पर तीन साल तक किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इस अध्ययन से जुड़े प्रोफेसर स्टैंटन ग्लैंट्ज ने कहा, 'तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के बाद भी ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने वालों में फेफड़ों के रोग का खतरा करीब तीन गुना ज्यादा पाया। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ई-सिगरेट भी नुकसानदेह है।' पूर्व में किए गए अध्ययन में भी ई-सिगरेट और फेफड़ों के रोग के बीच संबंध पाया गया था। -प्रेट्र

वायु प्रदूषण से हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम

बढ़ता वायु प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का कारण माना जा रहा है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण का इंसानों और पशुओं की सेहत पर नुकसानदेह प्रभाव पाया है। इसके चलते हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, वायु प्रदूषण खासतौर पर वायु में मौजूद सूक्ष्म कणों या पार्टिक्युलेट मैटर (पीएम) से उपजे हृदय रोग और स्ट्रोक से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। प्रमुख शोधकर्ता और ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर जेरेमी पियरसन ने कहा, 'हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण हृदय पर नुकसानदेह असर डाल सकता है। नए अध्ययन में इसके और गहरे संबंध का पता चला है।' -आइएएनएस

एवरेस्ट फतह करना है तो बतानी होगी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, बीमा भी होगा अनिवार्य

2019 में चढ़ाई के दौरान नौ लोगों की मौत हो गई थी। प्रतीकात्मक

काठमांडू, आइएएनएस : माउंट एवरेस्ट को फतह करने के इच्छुक सभी पर्वतारोहियों को अब अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बतानी होगी। उन्हें पंजीकृत डॉक्टर से प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही अनिवार्य बीमा की कॉपी भी देनी होगी। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल का पर्यटन विभाग इन नियमों को अगले सीजन से लागू करने की तैयारी में है।

एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य वाले पर्वतारोहियों को ही मंजूरी देने के मकसद से नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। 2019 में चढ़ाई के दौरान नौ लोगों की मौत हो गई थी। पर्यटन विभाग की निदेशक मीरा आचार्य ने कहा, पिछले चार सालों के दौरान एक वर्ष में जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों की यह सबसे अधिक संख्या है। चूंकि सबसे अधिक मौतें स्वास्थ्य कारणों के चलते हुई हैं, इसीलिए यह मसौदा तैयार किया गया है। मंत्रालय द्वारा इन नियमों को मंजूरी देने के बाद इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। तब तक 16 साल से कम उम्र के पर्वतारोहियों, गंभीर बीमारियों वाले व्यक्तियों और आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर रोक पहले की तरह प्रभावी रहेगी। अनिवार्य बीमा के संबंध में निदेशक ने कहा कि यह मुख्य रूप से बचाव और उपचार से संबंधित है। चढ़ाई के दौरान पर्वतारोही के बीमार होने या कहीं ऊंचाई पर फंसने की स्थिति में यह बीमा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगा।

एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बचाव और राहत का काम करने वाली संस्थाओं के अनुसार, डेथ जोन (8,000 मीटर से ऊपर) से ऊपर अगर किसी पर्वतारोही की मौत होती है तो उसका शव निकालने में दो लाख डॉलर (करीब डेढ़ करोड़ रुपये) से ज्यादा का खर्च आता है। जबकि डेथ जोन से नीचे फंसे लोगों को निकालने में 14 से 42 लाख रुपये का खर्च आता है।

दिल की बीमारी से दूर रखता है अंडे का सेवन

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं का कहना है कि रोजाना एक अंडे के सेवन से हृदय की बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी होता है कि अपने आहार में कम कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करें।

रक्त में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल धमनियों में मोटे थक्के बनाता है, जिसकी वजह से रक्त के संचार में बाधा उत्पन्न होती है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। 'सर्कुलेशन' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अंडे के सेवन से दिल की बीमारी को दूर रखा जा सकता है।

शोधकर्ताओं का कहना है अंडे का सेवन नहीं करने वाले लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों से दूर रहने के लिए सेचुरेटेड फैट (डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल) का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। उन्हें इसकी जगह पॉलीअनसेचुरेटेड फैट (मकई, कैनोला आदि) को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इससे धमनियों में वसा का जमाव बंद हो जाता है।

भारत के डेक्कन ट्रैप्स ने पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव छोड़ा था

वाशिंगटन, प्रेट्र : एक अध्ययन के अनुसार भारत के डेक्कन ट्रैप्स (दक्षिणी पठार) में बड़े पैमाने पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने जलवायु और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जोकि विश्व में लंबे समय तक रहा। अमेरिका की मिशीगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि 6.6 करोड़ साल पहले डेक्कन ट्रैप्स में ज्वालामुखी विस्फोटों से पृथ्वी के लगभग तीन चौथाई पेड़ और विभिन्न प्रजातियों के जानवर समाप्त हो गए। इसका सबसे ज्यादा असर डायनासोरों पर भी पड़ा। वैज्ञानिकों ने काफी समय तक डेक्कन ट्रैप्स में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के महत्व पर बहस की है। यहां विस्फोट क्षुद्रग्रहों की बमबारी से पहले शुरू हुए थे और दस लाख सालों तक कभी शांत तो कभी बेहद प्रबल रहे। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों ने समुद्री घोंघों के कवच के जीवाश्म से इस पर नई जानकारी प्राप्त की है। कवच के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि ज्वालामुखी विस्फोटों से वातवरण में पारे के प्रदूषक तत्व फैल गए थे।

परवाज को तैयार बाज

सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज फाल्कनरी फेस्टिवल के मौके पर राजधानी रियाद के उपनगर मलहम में अपने पालतू बाज को उड़ाता एक प्रतियोगी। सऊदी फाल्कन्स क्लब द्वारा आयोजित यह बेहद लोकप्रिय महोत्सव है। इसमें अलग-अलग वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बाजों के अलावा ऊंटों की दौड़ भी इस इवेंट का हिस्सा है। बाजों की सौंदर्य प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। इसमें विजेताओं को इनाम के रूप में भारी-भरकम रकम दी जाती है। इस वर्ष पहली बार एक महिला ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। रायटर

गनावा संस्कृति यूनेस्को की सूची में शामिल

मोरक्को की गनावा संस्कृति को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह दिए जाने की खुशी में एस्साओरिया शहर में जश्न मनाते गनावा पारंपरिक समूह के सदस्य। संगीत, अफ्रीकी रीति-रिवाजों और सूफी परंपराओं से ओतप्रोत यह संस्कृति अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में भी फैली हुई है। अक्सर रंग-बिरंगे परिधानों में सजे गनावा के संगीतकार गुनबेरी बजाते हैं। लट्टू की तरह दिखने वाले इस वाद्ययंत्र में तीन तार होते हैं, जिन्हें क्रेकब कहा जाता है। इससे संगीत की मधुर स्वरलहरियां निकलती हैं। एएफपी

स्क्रीन शॉट

करण जौहर ने पूरा किया अपना वादा

हिंदी सिनेमा में कब कौन किसकी जगह ले ले, यह कहा नहीं जा सकता है। यहां ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अपने वादों पर कायम रहें। बात अगर करण जौहर की करें, तो वह अपने वादों के पक्के लगते हैं। तभी तो करण ने अंगद बेदी को अपनी आगामी फिल्म में मौका दिया है। करण की फिल्म 'कारगिल गर्ल' में अंगद बेदी अहम किरदार में होंगे। करण ने यह वादा अंगद से तब किया था, जब उन्होंने उनकी फिल्म 'सूरमा' देखी थी। फिल्म में अंगद दिलजीत दोसांझ के किरदार संदीप सिंह के बड़े भाई के किरदार में थे। जिस तरह से फिल्म में उन्होंने बड़े भाई का किरदार निभाया था, करण उससे काफी प्रभावित हुए थे। करण ने अंगद को फिल्म देखने के बाद मैसेज किया था कि उन्होंने उनकी फिल्म देखी है और वह भविष्य में उन्हें अपनी किसी फिल्म में कास्ट जरूर करेंगे। हालांकि अंगद करण जौहर की फिल्म 'उंगली' में काम कर चुके हैं। जब कारगिल गर्ल की स्क्रिप्ट करण के पास आई, तब करण ने अंगद को कॉल करके कहा कि वह एक बार फिल्म के निर्देशक शरण शर्मा से मिल लें। अंगद का कहना है कि करण भले ही बहुत बड़े निर्माता-निर्देशक हैं, लेकिन उनके पांव हमेशा जमीन पर रहते हैं। वह हमेशा प्रतिभाशाली लोगों को मौका देते हैं। 'कारगिल गर्ल' गुंजन सक्सेना की बायोपिक है। गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रह चुकी हैं। कारगिल युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही है। फिल्म में गुंजन का किरदार जाह्नवी कपूर निभा रही हैं। अंगद उनके भाई के किरदार में होंगे। अंगद के मुताबिक, भाई-बहन के बीच की जो बॉन्डिंग है, वह इस फिल्म का मुख्य आधार होगी।

करीना को पसंद आते हैं सच्चे लोग

करीना कपूर खान ने लगभग दो दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया है। इसकी वजह यह है कि वे लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। जल्द ही करीना की फिल्म 'गुड न्यूज' रिलीज होने वाली है। करीना कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोग एक-दूसरे के काम की तारीफ करते नजर आते हैं, मगर वे आपके काम के बारे में कभी सच नहीं बताते हैं। जबकि एक स्टार के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह काम के बारे में सच जान सके। तभी वह बेहतर बन सकेगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में करीना ने कहा, 'मैं हमेशा उम्मीद करती हूं कि मेरे करीबी लोग मेरी फिल्मों के बारे में सच बोलें। मैं इतने सालों से अपनी जगह इसीलिए बनाकर रख पाई, क्योंकि मैं 'यस मैन' टाइप लोगों से घिरी नहीं रहती हूं। एक एक्टर के लिए जरूरी है कि वह ऐसे लोगों के साथ रहे, जो उसे सच्चाई बताते रहें। मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं रखती, जो हमेशा मेरे काम को अच्छा कहें। पहले अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूं।' करीना कहती हैं, 'मैंने 22 साल की उम्र में 'चमेली' में काम किया, जिस समय वूमन-लीड फिल्में कम होती थीं। 'वीरे दी वेडिंग' को करने से कई एक्ट्रेस ने मना कर दिया था। कोई भी बोल्ड फिल्म नहीं करना चाहती थी।' 'गुड न्यूज' में अपनी भूमिका पर करीना कहती हैं, 'आजकल मैं कम फिल्में कर रही हूं, इसलिए चाहती हूं कि लोग मेरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्साइटेड रहें।'

पिता को विदेश में मिले सम्मान पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

इन दिनों अमिताभ बच्चन यूरोप में अपनी फिल्म 'चेहरे' की शूटिंग कर रहे हैं। उनके लिए यूरोप और भी दिल के करीब तब हो गया, जब वहां उनके पिता कवि डॉ. हरिवंश राय बच्चन को सम्मानित किया गया। उनके लिए पोलैंड में एक प्रार्थना रखी गई थी, जिसकी कुछ तस्वीरें अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। फूलों से सजी पिता की तस्वीर के साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'यूरोप के सबसे पुराने चर्च में से एक, पोलैंड में बाबूजी के लिए हुई प्रार्थना में। दिल को छूने और भावुक करने वाला पल। उनकी आत्मा को जरूर प्यार और शांति मिल रही होगी। बिशप और पोलैंड की जनता को धन्यवाद।'

'थप्पड़' और 'बंकर' की रिलीज तारीखें घोषित, अप्रैल में रिलीज होगी 'गुलाबो सिताबो'

सोमवार को 'थप्पड़' और 'बंकर' दो नई फिल्मों की रिलीज डेट का एलान किया गया। वहीं अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म 'गुलाबो सिताबो' की रिलीज डेट में भी बदलाव किया गया है। अब 'गुलाबो सिताबो' 24 अप्रैल के बजाय एक हफ्ते पहले यानी 17 अप्रैल को रिलीज होगी। बीच में खबरें आई थीं कि यह फिल्म 28 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन आयुष्मान खुराना की ही फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' 21 फरवरी को रिलीज होनी है। ऐसे में दोनों फिल्मों की रिलीज के बीच सिर्फ एक सप्ताह का ही अंतर था। ऐसे में बॉलीवुड के गलियारों में खबरें आ रही थीं कि दोनों फिल्मों की कमाई पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए रिलीज तारीख में फेरबदल किया जा रहा है।

चिंताजनक

निम्न आय वाले देश मोटापे और कुपोषण की दोहरी मार से जूझ रहे हैं, शोधकर्ताओं ने बताया है कि खाद्य प्रणाली में आए बदलाव की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिली है

मोटापे और कुपोषण का सामना कर रहे गरीब देश

प्रतीकात्मक

- द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन में दी गई जानकारी
- अध्ययन में 1990 और 2010 में हुए सर्वेक्षणों के डाटा का इस्तेमाल किया गया
- जंक फूड उपलब्ध होने से सुरक्षित, स्वस्थ और सस्ते आहारों का सेवन हुआ कम

वाशिंगटन, प्रेट्र : दुनिया के करीब एक तिहाई निम्न आय वाले देशों को मोटापे और कुपोषण की दोहरी मार से जूझना पड़ रहा है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात की जानकारी दी गई है।

अध्ययन करने वाले अमेरिका की नार्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बैरी एम पॉपकिन ने बताया कि खाद्य प्रणाली में हुए बदलावों की वजह से इसके मामले बढ़ गए हैं। निम्न आय वाले देशों में पिछले कुछ वर्षों में सुपरमार्केट का बढ़ना, ताजा खाद्य बाजारों का गायब होना और खाद्य शृंखला को कंपनियों द्वारा नियंत्रित किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। उन्होंने बताया कि हमारे शोध से पता चलता है कि सभी कम आय वाले देशों के वयस्कों में कम से कम 20 प्रतिशत अधिक वजन और मोटापे का स्तर पाया जाता है। इसके साथ ही इन देशों में कुपोषण का स्तर भी बहुत ज्यादा पाया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी 'रेडी टू ईट फूड', जंक फूड और अस्वास्थ्यकारी भोजन उपलब्ध होने से सुरक्षित, स्वस्थ और सस्ते आहारों का सेवन कम हो गया है। पॉपकिन और उनके सह लेखकों ने 1990 और 2010 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुए सर्वेक्षणों के डाटा का इस्तेमाल किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किन देशों को कुपोषण का दोहरा बोझ झेलना पड़ा। परिणामों से पता चलता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक तिहाई से अधिक में कुपोषण और मोटापे के मामले अधिक थे। 1990 में 123 देशों के परीक्षण में 45 तो 2010 में 126 देशों में से 48 देश ऐसे थे जिनमें मोटापा और कुपोषण के मामलों का बहुतायत था। इन देशों की आबादी में 30 फीसद से ज्यादा लोगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। 20 फीसद से ज्यादा महिलाओं में पतलापन था और 20 फीसद से ही ज्यादा लोग मोटापे से ग्रसित थे।

शोधकर्ताओं के मुताबिक यह समस्या उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आम है। एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर लगभग 2.3 अरब बच्चे और वयस्क अधिक वजन वाले हैं और 15 करोड़ बच्चों का सही तरह से विकास नहीं हो पाया है।